RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 12 अंक 47
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 21 दिसंबर, 2023
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

दलाई लामा ने अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया
राष्ट्रीय-10

मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा: शाह

लोकसभा ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए तीन प्रमुख विधेयक पारित किए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र ने बुधवार को लोकसभा में मॉब लिंचिंग का अपराध करने वालों के लिए मौत की सजा के प्रावधान वाला एक नया आपराधिक विधेयक पारित किया। मॉब लिंचिंग के लिए सजा का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली कांग्रेस सरकारों से सवाल किया कि उन्होंने 58 साल तक देश पर शासन किया, फिर वे मॉब लिंचिंग को कानून में शामिल क्यों नहीं कर सके।

गृह मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा के दौरान विपक्ष सहित सदस्यों को अपने जवाब में कहा कि आपने हमें (भाजपा) को गाली देने के लिए मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप इसके बारे में भूल गए। लोकसभा ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए तीन प्रमुख विधेयक पारित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि सजा देने के बजाय त्वरित न्याय देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिल पहली बार अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए थे। गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा कई सिफारिशें करने के बाद सरकार ने विधेयकों को वापस लेने का फैसला किया और पिछले सप्ताह उनका पुन:प्रारूपित संस्करण पेश किया। भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 की सीआरपीसी की जगह लेगी और भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। 'एक बार मैं चिदंबरम का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि यह गृह मंत्री के लिए एक परीक्षा है कि अगर वह एक नया कानून लाएंगे तो मॉब लिंचिंग के (मुद्दे पर) क्या करेंगे?

इस पर निचले सदन में जवाब देते हुए कहा कि चिदंबरम न तो भाजपा को समझ पाए हैं और न ही उसके सिद्धांतों को। शाह ने कहा कि हमारी पार्टी की एक ही विचारधारा है और वह है देश का विकास। विपक्ष पर अपना हमला जारी रखते हुए, अमित शाह ने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो कहते हैं कि भाजपा को समझ नहीं है। गृह मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने उनसे कहा कि अगर किसी का दिल भारतीय है तो आप कानूनों को समझेंगे। अगर यह इतालवी है, तो आप नहीं समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान तब आया है जब पिछले सप्ताह संसद उल्लंघन की घटना पर मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पिछले चार दिनों की बैठक के दौरान निचले सदन के 97 सहित 143 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। बहस का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि तीन बिलों में आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा भी है और 'राज्य के खिलाफ अपराध' नामक एक नया खंड पेश करते हुए राजद्रोह को अपराध के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

बहस के दौरान कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे। जबकि कई विपक्षी दल आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने की मांग करने वाले विधेयकों के आलोचक रहे हैं, केवल मुट्ठी भर गैर-एनडीए सदस्य सदन में मौजूद थे, जिनमें हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, बीजू जनता दल और बहुजन समाज के सांसद शामिल हैं। शाह ने कहा कि मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि कैसे कुछ लोग 'मानवाधिकार' के नाम पर आतंकवादियों की रक्षा करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। याद रखें, यह न तो अंग्रेजों का शासन है और न ही कांग्रेस का। यह मोदी का शासन है। आतंकवादियों को बचाने के किसी भी तर्क पर विचार (शेष पेज 9)

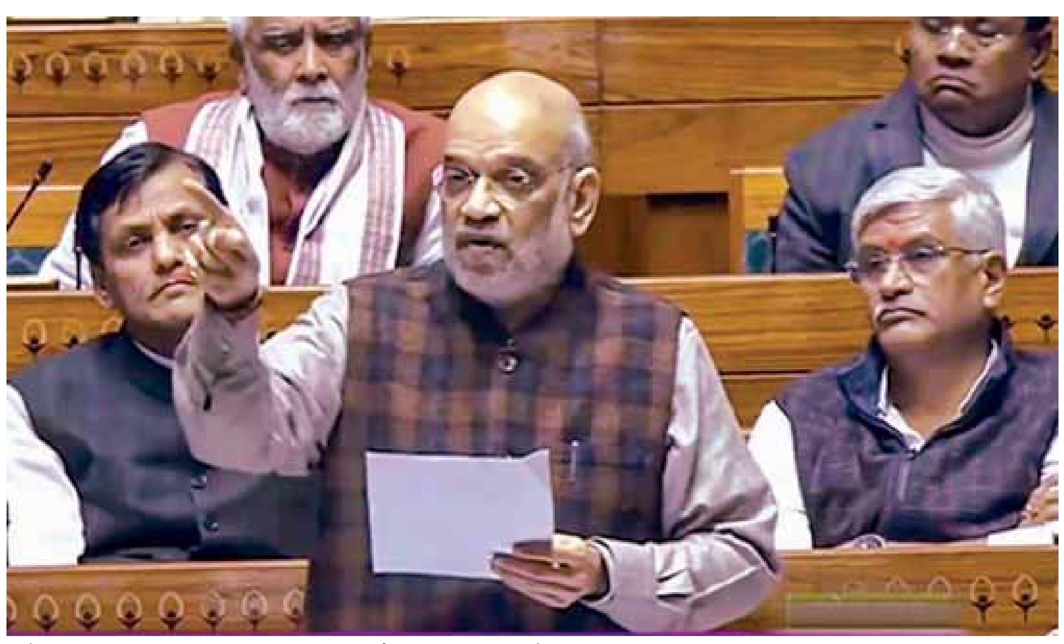

नई दिल्ली में बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा में भाग लेते गृहमंत्री अमित शाह।

कुछ घटनाओं को भारत-अमेरिका संबंधों से जोड़ना ठीक नहीं: पीएम

- सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की नाकाम साजिश को लेकर पीएम मोदी ने पहली बार की टिप्पणी
- कहा-भारत की प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है अगर कोई जानकारी देता है तो वह इस पर गौर करेगा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है और अगर कोई जानकारी देता है तो वह इस पर गौर करेगा। सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की नाकाम साजिश का तार भारत से जोड़ने के अमेरिका के आरोपों के संबंध में यह पीएम मोदी का यह पहला बयान माना जा रहा है।

द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में यह दावा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मजबूत द्विदलीय समर्थन है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ घटनाओं को राजनयिक संबंधों से जोड़ना उचित नहीं है। ब्रिटिश दैनिक को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि अगर कोई हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने की पृष्ठभूमि में आईं कि निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम कर रहा था, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता (शेष पेज 9)

नकल उतारने की मुर्मू व पीएम ने की निंदा, दो और सांसद निलंबित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सांसदों के निलंबन के खिलाफ मंगलवार को संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के बाद बाद बुधवार को एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने इसकी कड़ी निंदा की।

वहीं उपराष्ट्रपति की नकल उतारने पर वकील अभिषेक गौतम ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि वे संसद या उपराष्ट्रपति पद का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भारी बवाल के बाद टीएमसी सांसद ने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। दूसरी ओर, जाट महासंघ के कार्यकर्ताओं ने धनखड़ का उपहास किये जाने के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय के पास विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में टीएमसी सांसद का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा इस मामले को उठाकर 140 से अधिक सांसदों के अभूतपूर्व निलंबन से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है, सरकार का यह हताशा भरा प्रयास है।

उपराष्ट्रपति की 'मिमिक्री' घटना पर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि जोकर (क्लॉउन) के रूप में काम कर रहे और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भाजपा सांसद रवि किशन के स्टूडियो में कैमरामैन की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर कहा कि संसद परिसर में जिस तरह से उपराष्ट्रपति को अपमानित करने की घटना से व्यथित हूं, यह निराशाजनक है। मुर्मू ने कहा, निर्वाचित प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यही संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रपति के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्यसभा सभापति ने मुर्मू को बुनियादी शिष्टाचार हमेशा बना रखने के लिए उनके विनम्र शब्दों और समय पर याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। धनखड़ ने मुर्मू को जवाब दिया, मैं अपनी आखिरी सांस तक संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। उपराष्ट्रपति सचिवालय से एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति को फोन कर मंगलवार को पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों की घृणित नाटकीयता पर बहुत दुख व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे (उपराष्ट्रपति) से कहा कि वह (मोदी) पिछले बीस वर्षों से इस तरह के अपमान सह रहे हैं, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का अपमान वह भी संसद परिसर में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पोस्ट में धनखड़ के हवाले से कहा गया, उन्होंने सदन में भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। राज्यसभा में धनखड़ ने कहा कि उनकी नकल करने के कृत्य और इसकी वीडियोग्राफी से उपराष्ट्रपति पद के सम्मान, किसानों और उनके अपने समुदाय का अपमान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ की मिमिक्री को किसान और जाट (उनकी जाति) के रूप में उनकी पृष्ठभूमि का (शेष पेज 9)

प्रवर्तन निदेशालय के समन के बीच केजरीवाल विपश्यना के लिए रवाना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली शराब घाटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल को एजेंसी की जांच में शामिल होने के लिए 21 दिसंबर को ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए समन भेजा था। लेकिन इससे एक दिन पहले ही वह 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान के लिए राजधानी से बाहर चले गए हैं। इससे पहले आप प्रमुख को जांच एजेंसी ने 2 नवंबर को बुलाया था लेकिन वह ईडी के सामने पेश होने के बजाय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का विकल्प चुना था। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सोमवार को नया समनजारी किया था। अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल को विपश्यना ध्यान सत्र के लिए मंगलवार को रवाना होना था, लेकिन गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित ध्यान सत्र के (शेष पेज 9)

बंगाल के मंत्री के ठिकाने पर ईडी का छापा, लालू और तेजस्वी तलब

पायनियर समाचार सेवा। कोलकाता/नई दिल्ली

लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का फाइल चित्र

जेल में बंद पश्चिम बंगाल की वन मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक की मुश्किलें उनके कार्यालय में ईडी को मिले दस्तावेजों के बाद बढ़ गई है। एजेंसी के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ज्योति प्रिया के कार्यालय से 10 करोड़ रुपये के बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट प्रमाणपत्र, कई संपत्ति दस्तावेज और कम से कम 600 सादा स्टांप पेपर बरामद किए हैं।

वहीं एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन धनशोधन मामले की जांच के क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए तलब किया है। तृणमूल मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2021 में वन विभाग में स्थानांतरित किए जाने से पहले लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक बंगाल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थीं। अरण्य भवन में मल्लिक के वन मंत्रालय कार्यालय के अंदर छापेमारी करने वाले ईडी अधिकारियों ने कहा कि एफडी प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज उनके निजी बाड़े के अंदर विभिन्न स्थानों पर छिपे हुए थे।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बरामद दस्तावेजों का वन विभाग के अधिकारियों से कोई संबंध था या नहीं, उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और कहा कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। ज्ञात रहे किज्योति प्रिया सीएम ममता बनर्जी की करीबी विश्वासपात्र, तृणमूल कांग्रेस के उत्तर 24 परगना के पूर्व संगठनात्मक प्रभारी हैं। वहीं संघीय एजेंसी ईडी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (34) को 22 दिसंबर को दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है, वहीं लालू प्रसाद को अगले सप्ताह 27 दिसंबर को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा गया है। इस मामले में ईडी एक बार 11 अप्रैल को तेजस्वी यादव से करीब आठ घंटे तक पूछताछ कर चुकी है लेकिन यह पहली बार है जब उसने लालू को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। यह समन लालू प्रसाद परिवार के एक कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल से पूछताछ के (शेष पेज 9)

सात्विक और चिराग को खेलरत्न, शमी और शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार

भाषा। नई दिल्ली

भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा जबकि वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पैरा एशियाई खेलों की चैम्पियन तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में नौ जनवरी को आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी।

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने जिन नामों की अनुशंसा की थी उसके आधार पर भारत की नंबर एक बैडमिंटन पुरुष युगल टीम चिराग और सात्विक को सर्वोच्च खेल सम्मान खेलरत्न देने का फैसला किया गया। इसके अलावा 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले तैंतीस वर्षीय तेज गेंदबाज शमी शामिल हैं। भारत इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शमी का नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष आग्रह किया था। इससे पहले उनका नाम देश के दूसरे सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं था।

शमी ने वनडे विश्व कप में केवल सात मैच में सर्वाधिक 24 विकेट हासिल किए थे। पहले चार मैच में बाहर रहने के बाद शमी को जब मौका मिला तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। शमी के अलावा 25 अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इनमें भुजाहीन तीरंदाज शीतल देवी, पुरुष हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, गोल्फर दीक्षा डागर, निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पहलवान अंतिम पंघाल, एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता वुशू खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी और टेबल टेनिस खिलाड़ी अयहिका मुखर्जी शामिल हैं।

प्रशिक्षकों को मिलने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए गणेश प्रभाकरन (मल्लखंभ), महावीर सैनी (पैरा एथलेटिक्स), ललित कुमार (कुश्ती), आरबी रमेश (शतरंज) और शिवेंद्र सिंह (हॉकी) का चयन किया गया है। ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार के लिए कविता सेल्वराज (कबड्डी), मंजूषा कंवर (बैडमिंटन) और विनीत कुमार शर्मा (हॉकी) को चुना गया है। खेल मंत्रालय ने इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार का फैसला करने के लिए 12 सदस्ईय समिति गठित की थी। इनमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएम खानविलकर के अलावा हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लै, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी कमलेश मेहता, पूर्व मुक्केबाज अखिल कुमार, महिला निशानेबाज और वर्तमान राष्ट्रीय कोच शुमा शिरूर, पूर्व क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे और पावरलिफ्टर फरमान पाशा भी समिति में शामिल थे।

विभिन्न पुरस्कारों के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार:- सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी (बैडमिंटन)।

अर्जुन पुरस्कार:- मोहम्मद शमी (क्रिकेट), अजय रेड्डी (दृष्टिबाधित क्रिकेट), ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी (तीरंदाजी), शीतल देवी (पैरा तीरंदाजी), पारुल चौधरी और मुरली श्रीशंकर (एथलेटिक्स), मोहम्मद हुसामुद्दीन (मुक्केबाजी), आर वैशाली (शतरंज), दिव्यकृति सिंह और अनूष अग्रवाल (घुड़सवारी), दीक्षा डागर (गोल्फ), कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू (हॉकी), पिंकी (लॉन बॉल), ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह (निशानेबाजी), अंतिम पंघाल और सुनील कुमार (कुश्ती), अयहिका मुखर्जी (टेबल टेनिस), नाओरेम रोशिबिना देवी (वुशू), पवन कुमार और रितु नेगी (कबड्डी), नसरीन (खोखो), हरिंदर पाल सिंह संधू (स्क्वाश), प्राची यादव (पैरा केनोइंग)।

ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार:- कविता सेल्वराज (कबड्डी), मंजूषा कंवर (बैडमिंटन) विनीत कुमार शर्मा (हॉकी)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार:- गणेश प्रभाकरन (मल्लखंब), महावीर सैनी (पैरा एथलेटिक्स), ललित कुमार (कुश्ती), आरबी रमेश (शतरंज), शिवेंद्र सिंह (हॉकी)

द्रोणाचार्य पुरस्कार (आजीवन वर्ग):- जसकीरज सिंह ग्रेवाल (गोल्फ के लिए), भास्करन ई (कबड्डी के लिए), जयंत कुमार पुशीलाल (टेबल टेनिस के लिए)।

कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी

हर पॉजिटिव मरीज की होगी जिनोम सिक्वेंसिंग, गाजियाबाद में मास्क पहनने की सलाह

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

केरल में कोरोना का नया वेरिएंट जेएन-1 पाए जाने के बाद दिल्ली-एनसीआर में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।

निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में जो कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, उनके सैंपलों की जिनोम सिक्वेंसिंग कराई जाए।

गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवतोष शंखधर ने कहा, गाजियाबाद देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। इसलिए ये अतिसंवेदनशील जनपद है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट जेएन-1 से रोकथाम और बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना जरूरी हो गया है। सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा, अगर आपके आसपास कोविड पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम के नंबर. 9910426374, 8826797248 पर दें।

स्वास्थ्य विभाग की चिंता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा से हर रोज कई लाख लोग दिल्ली जाते हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग फ्लाइट के जरिये विदेश जाते हैं और वहां से आते भी हैं। केरल के लिए भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से कई उड़ानें हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से भी अलग-अलग राज्यों के लिए उड़ानें संचालित होती हैं। कुल मिलाकर ह्यूमन ट्रैफिक बना रहता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद और नोएडा में सतर्कता बरत रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से कोरोना बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। उधर, इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया ने अहम बैठक बुलाई है।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन

- बाजारों, मंडियों व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क, हैंड सैनेटाइजर का प्रयोग करें।
- वृद्धों एवं बच्चों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ले जाने से बचा जाए।
- किडनी, लीवर, हृदय, डायबिटीज जैसे रोगियों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए।
- सर्दी, जुकाम या फ्लू के लक्षण होने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचकर कोविड वायरस जांच कराएं।
- शादी समारोहों या अन्य आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।

ग्रेटर नोएडा में दूसरे दिन भी चली सीलिंग की कार्रवाई

नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यहां के आवासीय सेक्टरों में मकानों के अंदर चल रहे होटलों, रेस्टोरेंट और पीजी के खिलाफ आज दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की है।

ग्रेटर नोएडा के अंसल गोल्फ लिंक-1 सोसाइटी में अवैध रूप से चल रहे होटल, रेस्टोरेंट और पीजी के खिलाफबुधवार को दूसरे दिन भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का व्यापक अभियान जारी रहा। ग्रेटर नोएडा के अंसल गोल्फ लिंक-1 सोसाइटी में अवैध रूप से चल रहे होटल, रेस्टोरेंट और पीजी के खिलाफ मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने व्यापक अभियान छेड़ा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों ने अभियान के तहत अवैध गतिविधियां चलाने के आरोप में दूसरे दिन भी सीलिंग की कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अभियान के तहत मंगलवार को 25 होटलों को सील किया था। बुधवार सुबह भी 8 व्यवसायिक प्रतिष्ठान सील किए गए थे।

संक्षिप्त समाचार

प्राथमिक विद्यालय सेक्टर-15 नया बांस में अग्नि से बचाव के लिए फायर मॉक ड्रिल कराई गई। इस दौरान अध्यापक व विद्यार्थियों को अग्निशमन उपकरणों का संचालन करना भी सिखाया गया।

टोल प्लाजा पर 46 गांव के किसान करेंगे महापंचायत

नोएडा। एनएच-91 के लुहारली टोल प्लाजा पर 25 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 46 गांव के किसान और प्रधान इस महा पंचायत में शामिल होंगे। टोल मैनेजमेंट के खिलाफयह सभी लोग इकट्ठा होकर हल्ला बोलेंगे। किसान संघ ने एसीपी दादरी को ज्ञापन सौंपा। दादरी थाना क्षेत्र के एनएच 91 टोल प्लाजा के मैनेजमेंट के खिलाफ46 गांव के किसान हल्ला बोलेंगे। इसको लेकर किसान संघ के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन एसीपी दादरी को सौंपा। बिल्लू अधाना ने बताया कि लुहारली टोल मैनेजमेंट की तानाशाही को लेकर 25 दिसंबर को टोल पर महापंचायत की जाएगी। पिछले काफी समय से क्षेत्र के किसान और क्षेत्रवासी टोल मैनेजमेंट से परेशान होकर अब सब्र का बांध टूट चुका है। किसानों ने बताया कि बुलंदशहर से लेकर गाजियाबाद तक पड़ने वाले गांव के सर्विस रोड नहीं बनाए गए। रात के समय स्ट्रीट लाइट नहीं जलती सिर्फ दिखावे के लिए स्ट्रीट लाइट होती है। रोड पर भारी वाहन दौड़ते हैं एकहीं भी कोई अंडरपास की व्यवस्था नहीं है आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

श्री श्याम जन्मोत्सव व संकीर्तन 23 को

नोएडा। 23 दिसंबर को श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का श्री श्याम जन्मोत्सव तथा संकीर्तन का आयोजन सेक्टर.19 के बारातघर में होगा। यह जानकारी खाटू वाले श्याम के प्रेमी संजय गोयल ने दी है। श्री गोयल ने बताया कि यह कार्यक्रम सायं 5 बजे से शुरू होगा तथा देर रात प्रभु की इच्छा तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भजन गायक वृंदावन धाम की दीदी मीनू शर्मा, पानीपत की आरती शर्मा, दिल्ली के सुनील जैन तथा गाजियाबाद के केशव निखिल श्री खाटू श्याम का गुणगान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम सेवा परिवार द्वारा किया जा रहा है।

भाजयुमो ने निकाली बाइक रैली

नोएडा। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा नोएडा महानगर में जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में सैनिक विहार मंडल में बाइक रैली का आयोजन किया। बाइक रैली का उद्देश्य विकसित भारत यात्रा को जन.जन तक पहुंचाना तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन.जन तक पहुंचाना है। इस दौरान इस बात की भी जानकारी सुनिश्चित करनी थी कि योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी मिले। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नोएडा महानगर के नेता व कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी लंबी बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उसे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने उन्हें इन योजनाओं की जानकारी देना था। क्यों कि योजनाओं की जानकारी होने पर ही इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है।

फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मांगी रंगदारी

गाजियाबाद। मुरादनगर की नगर की एक कॉलोनी निवासी युवक को फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। नगर की एक कॉलोनी निवासी एक युवक ने बताया कि युवती बनकर पहले मेरे से दोस्ती की। इसके बाद आरोपियों ने मेरी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। इसके बाद उन्होंने मेरे फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए ना देने पर अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि वह कई बार फेसबुक पर बात करने वाली युवती की पैसे देकर मदद भी कर चुका है। पीड़ित ने मुरादनगर थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़ित ने इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मुरादनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है।

किराये या लीज पर भूखंड देने वालों की होगी पहचान

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● सिर्फ निवेश करने वाले को मिलेगा आवंटन

नोएडा में अक्सर देखा गया कि यहां आईटी, आईटीईएस, संस्थागत, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन उन उद्यमियों को नहीं होता जो यहां स्वयं निवेश करना चाहते है। रोजगार देना चाहते।

यहां कंसेशनल रेट पर उन लोगों को औद्योगिक, संस्थागत, आईटी और आईटीईएस भूखंड आवंटित हो जाते है जो उस भूखंड पर निर्माण कर उसे रेंट पर देते है। या भूखंड ही किसी अन्य को लीज पर दे देते है। ऐसी कई शिकायत नोएडा के औद्योगिक संगठन की ओर से लगातार की जाती रही है। इससे जहां एक ओर सही उद्यमी और निवेशक को भूखंड नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेंट पर होने की वजह से भूखंड की उपयोगिता कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। इस संबंध में अवस्थापन और औद्योगिक विकास आयुक्त ने एक आदेश तीनों प्राधिकरण को दिए है। इसके लिए उप्र औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा-12 उप्र अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा-41 के अंतर्गत आदेश दिया कि अब इन भूखंडों के आवंटन के समय प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि आवेदक प्राधिकरण के बनाए गए पैरामीटर पर खरा है या नहीं।

प्राधिकरण आवेदक का बैकग्राउंड चेक कर सकता है। प्राधिकरण साक्षात्कार के जरिए ये सुनिश्चित करेगा कि जिसका इंटरव्यू हो रहा है वहीं, यहां निवेश करेगा और निर्माण कर कंपनी का संचालन करेगा।

इसके अलावा यदि प्राधिकरण में कार्यरत किसी भी कर्मी का रिश्तेदार को भूखंड का आवंटन किया जा रहा है तो इससे पहले उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी।

बैंक मैनेजर ने ग्राहक के खाते से उड़ाए 28 करोड़

पायनियर सामचार सेवा। नोएडा

● पत्नी और मां के खातों में धन हस्तांरित करने के बाद परिवार समेत आरोपी फरार

नोएडा शहर में स्थित एक बैंक में अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। बैंक के सहायक मैनेजर ने एक खाताधारक के खाते में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दे दिया।

सहायक मैनेजर ने धोखाधड़ी करते हुए एक खाते से 28 करोड रुपए अपनी पत्नी व मां के खातों में ट्रांसफर कर दिए। अब आरोपी मैनेजर अपने परिवार सहित फरार हो गया है।

नोएडा के सेक्टर-22 स्थित साउथ इंडियन बैंक के डीजीएम रीजनल मैनेजर रैनजीत आर नायक ने अपने ही बैंक के सहायक प्रबंधक राहुल शर्मा उसकी पत्नी भूमिका शर्मा और मां सीमा शर्मा सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि सहायक मैनेजर ने एक बैंक खाते में सेंध लगाकर 28.7 करोड़ रुपए हड़प लिए। नोएडा के थाना सेक्टर.24 में दर्ज कराई रिपोर्ट में डीजीएम रीजनल ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से सेक्टर.22 स्थित शाखा में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा यहां जांच कराई गई। जांच के दौरान पता चला कि सेक्टर.48 स्थित एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च फाउंडेशन नामक कंपनी के खाते से सहायक बैंक प्रबंधक राहुल शर्मा ने 28.7 करोड़ रुपए अपनी पत्नी भूमिका शर्मा सहित अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिए हैं। इस संबंध में खाता धारक ने ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज कराते हुए बिना अनुमति के रुपए ट्रांसफ र करने का गंभीर आरोप लगाया। जांच में यह आरोप सही पाए गए। इसके बाद आरोपी सहायक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। नोएडा पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

नोएडा की पुलिस उन खातों की जांच पड़ताल कर रही है जिन खातों में बैंक से रकम ट्रांसफर हुई है वही बताया जाता है कि सहायक बैंक मैनेजर अपने परिवार सहित फरार हो गया है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। नोएडा में सहायक बैंक मैनेजर द्वारा 28 करोड़ रुपए का घोटाले का यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

वाहन नियम उल्लघंन करने वालों के काटे चालान

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में दिनांक 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यातायात पुलिस व नागरिक पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 09 स्थानों पर संयुक्त टीम बनाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध चैकिंग की गयी। यातायात पुलिस व नागरिक पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 529 वाहन चालकों को चेक किया गया। जिसमें 9 वाहन चालक नशे की स्थिति में पाये गए। इन वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने पर उनके वाहनों को सीज/ ई-चालान की कार्रवाई की गई है। दिनांक 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रचलित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान के दौरान यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा 19 दिसंबर को दादरी, तिलपता, कुलेशरा, परीचौक, सेक्टर-37, सेक्टर 59, माडल टाउन आदि स्थानों पर 845 वाहन चालकों व आमजन को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया।

सलारपुर गांव में किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान

नोएडा। थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सलारपुर गांव में एक 14 वर्षीय किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना के समय किशोरी घर में अकेली थी। मूल रूप से गोंडा निवासी अंग्रेज सिंह अपने परिवार सहित सलारपुर गांव में किराए पर रह रहे हैं। अंग्रेज सिंह एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। मंगलवार को वह ड्यूटी पर चले गए। घर पर उनकी पत्नी तथा 14 वर्ष से बेटी अकेली थी। शाम के समय उनकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो उन्हें किशोरी फंदे पर लटकी हुई मिली।

भाजपा नेता सिंगा पंडित पर हमला करने वाले हत्थे चढ़े

● वारदात के पीछे गैंगस्टर रणदीप भाटी गैंग का नाम सामने आया

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

रणदीप भाटी गिरोह के दो शार्प शूटर को थाना बीटा-2 पुलिस ने गिरफ्तार किया।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 11 माह पूर्व भाजपा नेता संचित उर्फ सिंगा पंडित पर जानलेवा हमला करने वाले गैंगस्टर रणदीप भाटी गिरोह के दो शार्प शूटर को थाना बीटा-2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए शार्प शूटरों ने रणदीप भाटी के कहने पर भाजपा नेता सिंगा पंडित पर जानलेवा हमला किया था।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफभी जुटी हुई थी। इस मामले में उस समय जमकर राजनीति हुई थी। ग्रेटर नोएडा जोन के एडीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि थाना बीटा-2 पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी गिरोह के दो सदस्य क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अल्फा I गोल चक्कर के पास से शिवम पुत्र राज व अजय कुमार त्रिपाठी पुत्र राघव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास से एक पिस्टल तमंचा व कारतूस बरामद हुए। एडीसीपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी गैंगस्टर रणदीप भाटी गैंग के शार्प शूटर हैं। रणदीप भाटी के कहने पर शिवम व अजय कुमार ने अपने साथियों साथ मिलकरआईकॉन अपार्टमेंट तिराहे के पास लडपुरा गांव निवासी संचित उर्फ सिंगा पंडित को घेर लिया था।

लापरवाही पर ठेकेदार पर लगाया जुर्माना

● एसीईओ ने सेक्टर-2 का किया निरीक्षण, खामियां मिलने पर की कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने सेक्टर-2 का निरीक्षण किया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने सेक्टर 2 का निरीक्षण किया। सेक्टर 2 में मौके पर मेंटेनेंस के कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित फर्म पारस कंस्ट्रक्शन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, सड़कों पर मलबा डालने वाले 10 आवंटियों पर भी 40 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया गया है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर 2 और 3 के निवासी समस्याओं को लेकर प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से मिले थे। सीईओ के निर्देश पर मंगलवार को एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने सेक्टर 2 का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान सेक्टर 2 में मेंटेनेंस के कार्यों में लापरवाही दिखी। नालियां और पटरी ड्रेसिंग क्षतिग्रस्त मिलीं। मेंटेनेंस से जुड़े अन्य कार्यों में भी लापरवाही दिखी, जिसके चलते एसीईओ ने संबंधित फर्म पारस कंस्ट्रक्शन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। वर्क सर्किल 3 की तरफसे मंगलवार शाम को ही इस आशय की नोटिस जारी कर दी गई है। एसीईओ के निरीक्षण के दौरान सेक्टर 2 में कई जगह सड़कों पर मलबे का ढेर दिखा। घरों के निर्माण से निकलने वाले मलबे को आवंटियों ने सड़कों पर फेंक दिया है। एसीईओ ने इन आवंटियों को चिन्हित कर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। वर्क सर्कल तीन के इंजीनियरों ने 10 आवंटियों को चिन्हित कर 40 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगा दिया है। प्राधिकरण की तरफ से चेतावनी दी गई है, कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर मलबे का ढेर लगाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली पीठ 9 न्यायालय -।। के समक्ष
कम्पनी आवेदन सीए (सीएए) सं. 53/एनडी/2022
में
कम्पनी याचिका सं. सीपी (सीएए) 75/एनडी/2023
कम्पनी अधिनियम, 2013
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियमावली, 2016 के तहत याचिका के विषय में
तथा
के विषय में :
मैसर्स ऐक्सिन ओवरसीज लिमिटेड ....अंतरणकर्ता/याचिकादाता कम्पनी 1
तथा
मैसर्स सरला ओवरसीज लिमिटेड ....अंतरणकर्ता/याचिकादाता कम्पनी 2
का
मैसर्स मेगा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
...........अंतरिती/याचिकादाता कम्पनी के साथ विलय की स्कीम।
याचिका की सुनवाई की सूचना
मैसर्स ऐक्सिन ओवरसीज लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी 1), मैसर्स सरला ओवरसीज लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी 2) का मैसर्स मेगा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के साथ समामेलन की स्कीम के अनुमोदन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक याचिका उक्त कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से 07 नवम्बर, 2023 को प्रस्तुत की गई थी और माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ 2 के समक्ष उक्त याचिका की सुनवाई 18 जनवरी, 2024 को की जानी नियत है।
कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका/आवेदन/विचारार्थ विषय के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, वह उसकी सूचना, जो स्वयं उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा उसके नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, माननीय न्यायाधिकरण तथा/अथवा याचिकादाता के अधिवक्ता इस प्रकार भेज सकता है, कि याचिकादाता के अधिवक्ता को याचिका/आवेदन/विचारार्थ विषय की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि वह याचिका/आवेदन/विचारार्थ विषय का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करना होगा।
याचिका/आवेदन/विचारार्थ विषय की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।
हस्ता./
ईश्वर सीएच मोहापात्रा
याचिकादाता हेतु अधिवक्ता
7/1, जीएफ, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली 110008
तिथि : 20-12-2023

शुद्धिपत्र
ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तृतीय तल,प्लॉट नंबर 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग,दिल्ली-110005
ऋण खाता सं. 002105023126, 002155000039 एवं 002155000045 कर्जदार का नाम टेक्नोक्रेट्स टूलिंग प्राइवेट लिमिटेड, उमेश कुमार सिंह-निदेशक, प्रवीण राव-निदेशक, एसपीएस टेक्नोलॉजी, उमेश कुमार सिंह, रीना सिंह के संबंध में सरफासी ऐक्ट के तहत मांग सूचना प्रकाशन मांग सूचना दिनांकित 1 दिसम्बर, 2022 तथा प्रकाशित दिनांकित 24 फरवरी, 2023 पायनियर (हिन्दी) एवं पायनियर (अंग्रेजी) क्रमानुसार में और सांकेतिक कब्जा सूचना दिनांकित 04 मई, 2023 इसका प्रकाशन दिनांक 09 मई, 2023 को पायनियर (हिन्दी) एवं पायनियर (अंग्रेजी) में दिनांक 10 मई, 2023 को इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और प्रातःकाल (हिन्दी) में एवं दिनांक 10 मई, 2023 को ओडिशा टुडे (अंग्रेजी) और उत्कल मेल (ओडीआई) में और भौतिक कब्जा सूचना, पूर्व-बिक्री सूचना, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी लिस्ट एवं पंचनामा दिनांकित 30 नवम्बर, 2023 एवं कर्जदार एवं पुलिस को पश्च-कब्जा सूचना तथा कर्जदार को खाली करने हेतु सूचना दिनांकित 01 दिसम्बर, 2023 का प्रकाशन दिनांकित 06 दिसम्बर, 2023 पायनियर (हिन्दी) एवं पायनियर (अंग्रेजी) में 06 दिसम्बर, 2023,को इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और प्रातःकाल (हिन्दी) में एवं दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 को ओडिशा टुडे (अंग्रेजी) और उत्कल मेल (ओडीआई) में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। सम्पूर्ण सरफासी कार्यवाही में सम्पत्ति पता फ्लैट नंबर एनजीएच 051, 5वां तल, टावर एच न्यू टाउन हाइट्स सेक्टर 90 गुरूग्राम एवं मांग सूचना प्रकाशन में एनपीए तिथि 15 अगस्त, 2401 क्रमानुसार वर्णित की गई है। हम यह वर्णित करने के इच्छुक हैं कि असावधानी के कारण और बिना किसी आशय के 13.2 एवं सांकेतिक सूचना में कर्जदारों के पता में एक टंकण त्रुटि हुई है तथा फ्लैट नंबर एनजीएच 051 पार्किंग स्पेस नंबर पीओएच-025 सहित, 5वां तल, टावर-एच न्यू टाउन हाइट्स सेक्टर 90 राजस्व सम्पदा ग्राम हयातपुर, तहसील और जिला गुरूग्राम एवं एनपीए तिथि 16 सितम्बर, 2022 के स्थान पर फ्लैट नंबर एनजीएच 051, 5वां तल, टावर एच न्यू टाउन हाइट्स सेक्टर 90 गुरूग्राम एवं मांग सूचना प्रकाशन में एनपीए तिथि 15 अगस्त, 2401 क्रमानुसार वर्णित की गई है। अतएव हम आपसे उसको फ्लैट नंबर एनजीएच 051 पार्किंग स्पेस नंबर पीओएच-025 सहित, 5वां तल, टावर-एच न्यू टाउन हाइट्स सेक्टर 90 राजस्व सम्पदा ग्राम हयातपुर, तहसील और जिला- गुरूग्राम एवं एनपीए तिथि 16 सितम्बर, 2022 के रूप में पढ़ने का अनुरोध करते हैं।
तिथि : 21 दिसम्बर, 2023
स्थान : गुरूग्राम
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व. श्री किशोरी लाल, निवासी 238, आरपीएस एमआईजी फ्लैट्स, शेख सराय फेज-1, नई दिल्ली-110017 ने उक्त फ्लैट नंबर 238, आरपीएस एमआईजी फ्लैट्स, शेख सराय फेज 1, नई दिल्ली 110017 सेल डीड दिनांकित 24 02 2005, पंजीकरण सं. 2798, अतिरिक्त बही नंबर 1, जिल्द नंबर 4755 के माध्यम से क्रय किया था, अब हमारा मुवक्किल श्री ओम प्रकाश उक्त सम्पत्ति के संबंध मे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पक्ष में बंधक के सृजन हेतु कार्यवाही कर रहा है।
आगे, यदि कोई व्यक्ति, निकाय, व्यष्टि, संस्था, जो उक्त सम्पत्ति अथवा उसके भाग के संबंध में अथवा उसके विरुद्ध अथवा उसकी सीमा के संबंध में बिक्री, विनिमय, पट्टा, ग्रहाणाधिकार, बंधक, प्रभार, ऋणभार, उपहार, न्यास, उपभोगाधिकार, अनुरक्षण, उत्तराधिकार, प्रामाणिक साक्ष्य अथवा अन्य प्रकार से किसी दावे, स्वत्वाधिकार, हित तथा/अथवा आपत्ति का धारक है अथवा उक्त सम्पत्ति के साथ संबंधित कोई स्वत्व, दस्तावेज उसकी अभिरक्षा में हैं, उसको उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को नीचे वर्णित पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 5 दिन के भीतर, उसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत के साथ देनी होगी, अन्यथा, ऐसे व्यक्ति का दावा शिथिलीकृत अथवा परित्यक्त माना जाएगा। 5 दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्रस्तुत की गई कोई भी आपत्ति उक्त सम्पत्ति अथवा हमारे मुवक्किल पर बाध्यकारी नहीं होगी और यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह इस प्रकाशन के 5 दिन के भीतर श्री अमनदीप सिंह (अधिवक्ता) कार्यालय पता : 236, आरपीएस एमआईजी फ्लैट्स, शेख सराय फेज 1, नई दिल्ली 110017, मोबाइल नंबर 9711570956, ई मेल: aman@dexterjuris.com को भेजी जानी चाहिए।
हस्ता./-
अमनदीप सिंह
अधिवक्ता

सार्वजनिक सूचना
इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रखर शुक्ला और प्रतिमा शुक्ला ने प्रतीक ग्रुप (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) "प्रतीक ग्रैंड सिटी", सिद्धार्थ विहार, NH-24, गाजियाबाद के नाम से द्वारा विकसित की जा रही परियोजना में एक आवासीय फ्लैट बुक किया था। श्री प्रखर शुक्ला की दुर्भाग्य से 28-अप्रैल-2021 को मृत्यु हो गई है और श्रीमती प्रतिमा शुक्ला पत्नी श्री प्रखर शुक्ला निवासी फ्लैट नंबर 1208, टावर सी-6, प्रतीक ग्रैंड सिटी, सिद्धार्थ विहार, एनएच-24 गाजियाबाद, ने स्वर्गीय श्री प्रखर शुक्ला के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते कंपनी से संपर्क किया है और आवेदन किया है। यदि प्रखर शुक्ला का कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी है/ हैं,तो उक्त व्यक्ति को इस नोटिस के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ कंपनी से संपर्क करना होगा। यदि कंपनी को कोई नाम प्राप्त नहीं हुआ है, तो श्रीमती प्रतिमा शुक्ला पत्नी श्री प्रखर शुक्ला निवासी फ्लैट नंबर 1208,टावर सी-6,प्रतीक ग्रैंड सिटी, सिद्धार्थ विहार, एनएच-24 , गाजियाबाद को श्री प्रखर शुक्ला के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और इसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना
ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005.
जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/ज़मानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्ज़दार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सुमित कुमार मिश्रा/ विभा देवी मिश्रा/ LBDEL00002094431	फ्लैट 0.430, चौथी मंजिल, ब्लॉक-बी, मनहर गार्डन, हरीश नगर के पास, सिकंदरा- बोदला रोड, आगरा/ दिसंबर 18, 2023	जुलाई 31, 2023 रु. 24,16,442/-	दिल्ली/ एनसीआर एवं आगरा
2.	धनंजय कुमार/ चन्द्रशेखर प्रसाद/ LBDEL00002043180	फ्लैट नंबर 301, तीसरी मंजिल (फ्लैट नंबर 01, तीसरी मंजिल, ब्लॉक ए, मनहर गार्डन) ब्लॉक ए, मनहर गार्डन, हरीश नगर सिकंदरा- बोदला रोड, सिकंदरा आगरा/ दिसंबर 18, 2023	जुलाई 19, 2023 रु. 18,83,244/-	दिल्ली/ एनसीआर एवं आगरा
3.	दीपक कुमार मिश्रा/ रेखा मेहता/ LBGHZ00005174102	अपार्टमेंट नंबर सी- 207, दूसरी मंजिल टॉवर सी, मलबेरी काउंटी, गांव मुजेरी में स्थित, सेक्टर- 70, तहसील बल्लभगढ़, हरियाणा फ़रीदाबाद/ दिसंबर 19, 2023	जून 15, 2023 रु. 18,08,469/-	दिल्ली/ एनसीआर
4.	प्रदीप/ गीता/ LBFDB00005510709	फ्लैट नंबर 803 टी-7/ टॉवर ए, ''लेक व्यू अपार्टमेंट'', सेक्टर- 48, फ़रीदाबाद/ दिसंबर 19, 2023	जुलाई 14, 2023 रु. 39,41,029/-	दिल्ली/ एनसीआर
5.	धर्मवीर/पिंकी/ LBDEL00004897559	डीडीए एलआईजी, फ्लैट नंबर 1274, तीसरी मंजिल, संस्कृति अपार्टमेंट्स, पॉकेट-जीएच-1, सेक्टर-28, रोहिणी, दिल्ली/ दिसंबर 19, 2023	अक्टूबर 26, 2022 रु. 16,90,081/-	दिल्ली/ एनसीआर एवं हिसार

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।
दिनांक : दिसंबर 21, 2023
स्थान : दिल्ली/एनसीआर
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

हादसे में मृत महिला के परिवार को मेट्रो देगा 15 लाख

डीएमआरसी बच्चों की शिक्षा की भी करेगा व्यवस्था, इंद्रलोक स्टेशन पर दुर्घटना में महिला की गई थी जान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के परिजन को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) 15 लाख रुपये का मुआवजा देगा। इसके साथ ही महिला के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाएगी।

मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं। मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मृतका के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। चूंकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के लिए डीएमआरसी कानूनी तौर-तरीकों पर गौर कर रहा है। डीएमआरसी दोनों बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित करेगा। डीएमआरसी ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी गठित की है जो सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए मामले को देखेगी।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाए। 14 दिसंबर को रीना अपने छह वर्षीय बेटे के साथ भांजे की शादी में शामिल होने मेरठ जा रही थीं। उन्होंने नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ग्रीन लाइन की मेट्रो पकड़ी थी। इंद्रलोक स्टेशन पर मेट्रो बदलकर रेड लाइन की मेट्रो सवार हुई लेकिन उनका बेटा पीछे छूट गया था। बेटे के लिए दोबारा ट्रेन से बाहर उतरने के दौरान उनकी साड़ी, जैकेट मेट्रो के दरवाजे में फंस गया। स्वजनों का कहना है कि उनके कंधे में एक भारी भरकम बैग था।

महिला के पति की पहले ही हो चुकी है मौत

महिला के पति की पहले मौत हो गई थी। वह टमाटर की रेहड़ी लगाकर अपने दो नाबालिग बच्चों का भरण पोषण कर रही थीं। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल का कहना है कि मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रविधानों के अनुसार, मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

मेट्रो ट्रैक पर गिरने से आई थीं गंभीर चोट

महिला का बैग भी दरवाजे में फंस गया था। इस बीच मेट्रो चल पड़ी। इससे वह काफी दूर तक मेट्रो के साथ घिसटती रहीं। प्लेटफॉर्म से मेट्रो ट्रेन के आगे निकलने के बाद प्लेटफार्म पर लगे गेट से टकराकर वह मेट्रो के ट्रैक पर गिर गई थीं जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी।

16 दिसंबर को उनकी सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं। महिला की 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के कानूनी तौर-तरीकों को सुलझाने में लगा हुआ है।

दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए मामले को देखने के लिए डीएमआरसी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया गया है।

आईआईआईटी की जनरल काउंसिल के पुनर्गठन में देरी से एलजी नाराज

- उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव से तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जनरल काउंसिल के गठन में 3 वर्षों से अधिक की देरी पर चिंता व्यक्त की है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्य सचिव को विश्वविद्यालय के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समयबद्ध तरीके से जनरल काउंसिल का पुनर्गठन सुनिश्चित करने को कहा है। आईआईआईटी-दिल्ली की जनरल काउंसिल के पुनर्गठन की फाइल, जिसकी तीन वर्ष की अवधि मार्च 2019 में समाप्त हो गई थी, मई 2020 से अस्पष्ट कारणों से शिक्षा मंत्री पहले मनीष सिसोदिया और उसके बाद, आतिशी मार्लेना के पास पड़ी थी। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बारे में शिक्षा मंत्री की ओर से जानबूझकर बरती गई निष्क्रियता को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने सरकार से फाइल वापस ले ली।

फाइल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आईआईआईटी की जनरल काउंसिल का गठन अंतिम बार 15 मार्च 2016 को जारी अधिसूचना से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, जो मार्च 2019 में समाप्त हो गई। आईआईआईटी ने प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग से जुलाई, 2019 में ही जनरल काउंसिल के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया था। हालांकि,आईआईआईटी की जनरल काउंसिल की मंजूरी के लिए विभाग का प्रस्ताव बिना किसी कार्रवाई के 20 मई 2020 यानी तीन वर्ष से अधिक समय से शिक्षा मंत्री के कार्यालय में लंबित पड़ा हुआ था।

सचिवालय ने प्रशासनिक विभाग को वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में समयबद्ध तरीके से आईआईआईटी की जनरल काउंसिल के गठन के प्रस्ताव पर कार्रवाई निर्देशित करने हेतु निर्देश जारी किये हैं, वैधानिक प्रस्तावों के संदर्भ में विश्वविद्यालय के सुचारू प्रशासन और कामकाज के लिए मौजूदा कानून लागू है। सचिवालय ने फाइल में कहा है किआईआईआईटी की जनरल काउंसिल, एक वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते संस्थान के कामकाज से संबंधित प्रमुख कार्य जैसे- विकास, योजना, निगरानी और संस्थान के लिए रणनीतिक योजना को क्रियान्वित करना और कार्यक्रमों की समीक्षा करना, संस्थान के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना, संस्थान के वार्षिक खातों पर विचार करने के लिए अनिवार्य है।

डीजेबी ने सीवर में मौत के मामले में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख किया

- उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बढ़ाई मुआवजा राशि

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए सीवर सफाई के मामलों में मौत पर मुआवजा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले अक्टूबर में कहा था कि सरकारी अधिकारियों को सीवर की सफाई के दौरान जान गंवाने वालों के परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। दिल्ली जल बोर्ड के एक आदेश में कहा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए (यह देखते हुए कि पिछली तय राशि यानी 10 लाख रुपए, 1993 से लागू की गई है)। उस राशि का वर्तमान समतुल्य 30 लाख रुपए है। यह वह राशि होगी, जिसका संबंधित एजेंसियों द्वारा भुगतान किया गया।

डीजेबी ने यह भी कहा कि सीवर की सफाई के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले पीड़ितों के मामले में स्थिति की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा। इसने कहा कि न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ज्ञात हो कि पूरे देश में आज भी मजदूर सीवर में उतर कर उसकी सफाई करते हैं, लेकिन इस दौरान कई मजदूरों की मौत की खबर भी सामने आती है। वहीं, सीवर में सफाई करने के दौरान होने वाली मौतों पर लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर निकाला मार्च

- कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबित करने के खिलाफ 22 दिसंबर को जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ संसद का घेराव करने के लिए बुधवार को एक विरोध मार्च निकाला। युवा कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता रायसीना रोड पर संगठन के दफ्तर के पास जमा हुए। प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर थामे हुए थे। प्रदर्शन की अगुवाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय श्रीनिवास बी वी ने की। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस 22 दिसंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। अरविन्दर सिंह लवली ने प्रदर्शन की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन से घबराई भाजपा व एनडीए जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रही है वो भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली कार्यवाही है। संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के बयान की मांग करना अनुचित मांग नहीं है। लवली ने सभी कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ता से जंतर मंतर पर पहुँचने की अपली की है।

रेप-हत्या मामले में बच्ची का नहीं मिला शव

नई दिल्ली। स्वरूप नगर इलाके में अपने मकान मालिक के हाथों कथित रूप से अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की शिकार बनी नौ वर्षीय एक बच्ची का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमारा तलाशी अभियान बुधवार सुबह फिर से शुरू हुआ। अलग-अलग टीम काम कर रही हैं और गोताखोर मुनक नहर में शव की तलाश कर रहे हैं।

स्वरूप नगर इलाके में एक मकान मालिक ने 12 दिसंबर को इस बच्ची का कथित तौर पर अपहरण किया और फिर दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में उसने उसके शव को बाहरी एक नहर में फेंक दिया था।

छीना झपटी में ई-रिक्शा से गिरने से महिला घायल

- पुलिस दर्ज किया मामला, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में छीना झपटी की एक घटना के दौरान ई-रिक्शा से गिरने के बाद अरुणाचल प्रदेश की एक महिला सिर में चोट लगने से घायल हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रविवार को सिविल लाइंस क्षेत्र में पर्स छीनने की सूचना मिली। उसने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली केसांग दोरजी (66) पर्स छीनने के दौरान ई-रिक्शा से गिर गई जिससे उनके सिर में चोट लग गई। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) मनोज कुमार मीणा ने बताया कि दोरजी ई-रिक्शा में मजनू का टीला से मेट्रो स्टेशन जा रही थीं। उन्होंने बताया कि दोरजी को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि रविवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 392 (लूटपाट के लिए सजा) और 394 (लूटपाट करने में जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है।

जब्त पुराने वाहनों से जुड़ी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी

- दोपहिया वाहनों पर 5,000 और चार पहिया गाड़ियों पर 10,000 का जुर्माना लगाने की योजना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए पुराने वाहनों को छोड़ने के लिए तैयार की जा रही एक नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। परिवहन विभाग की नीति उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। यह नीति दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपए और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की योजना बनाई है।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने या सड़कों पर चलाए जाने के चलते प्रवर्तन टीमों ने जब्त कर लिया था। सरकार उन लोगों को अपने वाहनों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए छह से 12 महीने की समय सीमा भी प्रदान कर सकती है जो वाहनों को कबाड़ में नहीं भेजना चाहते। जब भी कोई पुरानी कार मरम्मत के लिए ले जाई जाएगी तो परिवहन विभाग को सूचित करना होगा और गाड़ी को लॉरी या किसी अन्य वाहन में लादकर ले जाना होगा।

उन्होंने कहा कि नीति के तहत लोगों को यह शपथपत्र देना होगा कि वे अपने वाहन सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा नहीं करेंगे और न ही उन्हें सड़कों पर चलाएंगे। अधिकारियों ने पहले बताया था कि दिल्ली सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुराने वाहनों के लिए दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव करने की योजना बना रही है।

अंबेडकर विवि ने 1095 छात्रों को प्रदान की डिग्रियां

- दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, शिक्षा मंत्री आतिशी समारोह में हुई शामिल

अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रा को डिग्री देते एलजी वीके सक्सेना व शिक्षा मंत्री आतिशी।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1095 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। इस बार डिग्रियां प्राप्त करने वालों में 58 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं। विवि के 12वें दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर आतिशी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। कई लोगों के विपरीत, छात्र-छात्रओं को अच्छे संस्थान में पढ़ने का अवसर मिला।

अब मौका है कि आपने संस्थान में जो कुछ सीखा उसका इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए करें। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात है। कई बार समाज में लिबरल आर्ट्स को हेय दृष्टि से देखा जाता है लेकिन लिबरल आर्ट्स पढ़कर छात्रों के भीतर दुनिया के प्रति जो नजरिया विकसित होता है, ऐसा नजरिया किसी और डिसिप्लिन में विकसित नहीं होता है। छात्रों के पास एक बेहतर भारत बनाने की ताकत, जुनून और दृढ़ संकल्प है।

भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने का जो सपना देखा है, अब उसे पूरा करने की जिम्मेदारी छात्रों पर है। इस दहलीज से आप सब बाहर कदम रखेंगे तो आप सभी को अपने लिए या सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं सोचना है बल्कि आप सभी यहां से निकलते वक्त एक देश के लिए भी सपना लेकर जाये और इस भारत को दुनिया का नंबर-1 देश बनाने का सपना साथ लेकर जाए।

इस साल विश्वविद्यालय द्वारा 1095 डिग्रियां सौंपी गई है। इनमें 33 पीएचडी डिग्री, 13 एम फिल डिग्री, 602 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, 442 ग्रेजुएट डिग्रियाँ और 5 डिप्लोमा सौंपी गई।

संक्षिप्त समाचार

सर्वेश तिवारी बनें पीआरएसडी के नए चेयरमैन

नई दिल्ली। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी दिल्ली (पीआरएसडी) के नए चेयरमैन के रूप में सर्वेश तिवारी ने पदभार संभाला है। उन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के मुख्य महाप्रबंधक एसएस राव की जगह बनाया गया है। वहीं दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मार्केटिंग के उपाध्यक्ष विपिन खरबंदा को पीआरएसडी का वाइस चेयरमैन और आरईसी के पूर्व महाप्रबंधक (संचार) राम विजय को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 17 दिसंबर को आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक में क्रिटिक कम्युनिकेशंस के निदेशक संचित शर्मा को संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया। सर्वेश तिवारी पीआर प्रोफेशनल्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। वे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व रक्षा और गृह मामलों के मंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता पीटर डटन पर गुरुग्राम स्थित पीआर प्रोफेशनल्स की सेवा लेने का आरोप लगने के बाद विवादों में घिर गए थे।

दिल्ली से आगरा तक होगी हिंदायन साइकिल दौड़

नई दिल्ली। हिंदायन साइकिल यात्रा एवं दौड़ का दूसरा संस्करण अगले साल फरवरी में दिल्ली और आगरा के बीच आयोजित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। हिंदायन की वेबसाइट पर जाकर इस यात्रा के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। यह पंजीकरण 25 दिसंबर तक ही होगा। कार्यक्रम के संयोजक विष्णुदास चपके ने बताया कि इस यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस दौरान 10 फरवरी, 2024 को दिल्ली-आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर 220 किलोमीटर की साइकिल यात्रा आयोजित की जाएगी। चपके ने बताया कि हिंदायन साइकिल यात्रा और दौड़ का पिछला संस्करण इस साल पांच से 19 फरवरी के बीच दिल्ली से पुणे के बीच आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले संस्करण में भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने भी दल भेजे थे। उन्होंने कहा, हमें 2024 के आयोजन के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) द्वारा अपने दल भेजे जाने की उम्मीद है।

सुकेश के बयान पर रोक को जैकलीन कोर्ट पहुंची

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को उनसे संबंधित कोई भी बयान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया में जारी करने से तत्काल रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में, मंडोली जेल के अधीक्षक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे चंद्रशेखर को उनके (जैकलीन) बारे में कोई और पत्र, बयान या संदेश जारी करने की अनुमति न दें। याचिका में कहा गया कि मीडिया में परेशान करने वाले पत्रों के अनचाहे प्रसार ने उनके लिए परेशान करने वाला माहौल उत्पन्न कर दिया है। इसमें कहा गया कि इसके अलावा, इससे उनकी सुरक्षा और हित भी प्रभावित हुए हैं।

47 लाख यात्रियों ने एनसीएमसी का किया इस्तेमाल

डीएमआरसी ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी के पिछले छह माह के आंकड़े पेश किए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो में यात्रा के लिए पिछले छह महीने में 47 लाख से अधिक यात्रियों ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का इस्तेमाल किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार, सीएमसी सुविधा इस साल पांच जून को शुरू की गई थी और 12 दिसंबर तक 47.97 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है।

डीएमआरसी की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में कुल 1.67 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया, जबकि अगस्त में यह संख्या बढ़कर 4.96 लाख हो गई, सितंबर में 8.52 लाख, अक्टूबर में 12.65 लाख, नवंबर में 13.34 लाख और 12 दिसंबर तक 6.81 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया। अधिकारियों के अनुसार, एनसीएमसी एक ओपन-लूप कार्ड है, जो उपयोगकर्ताओं को मेट्रो यात्रा शुल्क, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क और खुदरा भुगतान करने में सक्षम बनाता है। जबकि कार्ड (एसवी-2) एक बंद-लूप कार्ड है और इसका उपयोग केवल डीएमआरसी प्रणाली में किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सामान्य कार्ड के माध्यम से लोगों को देश भर में मेट्रो और बस सेवाओं सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2019 में स्वदेशी रूप से विकसित एनसीएमसी की शुरुआत की थी। मोदी ने इससे पहले 28 दिसंबर, 2020 को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एनसीएमसी सेवाओं की शुरुआत की थी। डीएमआरसी का मौजूदा नेटवर्क 286 स्टेशन के साथ लगभग 392 किलोमीटर है, जिसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर और गुड़गांव में रैपिड मेट्रो भी शामिल है।

उद्यमशीलता के 5 साल पूरा होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- बेरोजगारी खत्म करने के समाधान के रूप में आप सरकार ने की शुरू किया एंत्रप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम : आतिशी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केजरीवाल सरकार के एंत्रप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के 5 साल पूरा होने के जश्न में बुधवार को एससीईआरटी द्वारा उद्यमशीलता शिक्षा की शक्ति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नामी यंग एंत्रप्रेन्योर्स और शिक्षाविदों ने शिरकत की।

इस सम्मेलन के साथ आयोजित एक्सपो में स्कूलों के बिजनेस ब्लास्टर्स 2022-23 सत्र के छात्रों ने अपने बिजनेस आइडियाज व प्रॉडक्ट्स को भी प्रदर्शित किया। साथ ही 8 राज्यों से माइंडसेट डेवलपमेंट, एजुकेशन व ईको-सिस्टम विषय पर आए 45 रिसर्च पेपर्स भी पेश किए। सम्मेलन में युवा एंत्रप्रेन्योर्स, सफल उद्यमियों, छात्रों व शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन व पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि, जब शिक्षा की बात करते है तो उसका एक मुख्य उद्देश्य ये होता है, छात्रों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना लेकिन आज देश में युवा बेरोजगारों की बड़ी संख्या है।

नर्सिंग ऑफिसर्स ने छह दिन ब्लैक बैज लगाकर बुलंद किए विरोध के स्वर

21 दिसंबर को राज्य स्तरीय बैठक में लिया जा सकता है निर्णय

यूनिटी दिखाकर सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में अपनी मांगों के समर्थन में ब्लैक बैज लगाकर अंतिम दिन के विरोध में एकत्रित नर्सिंग ऑफिसर्स।

अस्पतालों में अपने को कर्तव्य समझकर करने वाली नर्सिंग ऑफिसर्स ने अपनी दो मांगों को लेकर छह दिन तक ब्लैक बैज लगाकर सरकार के समक्ष आवाज उठाई। काम भी प्रभावित ना हो और उनकी मांगें भी सरकार तक पहुंचे, इसी सोच के साथ नर्सिंग ऑफिसर्स ने ब्लैक बैज लगाकर ही काम किया।

शांतिपूर्वक विरोध के छठे एवं अंतिम दिन बुधवार को सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर्स ने एकत्रित होकर अपनी यूनिटी दिखाई। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया।

इस अवसर पर ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की राज्य प्रधान निर्मल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर्स की दो ही मांगें हैं। पहली तो उन्हें केंद्र सरकार के नर्सिंग ऑफिसर्स के समान 7200 रुपये नर्सिंग अलाउंस दिया जाए। दूसरी मांग नर्सिंग ऑफिसर्स को सी ग्रुप से बी ग्रुप में शामिल किया जाए। इन दो मांगों को सरकार वर्षों से लटकाए हुए है। इन मांगों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन ने 12 दिसम्बर को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद इस पर कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब एसोसिएशन आगे की रणनीति 21 दिसम्बर गुरुवार को राज्य स्तरीय की बैठक में तय की जाएगी। राज्य प्रधान निर्मल ढांडा ने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर्स की ओर से अपने कार्यस्थल पर सदा काम को तवज्जो दी जाती है।

शरीर में रीढ़ की हड्डी की तरह अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं। मरीज की हर स्तर पर उन्हें देखभाल करनी पड़ती है। मरीजों के अलावा अस्पतालों में अन्य कई कार्यों में भी नर्सेज को लगाया जाता है। कोविड19 के समय और वैक्सीनेशन में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अहम भूमिका निभाई। अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने देना ही उनकी प्राथमिकताओं में रहता है।

नर्सिंग ऑफिसर अपने काम को पूरी निष्ठा से करती/करते हैं। अपने काम की वे वे खुद जिम्मेदारी लेती हैं। जिला प्रधान कमलेश सिवाच, सीएनओ सुनीता देवी, एसएनओ नीलम, एसएनओ रोशनी देवी, एसएनओ संतोष, एसएनओ निर्मल कुमारी, एसएनओ प्रेम देवी, नर्सिंग ऑफिसर पूनम सहराय, दीप्ति, प्रियंका अरोड़ा, जया कुमारी, प्रियंका सैनी, नेहा, कोमल, अंकिता समेत अनेक नर्सिंग ऑफिसर्स ने यूनिटी दिखाकर सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की।

नर्सिंग ऑफिसर्स ने कहा कि वे अपने इस प्रोफेशन में अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठातीं, जिससे कि मरीजों के उपचार में कोई बाधा आए। बीते छह दिनों में उनका यह प्रयास रहा कि उनकी तरफ से अपनी मांगें भी सरकार तक पहुंच जाएं और काम भी प्रभावित ना हो।

अब भारत की धरती पर नहीं होंगे हिंदू विरोधी षडयंत्र: डॉ.जैन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम में पत्रकारों से बात करते विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन।

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डा. सुरेंद्र जैन ने कहा कि भारत देश पर हमला करने वालों, लुटेरों द्वारा बनाए गए अपमान के प्रतीकों को देश क्षमा नहीं कर पाएगा। अब भारत की धरती पर हिन्दू विरोधी षडयंत्र नहीं हो पाएंगे। वर्ष 1885 में दर्ज मुकदमें में 491 वर्ष के संघर्षों, लाखों बलिदानों और 134 साल की न्यायिक लड़ाई के बाद देश में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया। अब अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है। यह पूरे विश्व के हिन्दुओं की जीत है और जश्न का दौर है। यह बात उन्होंने बुधवार को यहां पत्रकारवार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर हुआ आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। 16 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। अनेक बलिदानों के बाद हमें वह दिन देखने को मिला है जिसका सेंकड़ों वर्षों से इंतजार था। डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि देश में रहने वाले किसी भी पंथ के लोग हों, सभी ने राम मंदिर के लिए सहयोग दिया है। भिक्षुक से लेकर धनाढ्यों तक के सहयोग से राम मंदिर बना है। इसमें 65 करोड़ राम भक्तों ने सहयोग दिया। 22 जनवरी को राष्ट्रीय शौर्य जागरण का महापर्व है। केवल अयोध्या ही नहीं संपूर्ण विश्व के राम भक्त इस दिन को दीपावली की तरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं।

डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास के बाद दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे और अब 491 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम फिर से लौट रहे हैं। इस खुशी में देश के 5 लाख मंदिरों में दीपोत्सव होगा। वहां पर अयोध्या से राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हर राम भक्त के घर पर घी के दीपक जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 30 हजार टोलियां बनेंगी, जिसमें एक लाख कार्यकर्ता होंगे। वे प्रदेश के 6725 गांवों में जाएंगे और लोगों को 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम का निमंत्रण देंगे। डा. सुरेंद्र जैन ने कहा कि गुरुग्राम में 5 हजार कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे। गुरुग्राम के सिद्धेश्वर मंदिर में 21 हजार दीपक, सेक्टर-10ए स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 11000 दीपक, गौशाला में 11000 दीपक और श्री शक्ति मंदिर सेक्टर-23 में 11000 दीपक जलाए जाएंगे।

इस अवसर पर स्वामी ब्रहमोद्रानन्द सरस्वती ने कहा कि जिस दिन का इंतजार रामभक्तों को सदियों से था वो पूरा हो रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है।

आधुनिक मशीनी तकनीक के प्रयोग से ही कम हो सकती है कृषि लागत : एडीसी मीणा

ड्रोन के रेट तय करने के लिए कृषि विभाग की आयोजित हुई बैठक

उच्चाधिकारियों से बात कर निश्चित किए जाएंगे जिले में ड्रोन के दाम

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

कृषि विभाग अधिकारियों के साथ बैठक करते एडीसी हितेश कुमार मीणा।

एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि सस्ती दरों पर अत्याधुनिक मशीनी तकनीक को उपलब्ध करवा कर ही खेती में किसान के लागत व्यय को कम किया जा सकता है। इसी मकसद से भारत सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग को लेकर आई है। वे बुधवार को ड्रोन के जिला में सरकारी रेट तय करने के लिए कृषि विभाग द्वारा आयोजित बैठक को ले रहे थे।

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी, ड्रोन चलाने वाली निजी कंपनियों के प्रतिनिधि व सहयोगी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कंपनी प्रतिनिधियों ने प्रति एकड़ ड्रोन के खर्च की दरें सामने रखीं और विचार-विमर्श के बाद अपने फाइनल रेट दिए। एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश में किसान की आय को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। एक ड्रोन दस लीटर के टैंक से नैनो यूरिया को एक एकड़ भूमि में 6 मिनट में स्प्रे कर देता है। इससे पानी व समय की भी बचत होती है तथा किसान को फसल की 8 से दस प्रतिशत अच्छी पैदावार मिलती है। उन्होंने कंपनियों को आश्वस्त किया कि कृषि विभाग के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर अंतिम दरें ड्रोन की तय कर दी जाएंगी। इस विषय में कंपनियों को भी अपने सामाजिक दायित्व को समझना होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. अनिल तंवर ने बैठक में बताया कि जिला के 62 किसानों ने ड्रोन से छिड़काव के लिए अपनी 301 एकड़ भूमि को पंजीकृत करवाया है। सरकार किसान से 100 रुपए लेकर प्रति एकड़ में ड्रोन से नैनो यूरिया का स्प्रे करवाएगी।

इसका बाकी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इफको के प्रबंधक हितेंद्र सिंह ने बताया कि इफको ने हरियाणा प्रदेश में 98 महिला व पुरुष किसानों को ड्रोन उड़ाने की हिसार में 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई है। इनमें से तीन गुरुग्राम के हैं। जो कि हिमांशी, शर्मिला व रामकिशन हैं। ये ड्रोन पायलट भी बैठक में उपस्थित थे। एडीसी ने कहा कि इन महिला पायलट से गांवों के विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में ड्रोन उड़वाया जाए।

सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की नहीं होगी कमी: सरपंच यादव

गांव सिकंदरपुर बढ़ा के शहीद सूबेदार पार्थ सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में सरपंच सुंदर लाल यादव ने प्रधानाचार्या से की चर्चा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गांव सिकंदरपुर बढ़ा स्कूल की प्रधानाचार्या गगन रानी का स्वागत करते सरपंच सुंदर लाल यादव।

जिला के गांव सिकन्दरपुर बढ़ा के शहीद सूबेदार पार्थ सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में नवनियुक्त प्रधानाचार्या गगन रानी का सरपंच सुंदर लाल यादव ने बुके देकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई व मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनसे चर्चा की।

चर्चा सत्र में सरपंच सुंदर लाल यादव ने कहा कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों का स्तर सरकार ने सुधारा है। शिक्षा का ढांचा मजबूत किया है। देश में जो नई शिक्षा नीति बनी है, उससे हमारा स्कूलों में शिक्षा का स्तर और अधिक मजबूत होगा। बच्चों को नई शिक्षा नीति में अपने कला, अपनी संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाएगा।

अब पढ़ाई के साथ रोजगार की शिक्षा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने स्कूलों को अपग्रेड करने, स्कूलों की इमारत बनाने के साथ स्कूल, कालेजों में बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा सुविधा भी दी है। ग्रामीण स्तर तक कालेज बनाए गए हैं। मेडिकल की शिक्षा देने के लिए हर जिला में मेडिकल कालेज बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम का यह सौभागय है कि यहां माता शीतला के नाम पर मेडिकल कालेज सेक्टर-102 खेड़की माजरा गांव में बन रहा है। सरपंच सुंदर लाल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। स्कूलों की खस्ता हालत को सरकार ने सुधारा है।

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए भाग लेंगे प्रख्यात कलाकार

गुरुग्राम। शहर के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्राता सेनानी जिला परिषद सभागार में 22-23 दिसंबर को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव समारोह की तैयारियां जोरों पर है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय समारोह में भारत के पावन ग्रंथ के प्रकट दिवस को मनाया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता का पावन संदेश दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए हर साल जिलास्तर व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाए जाने की परंपरा वर्ष 2015 में शुरू की थी।

नगर निगम ने शुरू किया स्वच्छता हीरो बनें-विलेन नहीं जागरुकता अभियान

गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित रंगभूमि ओपन एयर थिएटर से 50 जागरूकता वाहनों को रवाना करते संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डॉ. नरेश कुमार।

संयुक्त आयुक्त ने 50 जागरुकता वाहनों को किया रवाना

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नागरिकों को साफ-सफाई बनाए रखने तथा कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता हीरो बनें-विलेन नहीं अभियान की शुरूआत की गई। अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार ने सेक्टर-29 स्थित रंगभूमि ओपन एयर थिएटर से 50 जागरूकता वाहनों को रवाना किया। ये वाहन अलग-अलग क्षेत्रों में ऑडियो संदेश व फ्लैक्स बैनर पर लिखे संदेशों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करेंगे।

इस मौके पर संयुक्त आयुक्त ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशानुसार शहर की साफ-सफाई को बेहतर करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम हर संभव कार्य कर रहा है। इसके तहत 1 दिसंबर से विशेष सफाई अभियान लगातार चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप शहर में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के साथ ही कचरे, मलबे व हॉर्टिकल्चर वेस्ट का उठान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष जागरूकता अभियान के तहत 50 जागरूकता वाहन तैयार किए गए हैं, जिनमें ऑडियो संदेश के माध्यम से नागरिकों को कचरा ना फैलाने तथा कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा जागरूकता वाहन पर लिखित संदेशों व चित्रों के माध्यम से भी गीला, सूखा, घरेलू हानिकारक तथा जैव अपशिष्ट को अलग-अलग करने के लिए अपील की गई है।

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा यह जागरूकता अभियान पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है। क्योंकि अभियान में शामिल सभी 50 वाहन इलेक्ट्रिक हैं। जागरूकता अभियान में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने शहर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था को लगातार बेहतर कर रहा है।

शिकायतें वाट्सएप पर भेजें : संयुक्त आयुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा कूड़े, सीएंडडी वेस्ट (मलबे) व हॉर्टिकल्चर वेस्ट संबंधी शिकायतों के लिए अलग-अलग वाट्सएप नंबर जारी किए हुए हैं। नागरिक कूड़े या साफ-सफाई से संबंधित शिकायत के लिए वाट्सएप नंबर 7290097521, सीएंडडी अर्थात मलबा संबंधी शिकायत के लिए वाट्सएप नंबर-7290088127 तथा हॉर्टिकल्चर वेस्ट संबंधी शिकायत के लिए वाट्सएप नंबर-7290076135 पर फोटो व लोकेशन के साथ शिकायत भेजें।

आढ़तियों की हड़ताल से मंडी में पसरा सन्नाटा

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

मार्केट कमेटी विभाग की फीस वृद्धि के विरोध में स्थानीय मंडी में सब्जी आढ़तियों ने एक दिन की हड़ताल की। हडताल में सब्जी के रिटेलर में दुकानदार और कुछ रेहड़ी मालिकों ने भाग नहीं लिया। जिन्होंने रोजाना की तरफ से बुधवार को भी अपनी दुकान खोली और रेहड़ियां लगाई।

बुधवार को स्थानीय मंडी में सब्जी आढ़तियों ने मार्केट कमेटी की फीस वृद्धि और एक साल की फीस एक बार में लिए जाने के विरोध में हड़ताल की। हड़ताल की सूचना मंडी में सब्जी लेकर आने वाले किसानों को मंगलवार को ही मना कर दिया था। जिसके कारण बुधवार को किसान अपनी सब्जी को लेकर बिक्री के लिए मंडी में नहीं चहुंचे। आढ़तियों ने अपनी आढ़त सुबह से ही बंद रखी। जिसके चलते आज सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा रहा।

रिटेलर की दुकानें खुली : मंडी परिसर में रिटेल में सब्जी बेचने वाली करीब 150 दुकानों में बैठें दुकानदारों ने हड़ताल में पूरी तरह से भाग नहीं लिया। सब्जी के रिटेलर दुकानदारों ने सुबह 10 बजे के बाद से अपनी दुकानों को खोल लिया। इसी प्रकार से रेहड़ी व ठेला मालिकों ने मंगलवार को बची सब्जियों को ही बेचा। हड़ताल म रेहड़ी और ठेला मालिकों का असर भी मिला झूला रहा। क्योकि आढ़तों से सब्जियां लेकर बेचने वाले रेहड़ी-ठेला मालिक आज सुबह अपने घरों से नहीं आए। जिनकी संख्या 30 से 40 के लगभग थी।

ग्राहक भी कम पहुंचे कम : बुधवार को सब्जी आढ़तियों की हड़ताल होने की सूचना मंगलवार को शहर में आग की तरफ से फैल चुकी थी। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदार किरयाना और परचून का सामान लेकर गए। लेकिन मंडी में सब्जी की रिटेलर वाली दुकानों पर बुधवार को 10 से 15 फीसदी ग्राहक पहुंचा। एक दिन पहले की सब्जी होने के कारण रिटेलर दुकानदारों ने सामान दर पर ही से बेचा। हड़ताल को लेकर मार्केट कमेटी कार्यालय अधिकारी सचिव सुनीता शर्मा ने बताया कि सरकार के आदेशों की पालना की जाएगी। सरकार के आदेश के अनुसार फीस ली जाएगी। वहीं सब्जी की आढ़त बंद होने के कारण कोई भी व्यापारी मंडी परिसर में नहीं था।

वेंडर्स को सही तरीके से डोर-टू-डोर कचरा उठाना सुनिश्चित करने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

नगर निगम में बैठक लेते अधिकारी।

नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में घर-घर से कचरा एकत्रित करने वाले सभी वेंडर्स के साथ संयुक्त आयुक्तों ने अपने कार्यालय में बैठक की तथा उन्हें कार्य में बेहतर सुधार लाने के निर्देश दिए।

संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव ने जोन-1 क्षेत्र के वेंडर्स, संयुक्त आयुक्त संजीव सिंगला ने जोन-3 क्षेत्र के वेंडर्स, संयुक्त आयुक्त विजय यादव ने जोन-3 क्षेत्र के वेंडर्स तथा संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार ने जोन-4 क्षेत्र के वेंडर्स के साथ बैठक में सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई वेंडर अपना कार्य सही तरीके से नहीं करता है, तो उसे हटाकर उसकी जगह किसी अन्य वेंडर को कार्य सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने का कार्य सही प्रकार से ना होने के कारण नागरिकों को मजबूरीवश इधर-उधर कचरा फेंकना पड़ता है, जिससे गंदगी व बदबू फैलती है।

शहर में जगह-जगह पर कूड़ा हो जाता है। नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के तहत इधर-उधर फैले कूड़े को उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सभी वेंडर अपने-अपने क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा उठान सही प्रकार से सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को इधर-उधर कचरा ना फैंकना पड़े। अगर कोई वेंडर सही तरीके से कार्य नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक साथ हजारों विद्यार्थियों ने किया हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ

रॉयल पब्लिक स्कूल वजीरपुर में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने भी लिया भाग

बोधराज सीकरी के नेतृत्व में चलाई जा रही है हनुमान चालीसा पाठ मुहिम

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के वजीरपुर गांव स्थित रॉयल पब्लिक स्कूल में हनुमान चालीसा पाठ करते बच्चे, शिक्षक व अतिथि।

रॉयल पब्लिक स्कूल वजीरपुर में हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य स्टाफ ने एक साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। यहां 2725 साधकों ने 11-11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। समाजसेवी बोधराज सीकरी की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम की रॉयल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन विजय सिंह चौहान, कल्पना चौहान और आशीष सिंह चौहान ने सराहना की। बोधराज सीकरी ने बताया कि 10 महीने में पहली बार इतने बड़े समूह में हनुमान चालीसा पाठ गजेंद्र गोसाई की अगुआई में संगीतमय तरीके से हुआ है।

विद्यार्थियों ने पूरे अनुशासित तरीके से इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया। उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ के कुछ रहस्य की बातें भी विद्यार्थियों से सांझा की। किसी भी आध्यात्मिक कार्य में कैसे बैठा जाए, यह विधि भी बोधराज सीकरी ने विद्यार्थियों को सिखाई।

राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य, संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य, महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारा कर्तव्य और राष्ट्रगान व राष्ट्र की धरोहरों की सुरक्षा आदि बहुत से उदाहरण देकर बच्चों को प्रेरणा दी। स्कूल चेयरमैन विजय सिंह चौहान ने बोधराज सीकरी और उनकी टीम का शॉल पहनाकर अभिनंदन किया। उनसे आग्रह किया कि गुरुग्राम शहर में जो स्कूल हैं, उनमें भी हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करें और विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से संबोधित करें। विजय टंडन और रणधीर टंडन की फैक्टरी में वर्कर्स ने संकल्प लिया कि वो हर मंगलवार को फैक्ट्री में काम करने से पहले हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। वहां के 78 कर्मचारियों ने 2-2 बार पाठ किया। लोगों से जूम एप के माध्यम से ऑनलाइन हनुमान चालीसा पाठ कराने का भी संकल्प लिया है।

ऑनलाइन लगभग 36 महिलाओं ने 11-11 बार पाठ किया। अभी तक किये गए 10 महीनों के अंदर विभिन्न स्थानों पर किये गए पाठ को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इससे पहले 165 स्थानों पर हनुमान चालीसा के 462922 पाठ 32652 साधकों ने किए थे। इस मंगलवार के पाठ को मिलाकर 171 स्थानों पर 35,961 साधकों द्वारा 495,639 हनुमान चालीसा पाठ हो चुके हैं।

प्रशिक्षण के बाद 34 महिलाओं ने प्रमाणपत्र प्राप्त किये

पलवल। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रतीपुर पलवल में 33 बीपीएल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 13 दिवसीय जूट प्रोडक्ट उद्यमी बैच का समापन एवं मूल्यांकन हुआ। जिसमें अजय कुमार अग्रवाल ईडीपी असेसर एवं कोमल डोमेन असेसर ने मूल्यांकन किया। रवि शर्मा निदेशक ने सभी महिलाओं को भविष्य में रोजगार चालू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी का उत्साह बढ़ाते हुए बताया कि छोटे छोटे से बड़ा उद्यम स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा लोन लेकर अपना रोजगार चालू किया जा सकता है। संस्थान द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। वीरेंद्र सिंह कोर्स कोआर्डिनेटर ने बताया कि संस्थान पलवल जिले में वर्ष 2011 से कार्य कारयत है। जिसमें पलवल जिले के बेरोजगार युवक युवतियां भाग लेकर अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकती है। संस्थान द्वारा फ्रीज, एसी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सीसीटीवी कैमरा, मोटरसाइकिल सर्विसिंग, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट, वूमेन ट्रेलर, जूट प्रोडक्ट उद्यमी, टेडी बियर मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती, अचार पापड़ इत्यादि कोर्स निशुल्क कराए जाते हैं।

नवनियुक्त जिला बार एशोशिएशन की टीम ने ली शपथ

वकीलों ने टीम का फूलमालाओं से किया स्वागत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिला बार एशोशिएशन का सेक्टर-12, कोर्ट परिसर के प्रांगण में नई नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ समारोह आयोजित किया गया। जिसमें निर्वाचन अधिकारी ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को पदभार सौंपा। चुने हुए प्रधान जोगिंद्र नरवत व महासचिव पवन पाराशर व अन्य टीम को वकीलों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इस मौक पर वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व प्रधान संजीव चौधरी ने बोलते हुए कहा कि नई टीम बिना भेदभाव के सभी वकीलों के लिए कार्य करेगी और वकीलों की बैठने की समस्या व पार्किंग की समस्या के निवारण के लिए जल्द ही कोई समाधान निकाला जायेगा।

बार काउन्सिल पंजाब एंड हरियाणा के को-चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि किसी भी वकील की समस्या अगर बार काउंसिल में आती है तो वो उसका निवारण फरीदाबाद में बैठे हुए ही कर देंगे। चेयरमैन कुंवर दलपत सिंह व पूर्व प्रधान जोगिंद्र चौहान ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने बड़ी शांति से कराया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं।

बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा पूर्व मनोनित सदस्य शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट ने कहा कि बार और बैंच के बीच समन्वय स्थापित कराने का प्रयास किया जायेगा और किसी भी वकील की समस्या आती है तो नई कार्यकारिणी तुरंत उसका हल करेगी। मंच का संचालन पूर्व महासचिव धर्मवीर डागर एडवोकेट ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता जयबीर बीसला, पीके मित्तल, ओपी यादव, राव संजीव, एदल सिंह रावत, नरेंद्र अत्री, कुंवर बालू सिंह, वंदना भाटी, प्रदीप परमार, सतबीर शर्मा, संजीव अत्री, मुकेश नैन, कन्हैया लाल शर्मा, महेंद्र बैंसला, भारत चंदीला, अनुज शर्मा, सर्वेश कौशिक, अमित शर्मा, डीएस रावत, कमल भाटी, ओमप्रकाश कसाना, धर्मवीर नागर, आरपी वर्मा, मनमीत कौर, कुलदीप जोशी, विजय यादव, मनोज कुमार, रिंकेश अरोड़ा, आशीष मसीह, तरूण अरोड़ा, मंशा पासवान, पुष्पा चौहान, रीमा डागर, मंजुला अरोड़ा, आमीर चौधरी, रोहन शर्मा, वीरेंद्र धनखड़ आदि सैकड़ों वकील मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

केसीएम पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

पलवल। केसीएम पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में केजीवन से दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। जिसमें सर्वप्रथम केजी वन के छात्रों ने दौड़ लगाकर रिंग में बॉल एकत्रित किए। इस खेल में प्रथम स्थान तेजस्वी, द्वितीय प्रिंस और तृतीय स्थान रोहित ने अपने नाम किया। केजी टू के छात्रों ने रेस में दौड़कर बोतल की कैप खोले और बंद किए। इस खेल में कीर्ति, नव्या, लव, प्रवीण, रितेश और देव ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा प्रथम के छात्रों ने रेस में दौड़कर भाग लिया तथा डिस्पोजल गिलास द्वारा पिरामिड बनाए। इस खेल में दिव्यांशी, नैतिक, मयंक, दिव्या, रितेश, हर्षिता ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया और कक्षा दो के छात्रों ने रिंग रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। जिसमें गर्व, लावण्या, वेदिका, मयंक, सुहर्ष व रितेश ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान अपने नाम किया। सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया तथा बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मंच का संचालन सविता वर्मा ने किया तथा संपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय के खेल प्रशिक्षक सुरजीत द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किरण दीवान की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम के अंत में निदेशक देवदत्त भारद्वाज एवं प्रधानाचार्य सुनील आर्य द्वारा विजेता छात्रों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया तथा सभी छात्रों में खेल भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

बच्चों का सर्वांगीण विकास करना प्रतियोगिता का उद्देश्य

पलवल। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी-2023 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी हथीन सगीर अहमद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना व इनोवेटिव आइडिया के द्वारा समाज को लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वह सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें। उन्होंने कहा कि विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान और आप सभी इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनकर अपना, अपने समाज का, अपने खंड का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों को विज्ञान के विभिन्न अविष्कारों के बारे में जानकारी दी। एसडीएम हथीन ने बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल का निरीक्षण किया तथा बच्चों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में दो तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिसमें एक ग्रुप कक्षा छह से आठ का और दूसरा ग्रुप कक्षा नौ से 12 का शामिल रहा। इस अवसर पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने सभी अध्यापकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाएं। मुख्य अतिथि ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ध्यान लगाकर शिक्षा ग्रहण करें और उच्च से उच्च मुकाम हासिल करें। मंच संचालन रविंद्र दीक्षित ने किया। इस कार्य के लिए 12 सदस्य जजों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से सभी विषयों की टीमों को चेक किया और उनके आधार पर रिजल्ट घोषित किया। जज के रूप में प्रधानाचार्य सतीश कुमार, प्रधानाचार्य करणपाल, जीवन लाल, जीतपाल, ज्योति शर्मा, सोनिया महेला, करुणा रानी आदि मौजूद रहीं।

प्रतिभा खोजो योगासन प्रतियोगिता का आयोजन

पलवल। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष में जिलाभर में योग प्रतियोगिता क्रांति के संदर्भ में प्रतिभा खोजो योगासन प्रतियोगिता का आयोजन पूर्ण कालिक सेवा वृत्ति योगाचार्य गुरमेश सिंह के सानिध्य में राजकीय माध्यमिक पाठशाला नंबर चार शहर पलवल में गायत्री महामंत्र के उपरांत आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता देववती स्कूल हेड ने की तथा संयोजन विजेंद्री ने किया। निर्णायक मंडल की भूमिका सुदेश, सुनीता, धर्मवीर, अमृतलाल ने निभाई। विजेता खिलाड़ियों को योगाचार्य गुरमेश सिंह व अन्य अतिथियों ने वस्त्र तथा प्रमाणपत्र द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ योगी शिवम विजेता तथा ऋतिक उपविजेता रहे। इसी प्रकार लड़कियों के वर्ग में कुमारी इरम विजेता तथा जूही, अंशु उपविजेता रही। बाकी परिणाम में लड़कों के पांच से आठ आयुवर्ग में गौरव, गुलशन, गुड्डू, 10 से 12 आयुवर्ग में विवेक, चंद्रपाल, संदीप, शौकत, 12 से 14 आयुवर्ग में शिवम, राहुल, गौरव विजेता रहे। इसी प्रकार लड़कियों के वर्ग में पांच से आठ आयुवर्ग में पूजा, राधिका, पायल, बबली, आठ से 10 आयुवर्ग में जूही, प्रिया, कशिश, प्राची, 10 से 12 आयुवर्ग में मधु, बबली, रांशिका, 12 से 14 आयुवर्ग में इरम, अंशु, राधिका, दीप्ति विजेता रही।

सरकारी योजनाओं से विलंबित आवेदनों को तुरंत करें निपटारा

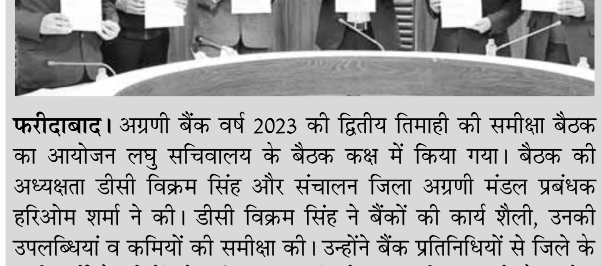

फरीदाबाद। अग्रणी बैंक वर्ष 2023 की द्वितीय तिमाही की समीक्षा बैठक का आयोजन लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीसी विक्रम सिंह और संचालन जिला अग्रणी मंडल प्रबंधक हरिओम शर्मा ने की। डीसी विक्रम सिंह ने बैंकों की कार्य शैली, उनकी उपलब्धियां व कमियों की समीक्षा की। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से जिले के सभी वर्गों के लोगों को सुविधाजनक ढंग से ऋण स्वीकृत करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि की विलंबित आवेदनों को तुरंत निपटारा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित संभाव्यतायुक्त ऋण योजना पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक पीयूष गोयल ने सभी प्रतिभागियों का इस सभा में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा आभार व्यक्त किया। बैठक में हरिओम शर्मा ने दूसरी तिमाही की रिपोर्ट पेश की। समीक्षा बैठक में रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक विनोद कुमार, डीडीएम नाबार्ड विनय त्रिपाठी, एफएलसी रोहताश सिंह यादव, आरसेटी निदेशक सतवीर सिंह, फरीदाबाद जिले के अनेक प्रशासनिक अधिकारी व सभी बैंकों के प्रतिनिधियों ने इस सभा में भाग लिया।

फरीदाबाद की सब्जी मंडी के आढ़ती हड़ताल पर

एडवांस में टैक्स देने के फैसले पर भड़के, कहा, नए स्लैब से व्यापारी परेशान

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

सरकार द्वारा सब्जी मंडी आढ़तियों पर लगाए गए नए टैक्स और एडवांस टैक्स के विरोध में फरीदाबाद की सब्जी मंडियां बुधवार को बंद हो गईं। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह का कहना है कि अभी तक एक प्रतिशत मार्केट फीस और एक प्रतिशत एचआरडीएफ लिया जाता था, जोकि ग्राहकों से लेकर सरकार को देना होता था। लेकिन अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 स्लैब बनाए गए हैं। जिसके चलते एडवांस में यह टैक्स भरना होगा। अगर पूरे साल काम कम होता है तो पैसा वापस का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर काम ज्यादा होता है तो उसी के मुताबिक और टैक्स देना होगा।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में टैक्स को वापस ले लिया गया था, लेकिन कोरोना काल में हरियाणा की वर्तमान सरकार ने इस टैक्स को फिर से लेना शुरू कर दिया था। अब टैक्स को एडवांस और बढ़ाकर लिए जाने व नए स्लैब लेने से आढ़ती परेशान हैं। जिसके चलते हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल से लोग परेशान हो रहे हैं।

रणबीर ने कहा कि अगर सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधान ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी में सामान की बिक्री पर दो प्रतिशत मार्केट फीस लेता है। वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसे माफ कर दिया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया।

अब यह फीस सप्ताह में दो दिन ली जाती है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मार्केट फीस को आढ़ती की वार्षिक बिक्री को आधार बनाकर अग्रिम तौर पर लेना चाहता है। इसका आढ़ती विरोध कर रहे हैं। आढ़त व्यापार संघ के प्रधान रोहताश शेखावत ने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अभी अग्रिम तौर पर एकमुश्त मार्केट फीस लेने के विरोध में बुधवार को सब्जी मंडियों में हड़ताल रही।

पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख ठगे

पलवल। एक व्यक्ति से बेटे को राजस्थान पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन रुपए ठग लिए। सीएम विंडो पर दी शिकायत के आधार पर हसनपुर थाना पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच होडल डीएसपी सज्जन कुमार को सौंपी गई है। नौरंगाबाद उर्फ मोहरू का नंगला निवासी जलालुद्दीन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसने जिला भरतपुर राजस्थान के जुरहरी में जमीन ली हुई है। उसी दौरान उसकी मुलाकात जुरहरी गांव निवासी इसर और नूंह के रीटट नगीना निवासी रसीद से हुई। उसने बताया कि जब करीब दो साल पहले अपने गांव गया तो इसर और रसीद उसके घर आए और कहने लगे कि तेरे बेटे को पुलिस में नौकरी लगवा देंगे। उनकी कामा के विधायक जायदा से अच्छी जानकारी है। इसके लिए पांच लाख रुपये लगेंगे। इस पर उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। दोनों ने उससे कहा कि तीन लाख अब दे दो, दो लाख नौकरी लगने के बाद दे देना। इस पर जलालुद्दीन ने उन्हें दो लाख रुपये दे दिए। उसके बाद दोबारा आरोपी उसके पास आए और कहने लगे विधायक ने कहा है कि तीन लाख रुपए पहले चाहिएं, दो बाद में दे देना।

बिजली निगम का लाइनमैन 15 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

बिजली बिल कम कराने के लिए 34 हजार रुपये मांग रहा था, विजिलेंस की टीम ने पकड़ा

पलवल। बिजली निगम में तैनात लाइनमैन को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शहर के हरी नगर के रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई की है। लाइनमैन बिजली का बिल कम कराने के लिए 34 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। कार्रवाई के समय ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन नरेंद्र यादव मौजूद रहे। मामले की जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर राज कुमार ने बताया कि हरी नगर निवासी रोबिन ने शिकायत दी थी कि उसका बिजली का बिल ज्यादा आया था। इस बिल को कम कराने के नाम पर उससे रिश्वत मांगी गई है। चांदहट एसडीओ कार्यालय में तैनात लाइनमैन लखमेंद्र उर्फ लोकेंद्र उससे 34 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन नरेंद्र यादव को नियुक्त किया गया। लाइनमैन लखमेंद्र उर्फ लोकेंद्र को रिश्वत की रकम मंगलवार शाम को रसूलपुर रोड पर देना तय हुआ। इसके लिए विजिलेंस की टीम ने पीड़ित को रंगे हुए 15 हजार रुपए के नोट दिए। रोबिन ने यह नोट रसूलपुर रोड पर लाइनमैन लखमेंद्र को दे दिए। रिश्वत देने के बाद टीम को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर लाइनमैन लखमेंद्र को रुपयों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हाथ धुलवाने पर रुपयों में लगे रंग के कारण लाइनमैन के हाथ लाल हो गए। टीम लाइनमैन को गिरफ्तार कर अपने साथ फरीदाबाद विजिलेंस थाने ले गई। टीम ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

12 सेक्टर में कार्यालय स्थानांतरित होने से हुडा सेक्टर वासियों की बढ़ी परेशानी

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

छह महीने पहले पलवल सेक्टर दो स्थित हुडा कार्यालय को सेक्टर-12 भेजने के बाद सेक्टर दो के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सेक्टर दो के लोगों को अपनी सीवर, पानी, सड़कों, एनओसी व दूसरे कार्यों के लिए 12 सेक्टर में धक्के खाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना था कि जब सेक्टर दो मे ही हुडा कार्यालय था तो उनके कार्य तुरंत हो जाते थे। परंतु अब कई-कई दिन तक उन्हें कार्यों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस तरीके से उनका समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं। हुडा कार्यालय को सेक्टर-12 में शिफ्ट किया गया तब से उनको कार्य होने में कई-कई दिन लग जाते हैं। उन्होंने बताया कि पानी के बिल को मिलने व भरने में भी सेक्टरवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है अब सेक्टर दो 90 प्रतिशत बन चुका है। इसकी वजह से सेक्टर में हजारों मकान बन चुके हैं। इ

> **पलवल** हुडा सेक्टर दो के सीवर-पानी के कार्यालय के सेक्टर 12 शिफ्ट होने के बाद से सेक्टर वासियों को अपने सीवर, पानी व दूसरे कार्यों के लिए सेक्टर 12 के कार्यालय में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे उनका समय और धन बर्बाद होता है। कार्यालय को दोबारा से सेक्टर दो में ही शिफ्ट किया जाए। जिससे लोगों को सुविधा रहे।
> **-द्रोण सिंह जन्नत, सेक्टरवासी**

> **सीवर-पानी** के कार्यालय को 12 सेक्टर में शिफ्ट होने के बाद लोगों ने इसको सेक्टर दो में ही करने की मांग की है। इस पर उच्च अधिकारियों से सलाह मशविरा के बाद इस पर अमल किया जाएगा।
> **-मेहरचंद, उपमंडल अभियंता हुडा**

साढ़े तीन करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे पांच गांवों में सचिवालय

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बल्लभगढ़ ब्लॉक के पांच गांवों में सचिवालयों का निर्माण करवाया जाएगा। सचिवालयों के निर्माण के बाद ग्रामीण अपने सभी कार्य सचिवालयों में ही कर सकेंगे। इसके लिए पंचायती राज के भेजे प्रपोजल को उच्च अधिकारियों की मंजूरी मिल चुकी हैं। साल 2024 के आखिर तक इन सचिवालयों का निर्माण पूरा करके ग्रामीणों को सौंप दिया जाएगा।

ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने के लिए जल्द ही पंचायती राज्य विभाग बल्लभगढ़ की तरफ से क्षेत्र के गांव डीग, मोहला, अटेरना, जोकोपुर व सिकराना में सचिवालयों का निर्माण करवाने का फैसला लिया गया है। प्रत्येक सचिवालय के निर्माण पर लगभग 70 लाख की लागत आएगी। सचिवालयों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए कमरे, हॉल, बाथरूम, टायलेट आदि बनाए जाएंगे। इन सचिवालयों में बैठकर ग्रामीण अपने सभी फैसले ले सकेंगे। अब तक ग्रामों में सचिवालयों की सुविधा नहीं होने की वजह से गांवों की पंचायतों को मंदिर व सामूहिक जगह पर अपने फैसले लेने पड़ते थे। परंतु अब सचिवालयों के निर्माण के बाद पंचायत व ग्रामीण अपने सभी फैसले इन सचिवालयों में बैठ कर ले सकेंगे। सचिवालयों में लोगों के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, कंप्यूटर और सभी दूसरे उपकरण मौजूद रहेंगे। गांवों में सचिवालय बनने के बाद हजारों ग्रामीणों को फायदा मिलेगा।

> **पांच** गांवों में सचिवालय बनाने का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इन सचिवालयों का निर्माण साढ़े तीन करोड़ की लागत से किया जाएगा।
> **-रामपाल, उपमंडल अभियंता पंचायती राज**

डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से होगा तीन गांवों का विकास

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से तिगांव ब्लॉक के तीन गांवों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। ये विकास कार्य तीनों गांवों में स्वच्छ ग्राम योजना के तहत करवाए जाएंगे। विकास कार्य को मार्च 2024 से पहले पूरा करवा लिया जाएगा। गांवों को साफ व बेहतर सुविधा देने के लिए, तिगांव के तीन गांवों में पंचायती राज फरीदाबाद की तरफ से विकास कार्य करवाने का फैसला लिया गया है। जिससे इन गांवों के लोगों को शहरों की तरह सभी सुविधाएं मिल सकें।

पंचायती राज विभाग की तरफ से तिगांव ब्लॉक के गांव सदपुरा, बुआपुर एवं महमूदपुर में ये विकास कार्य करवाने का फैसला लिया गया है। शुरुआत में इन गांवों में 50-50 लाख की लागत से इन गलियों को बनवाया जाएगा। गांवों को सीमेंटिड ब्लॉक से बनाया जाएगा। इसके अलावा गांवों की टूटी गलियों को भी पक्का करवाया जाएगा। सभी गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। जिससे रात के समय गांव पूरी तरह से बिजली की रोशनी में जग-मग रहें। इससे ग्रामीणों को रात में आने-जाने में सुविधा रहेगी। बरसाती व घरों के पानी की निकासी बेहतर ढंग से होगी। जिससे ग्रामीणों को जलभराव से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद भी गांव में दूसरे विकास कार्य भी पंचायती राज्य विभाग फरीदाबाद की तरफ से करवाए जाएंगे। जिससे ब्लॉक के सभी गांव साफ-सुथरे रहें।

> **गांवों** का विकास होने से हमें सुविधा रहेगी, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
> **-संजय अधाना, ग्रामीण**

> **तिगांव** ब्लॉक के तीन गांवों में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से गलियों, नालियों को पक्का किया जाएगा तथा स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा रहे।
> **-राजबीर शर्मा, कनिष्ठ अभियंता पंचायती राज**

एटीएम कार्ड बदलकर 42 हजार निकाले

पलवल। एक ठग ने एटीएम बूथ में धोखाधड़ी से व्यक्ति का डेबिट कार्ड बदलकर उसके खाते से 42 हजार ठग लिए। कैंप थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शमशाबाद में किराए के मकान में रहने वाले कृष्ण कुमार ने कैंप थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी। जिसके लिए, वह अपने एटीएम कार्ड से पांच हजार रुपये निकालने के लिए रेलवे स्टेशन के निकट स्थित एटीएम बूथ में पहुंचा। उसने वहां से पांच हजार रुपए निकाल लिए। उसी दौरान एटीएम बूथ में दो अज्ञात व्यक्ति आकर खड़े हो गए। कृष्ण ने बताया कि जब वह पैसे लेकर जाने लगा तो उन्होंने आवाज लगाकर कहा कि आपका बैंक खाता खुला रह गया है, इसे बंद कर दो। उनके कहने के बाद जब वह बूथ में पहुंचा तो उसने कैंसिल का बटन दबा दिया। इस पर युवकों ने कहा कि मशीन में बिना कार्ड लगाए कैंसिल नहीं होगी।

पलवल के हुडा सेक्टर दो में होग सड़कों का निर्माण

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

हुडा सेक्टर दो में जल्द ही सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए भेजे प्रपोजल को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। सड़कों के बनने के बाद लोगों को सुविधा रहेगी। सेक्टर दो में कुछ जगह पर सड़कें टूट गई थीं। जिनके नव निर्माण के लिए विभाग की तरफ से साठ लाख रुपये की लागत से सड़कों के बनाने का प्रपोजल भेजा गया था।

अब इस प्रपोजल को उच्च अधिकारियों की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही 22 फुट की चौड़ाई वाली इन सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सड़कों को सेक्टर वासियों की मांग पर बनाया जा रहा है। सड़कों को कंक्रीट व तारकोल से निर्मित किया जाएगा। उसके बाद सड़कों पर कॉरपेट भी बिछाया जाएगा। फरवरी 2024 तक सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करा दिया जाएगा।

> **सड़कों** के निर्माण के बाद सेक्टर वासियों को आने-जाने में सुविधा रहेगी। वहीं सेक्टर की सुंदरता में भी इजाफा होगा।
> **-कमलेश, सेक्टरवासी**

> **हुडा** सेक्टर दो की सड़कों का निर्माण 60 लाख की लागत से जल्द ही करवाया जाएगा। जिससे सेक्टरवासियों को सुविधा रहे।
> **-मेहरचंद, उपमंडल अभियंता एचएसवीपी**

सांसदों का निलंबन

कठोर निर्णय

विपक्षी सांसदों का निलंबन संसदीय परंपराओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में पिछले गुरुवार से संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 141 सांसदों का निलंबन देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इससे विपक्षी समूह 'इंडिया' की राज्यसभा में संख्या आधी तथा लोकसभा में एक तिहाई घट गई है। लोकसभा में 78 सांसदों को सोमवार को 'अराजक व्यवहार' तथा 'आसन के निर्देशों की अनदेखी' के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि, सदन में व्यवस्था और गरिमा बनाए रखना जरूरी है, पर सदस्यों के इतने बड़े पैमाने पर निलंबन से आरोपों के समतुल्य प्रतिक्रिया पर बहस स्वाभाविक है। सचमुच संसदीय गरिमा का महत्व है, पर इसके साथ ही सदन का सुचारु कामकाज सरकार के साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अतीत में अध्यक्ष की ओर से विपक्षी सदस्यों को मनाने के लिए परोक्ष उपाय किए जाते थे। इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को वार्ता के लिए आमत्रित किया, पर उनकी बात नहीं मानी गई। आलोचकों और विपक्षी नेताओं को लग सकता है कि सांसदों के निलंबन का निर्णय बहुत कठोर है, लेकिन यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने के पहले ही सभी सदस्यों ने 'असंसदीय' व्यवहार को परिभाषित कर उससे दूर रहने की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन विडंबना है कि इस प्रतिज्ञा को हवा में उड़ा दिया गया है।

लोकसभा का यह अंतिम सत्र से पहले का सत्र है। अत: इसमें अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को विमर्श के लिए रखा गया है जिनका जनता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जनता को उम्मीद थी कि विपक्ष इन पर

समुचित विचार-विमर्श करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसद की सुरक्षा में चूक की एक घटना को लेकर विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के बजाय अपने संकुचित चुनावी हितों को देखते हुए अराजकता पैदा कर संसद का कामकाज ठप करना ज्यादा उचित समझा। अतीत में भी संसद की सुरक्षा में इससे बड़ी घटनायें हुई हैं, पर तत्कालीन विपक्ष ने कभी ऐसी अराजक स्थिति नहीं पैदा की। विडंबना है कि संसद में कुछ अराजक तत्वों की आपराधिक घटना को परोक्ष रूप से उचित ठहराने के लिए कांग्रेस के एक नेता ने इसे बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ने का निन्दनीय प्रयास किया। विपक्ष लगातार संसद में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है और उसकी रिपोर्ट को संसद में रखा जाएगा। संसद की सुरक्षा व्यवस्था संसदीय सचिवालय के आधीन आती है जो सभी सांसदों के सुझावों व संस्तुतियों के आधार पर इसे संचालित करता है। ऐसे में गृह मंत्री द्वारा बयान की मांग पर संसद न चलने देना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि वे हालिया विधानसभा चुनावों में पराजय से हताश हैं और इस घटना को राजनीतिक तूल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा कि संसद में विपक्ष का यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी संख्या और कम हो सकती है। देश की जनता अपने सांसदों के कामकाज पर पैनी नजर रखती है। ऐसे में यदि वे जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के बजाय अपने निहित स्वार्थों या चुनावी राजनीति के चलते संसद का कामकाज ठप करते हैं तो प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सही सिद्ध हो सकती है।

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

जब सरकार विदेशी कंपनियों से खुदरा व्यापारी के सारे काम करने की उम्मीद करती है तो उनको बिक्री के अधिकार से कैसे रोका जा सकता है। सभी प्रकार के खुदरा व्यापार में शत-प्रतिशत एफडीआई को अनुमति मिलनी चाहिए।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

सरकार ई-कामर्स के इन्वेंटरी-आधारित माडलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई की अनुमति देने पर विचार कर रही है, लेकिन इसमें शर्त है कि इसका लक्ष्य केवल निर्यात बाजार होने चाहिए। ई-कामर्स में एफडीआई संबंधी समग्र नीति पर 2018 से विचार-विमर्श जारी है। वास्तव में ई-कामर्स फर्मों के प्रतिनिधियों तथा घरेलू व्यापारिक संगठन, जैसे कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स-सीएआईटी के प्रतिनिधियों से 2 अगस्त, 2023 को विचार-विमर्श हुआ। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग-डीपीआईआईटी ने प्रस्तावित ई-कामर्स नीति पर 'मूलाधारों' का एक प्रस्तुतीकरण किया। इस पृष्ठभूमि में टुकड़ों-टुकड़ों में कदम बढ़ाने तथा ई-कामर्स फर्मों को केवल निर्यात बाजारों तक सीमित करने की विशेष व्यवस्था से विसंगतियां पैदा होती हैं। यदि सरकार ऐसे विभाजन को उचित मानती है तो भी इसे ई-कामर्स के एक 'समग्र' पैकेज का अभिन्न अंग होना चाहिए। ई-कामर्स वस्तुओं व सेवाओं को इंटरनेट पर बेचने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2016 के प्रारंभ में सरकार ने तथाकथित मार्केटप्लेस माडल के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी। मार्केटप्लेस ऐसा प्लेटफार्म है जहां वेंडर अपने उत्पाद ग्राहकों को बेचते हैं, भले ही इसका स्वामी एक फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करता है। वह आर्डर बुक करने, इन्वायस बनाने, डिलीवरी का प्रबंध करने, आदि सेवायें देता है, पर वह इन्वेंटरी पर नियंत्रण करने या प्रत्यक्ष बिक्री जैसे काम नहीं कर सकता है। इस नीति का इरादा पूर्णत: स्पष्ट था। मार्केटप्लेस में विदेशी निवेशक को इन्वेंटरी माडल में निवेश की अनुमति नहीं थी। एक विदेशी निर्माता को भारत में निर्मित अपने उत्पाद ई-कामर्स खुदरा के माध्यम से बेचने की अनुमति है। ई-कामर्स में एफडीआई प्रवाह का एक और रास्ता सिंगल ब्रांड में खुदरा बिजनेस-एसबीआर में व्यापार करना है जिसके लिए उसे भौतिक स्टोरों का प्रबंध करना होगा। यह स्थिति बहु-ब्रांड खुदरा-एमबीआर या सरल भाषा में केवल 'खुदरा' से अलग है। दोनों माडलों के बीच नीतिगत रूप से स्पष्ट विभाजन के बावजूद जिनमें से एक में एफडीआई की अनुमति थी और दूसरे में सीधे बिक्री की अनुमति थी, यह लागू नहीं हुआ। डीपीआईआईटी के किसी चालाक नौकरशाह ने नीतिगत दस्तावेज के विस्तृत विवरण में इसे गायब कर दिया। प्रेसनोट 3 में दो शर्तों की बात की गई। पहला, मार्केटप्लेस के स्वामी को मार्केटप्लेस में कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से अधिक एक वेंडर या कंपनियों के समूह से लेने की अनुमति नहीं थी और दूसरा, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता था।

वेंडर को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण ऐसी कंपनी के लिए रास्ता खुल गया जो मार्केटप्लेस की स्वामी हो। वह सहायक या जेवी के रूप में चार कंपनियां बना कर प्रत्येक की प्लेटफार्म पर बिक्री का 25 प्रतिशत नियंत्रित कर सकता था। इस प्रकार जहां नीतिगत रूप से विदेशी निवेशकों को इन्वेंटरी माडल या प्रत्यक्ष बिक्री में निवेश की अनुमति नहीं थी, वास्तव में इसका उल्टा होने लगा। उसके उद्यमों को मार्केटप्लेस की लगभग सारी बिक्री सुनिश्चित करने की अनुमति देने से दूसरी शर्त भी हास्यास्पद हो गई जिसके चलते वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिक्री मूल्य प्रभावित नहीं कर सकता था। अमेजन, वाल्मार्ट, फ्लिपकार्ट आदि विशाल ई-कामर्स कंपनियों के पिछले दरवाजे से सीधी बिक्री में प्रवेश के कारण सर्वाधिक प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों-एमएसएमई ने इसकी सरकार से शिकायत की। इसके जवाब में 26 दिसंबर, 2018 को डीपीआईआईटी ने स्पष्ट किया कि 'मार्केटप्लेस या भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम-जेवी या सहायक कंपनी वाला स्वामी विक्रेता का स्वामी नहीं हो सकता है।' इसके साथ ही 'प्लेटफार्म पर कोई विक्रेता अपनी 25 प्रतिशत से अधिक इन्वेंटरी को प्लेटफार्म स्वामी से नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन विदेशी निवेशक पहली शर्त का उल्लंघन इस आधार पर कर सकते हैं कि उनका विक्रेता फर्म में हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक न हो, ताकि वे कह सकें कि उनका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मार्केटप्लेस का स्वामी प्लेटफार्म पर अपनी थोक शाखा के माध्यम से 'अपने' उत्पाद बेच सकता है।

इसके लिए केवल थोक शाखा को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह विक्रेता को अपनी सप्लाई 25 प्रतिशत की सीमा में रखे। यह केवल सीमाओं को धुंधली करने का मामला नहीं है। आधिकारिक नोट में मार्केटप्लेस के स्वामी व विक्रेता के बीच संबंध को स्वीकार कर उसे वैधता प्रदान की गई है। इससे विदेशी कंपनियों को इन्वेंटरी रखने तथा ग्राहकों को सीधी बिक्री पर लगाम नहीं लगती है। वे यह काम लाखों छोटे व्यापारियों की कीमत पर करते हैं। उदाहरणार्थ, अमेजन प्लेटफार्म पर 400,000 विक्रेताओं में से केवल तीन दर्जन फर्में ही कुल बिक्री का 67 प्रतिशत करती हैं।

इस बीच 2020-2021 में उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामलों के विभाग-डीसीए ने उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण ई-कामर्स नियम जारी किए। इन नियमों के अंतर्गत संबंधित उद्यमों द्वारा ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर बिक्री को प्रतिबंधित कर ई-कामर्स में बिजनेस-टु-बिजनेस बिक्री को सीमित किया गया। इसके साथ ही 'फ्लैश सेल्स' को सीमित कर ई-कामर्स फर्मों द्वारा 'प्रभुत्वकारी स्थिति के दुरुपयोग' पर रोक लगाते हुए मार्केटप्लेस ई-कामर्स उद्यमों द्वारा वस्तुओं के प्रोत्साहन में उनके नाम या ब्रांड के प्रयोग पर रोक लगाई गई।

प्रेसनोट 3 के संदर्भ में देखने पर यह लफ्फाजी के सिवा और कुछ नहीं है। इसके साथ ही नियामक अधिकारी तथा संस्थागत व्यवस्थाओं की अनुपस्थिति में विदेशी फर्मों के कामकाज पर नियंत्रण लगाना तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करना असंभव है। अब वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी अमेजन जैसी बड़ी ई-कामर्स कंपनियों को उस नियम से बाहर करना चाहते हैं जो 'मार्केटप्लेस स्वामी को इन्वेंटरी रखने से प्रतिबंधित करता' है, यदि इस उत्पाद को निर्यात बाजार में बेचना हो। मजेदार बात है कि व्यवहार में यह नियम कभी घरेलू खुदरा बिक्री के मामले में लागू नहीं किया गया, जिसका कारण नौकरशाहों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली है। फर्मों को इन छूटों का लाभ दिलाने के लिए कुछ शर्तें लगाने पर विचार हो रहा है, जैसे निर्यात के लिए इन्वेंटरी अलग रखना तथा कस्टम से जुड़ा गोदाम पूरी तरह डोमेस्टिक टैरिफ एरिया-डीटीए व अन्य बाजारों से अलग रखना शामिल है। इसके पीछे इरादा यह है कि निर्यात के लिए चयनित उत्पाद पुन: डीटीए में प्रवेश न कर सके।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नियमों की इस भूलभुलैया को कौन लागू करेगा? मूलभूत रूप से मार्केटप्लेस स्वामियों को निर्यात के क्षेत्र में अलग स्थान दिया जाना चाहिए। मंत्रालय का तर्क है कि इससे घरेलू उत्पादकों, जैसे किसानों, छोटे कारीगरों तथा उत्पाद के स्वामियों को विदेशी बाजारों में पहुंचना संभव होगा। लेकिन यह तर्क स्वीकार करना आसान नहीं है। पहला, एमएनसी लगातार विस्तारित होते भारतीय बाजार के अवसरों का लाभ उठाना चाहती हैं और अब तक हमारे नीति-निर्माताओं ने नियमों को अनुकूल बना कर उनकी सहायता की है। दूसरा, एमएनसी ने एमएसएमई को घरेलू बाजार में बिक्री में सहायता नहीं की है। ऐसे में उनसे निर्यात की आशा कैसे की जा सकती है। सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी ई-कामर्स कंपनियों की सहायता लेने का प्रस्ताव छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय उसे वर्तमान अव्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। मार्केटप्लेस का विचार ही गलत है।

जब सरकार विदेशी कंपनी से खुदरा व्यापारी के सारे काम करने की उम्मीद करती है तो वह उसे बिक्री करने के अधिकार से कैसे रोक सकती है। इसमें आर्डर बुक करना, इन्वायस तैयार करना, डिलीवरी की व्यवस्था करना, अस्वीकृत माल स्वीकार करना, आदि शामिल हैं। आगे बढ़ने का रास्ता यह विचार छोड़ कर खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देना है। नौकरशाहों ने यह काम पहले ही 'परोक्ष' रूप से कर दिया है। सरकार को यही काम स्पष्ट रूप से करना चाहिए। इसके साथ ही समानता स्थापित करने के लिए सभी खुदरा व्यापारियों, आनलाइन या आफलाइन को, छोटे या बड़े को 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देनी चाहिए।

सच्चे विकास का पैमाना

> "विकास को मापने के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां ही एकमात्र मानदंड नहीं हैं।"

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

भारत सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, वह पहले ही उठ चुका है। इसकी अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है... हम विश्व मंच पर भारत की बड़ी भूमिका की आशा करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता 'द यूएस प्रेसिडेंट' के इस बयान ने दुनिया भर के साथ-साथ भारत में भी खूब चर्चा बटोरी। भारत में जी20 शिखर सम्मेलन में एकत्र हुए अधिकांश विश्व नेताओं ने इसी प्रकार की भावनाएँ व्यक्त कीं। हालाँकि, आत्मनिरीक्षण करने पर, यदि कोई सोचता है तो मन में यह प्रश्न आता है कि %क्या हम उठ गए हैं?% यदि हाँ तो किस हद तक? क्या हम केवल वैज्ञानिक, तकनीकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण और ढांचागत विकास देखकर खुश हैं? क्या यही हमारी प्रगति का पैमाना है? हम कैसे मापें कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस युग में हम आगे बढ़ गए हैं?

इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञान हमारे लिए एक अद्भुत उपलब्धि रही है। लेकिन, हममें से कितने लोग इस तथ्य से अवगत होंगे कि इस विकास रथ के नीचे, हमारी असली दौलत दबी पड़ी है? क्या हमें यह एहसास नहीं है कि हमारी आध्यात्मिकता और हमारे मूल्य सभी भौतिकवाद के नीचे दबे पड़े हैं? याद रखें, हमारी दुनिया केवल जीवन के भौतिक पहलू तक ही सीमित नहीं है, इसमें मनोविज्ञान, आत्मा, आंतरिक स्व है जिसके साथ हम पहचान करते हैं।

आज हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं? वह क्या है जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है? दुर्भाग्य से, विज्ञान हमें इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें भौतिक रूप से समृद्ध लेकिन आध्यात्मिक रूप से गरीब बना दिया है। हमारा मन थका हुआ है, हमारी आत्माएं दुख रही हैं और इसलिए हमें खुद को

आध्यात्मिक रूप से चार्ज करके अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुन: प्राप्त करने की आवश्यकता है।

दुनिया में ज्ञान या विचारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें ज्ञान को जानने के बजाय उसका अनुभव करना होगा। विज्ञान के युग का तात्पर्य केवल प्रौद्योगिकी से नहीं है; यह दृष्टिकोण, जीवनशैली और जीवन के संपूर्ण दर्शन को भी संदर्भित करता है। वर्षों के विकास के साथ, हमने मछली की तरह समुद्र में तैरना और पक्षियों की तरह महाद्वीपों में उड़ना सीख लिया है, लेकिन अब हमें इंसानों की तरह धरती पर चलना सीखना होगा।

आज वही वैज्ञानिक जो दिन भर अपनी प्रयोगशालाओं में व्यस्त रहते थे, भौतिकी से तत्वमीमांसा की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि वे वास्तविकता जानना चाहते हैं। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम असेंबली लाइन पर निर्मित प्रोटोटाइप नहीं हैं; हम सभी व्यक्तिगत व्यक्तित्व हैं जिनकी अपनी पहचान हमारे मूल्यों, व्यक्तित्व लक्षणों और तौर-तरीकों के आधार पर होती है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता और शिक्षकों द्वारा दिए गए मूल्यों का एक निश्चित समूह रखता है। हालाँकि हमें यह याद रखना चाहिए कि मूल्यों को जाना या सिखाया नहीं जा सकता, आपको उन्हें आत्मसात करना होगा। हमारे पास मूल्यों की एक लंबी सूची हो सकती है लेकिन मूल रूप से मूल्य वह है जिसके लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं।

पूरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति को मूल्यों को व्यावहारिक रूप से अनुभव करने और स्वयं को प्रबुद्ध करने की आवश्यकता है। जरा कल्पना करें, यदि किसी को यह एहसास हो जाए कि एक परिष्कृत व्यक्ति पूरे वातावरण को उन्नत और आलोकित कर सकता है, तो वह दृश्य क्या होगा जब हर व्यक्ति मूल्यों से परिष्कृत होगा? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता?

इसलिए, अपने आप को उस निहाई के रूप में समझें जिससे चिंगारी निकलनी चाहिए जो आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करती है और जीवन के प्रति सम्मान, करुणा, ज्ञान और ईमानदारी के मूल्यों को सभी तक पहुंचाती है क्योंकि जितना अधिक हम अपने मूल्यों को साझा करते हैं, उतना अधिक यह जितना अधिक बढ़ता है।

आप की बात

अपराधी घोषित ट्रंप

कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने विद्रोह में शामिल होने के अपराध में राज्य के प्राथमिक मतदान से डोनाल्ड ट्रम्प पर प्रतिबंध लगाने का असाधारण कदम उठाया है। न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी संविधान के विद्रोह खंड के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें राज्य के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से भी हटा दिया। वहां के बैलेट पेपर में उनका नाम अब नहीं छपेगा। अमेरिकी कानूनविद इसे असाधारण एवं कड़ा फैसला बतला रहे हैं। 6 जनवरी, 2021 को लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले कैपिटल हिल में उग्र राष्ट्रवादियों ने जिस तरह तोड़फोड़ की थी वो अमेरिकी इतिहास में अपने किस्म की पहली घटना थी। स्पष्ट था कि इस आक्रमण के पीछे डोनाल्ड ट्रम्प एवं उनके भाषणों एवं विचारों का प्रभाव था। फैसले के अनुसार, अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रम्प 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के अयोग्य हैं। हालांकि, ट्रंप के वकील इस फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने जनादेश का अपहरण करने का प्रयास कर अमेरिकी लोकतंत्र पर सर्वाधिक घातक प्रहार किया था और शायद वे एक तानाशाह बनना चाहते थे।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

सांसदों का व्यवहार

संसद पर हुए हमले की वर्षगांठ पर फिर से संसद में दशहत फैलाने का प्रयास किया गया। इसको लेकर सांसद पिछले कई दिनों से ठप्प पड़ी है तथा 100 से अधिक सांसदों को निलंबित करना पड़ा है। इसका कारण सांसदों द्वारा फैलाई जा रही अराजकता है। आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन किया गया। शशि थरूर के अनुसार, सांसद ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उन्हें निलंबित किया जाए ताकि वह सुर्खियां बटोर सकें और जनता की सहानुभूति उन्हें मिल सके। लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है कि सदन में हुए हमले पर चर्चा करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है और सरकार वैसे भी उचित कार्रवाई कर रही है। स्पष्ट है कि विपक्ष सरकार से तकरार कर राजनीतिक लाभ उठाने को प्रयासरत है। विडंबना है कि जब संसद में हुडदंग के कारण कोई काम नहीं होता और अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस के पास हो जाते हैं तो विपक्षी सांसद अपने मतदाताओं को क्या जवाब देंगे? बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर संसद में हमला करने वालों को उचित ठहराना भी किसी प्रकार ठीक नहीं है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

कमलनाथ की विदाई

कांग्रेस ने विधानसभा में करारी हार के बाद अब कमलनाथ को हटाकर नया अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया है। जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, पर इसके बाद भी कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है। चुनाव नतीजों में करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने एक नया युवा अध्यक्ष बनाया है। लगता है कि कांग्रेस अपनी हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरना चाहती है। देखना होगा कि यह फेरबदल क्या रंग लाता है। पार्टी शायद अब नई पीढ़ी को अवसर देकर आगे बढ़ना चाहती है। यह सही भी है क्योंकि जब भाजपा ने तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री बनाए तब कांग्रेस को भी लगा कि यही रास्ता ठीक है। लेकिन जीतू पटवारी को लोकसभा चुनाव में घनघोर मोदी लहर का सामना करना पड़ेगा। आज मोदी की लहर के साथ मोदी की गारंटी भी चल रही है तब देखना होगा कि कांग्रेस कहां तक सफल होती है। मीडिया सर्वेक्षणों में भाजपा को साढे 350 से ऊपर सीट बताई जा रही है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को 150-160 तक समेट दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि प्रयोग का क्या फल मिलता है।

–**मनमोहन राजावत,** शाजापुर

टीबी मुक्ति अभियान

टीबी के इलाज में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गत दशकों में बड़ी प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर काम किया है। इसके लिए सभी हॉस्पिटलों में एक अलग से शाखा रखी गई है। इसमें मरीज की जांच, एक्स-रे, इलाज व दवाइयां निशुल्क वितरित की जाती है। टीबी विभाग के कर्मचारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों की नियमित यात्रा कर वहां मरीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं और टीबी की आशंका वाले मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र पर लाकर उसके निशुल्क पूर्ण इलाज की व्यवस्था की जाती है। टीबी के इलाज में डॉक पद्धति आ जाने के बाद से लोगों को जल्दी आराम होने लगा है। भारत सरकार ने दो साल में टीबी से मुक्ति का लक्ष्य सामने रखा है। चेचक, पोलियो और अब टीबी से मुक्त होना देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विगत वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति के साथ ही आज पीएचसी, सीएचसी व जिला अस्पतालों को निजी अस्पतालों की तरह ही जनता के आकर्षण का केन्द्र बनाने की बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए जन-जागरूकता भी जरूरी है।

–**विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

योजनाओं के लाभ से लोगों का वंचित होना लोकतंत्र पर था गंभीर प्रश्नः मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी यदि नागरिक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित थे तो यह लोकतंत्र पर गंभीर प्रश्न था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस बात का संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र को प्राप्त होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला का समवेत रूप है।

योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थी इस यात्रा में अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सीएम योगी बुधवार शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के समीप आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सुनने, सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का अनुभव (मेरी कहानी-मेरी जुबानी) सुनने और

● गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके तहत जो लोग भी किन्ही कारणवश योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, एलईडी बल्ब वितरण योजना, आयुष्मान भारत योजना, हर घर नल से जल योजना, जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना जैसी अनेक योजनाएं करोडों लोगों की जीवन में खुशहाली का माध्यम बनी हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर हम सबको 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के पीएम मोदी के संकल्प में अपना योगदान देना है।

मोदी के नेतृत्व में मिली गांव-गरीब को ताकतः नड्डा

गोरखपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पीएम पद संभालने के ससाथ ही कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब, महिलाओं, नौजवानों व किसानों को समर्पित रहेगी। सारी योजनाओं के केंद्र में भी उनका यही ध्येय है। पीएम मोदी के नेतृत्व में गांव-गरीब को ताकत मिली है। महिलाएं सशक्त हुई हैं, युवाओं को आवाज मिली है, किसानों को सहजता से आगे बढ़ने और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर आगे बढ़ने का अवसर मिला है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवम्बर को भगवान विरसा मुंडा के जन्मस्थान से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। 25 जनवरी 2024 तक यह यात्रा देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक ढाई हजार वैन के माध्यम से पहुंचेगी। यूपी में 57 हजार गांवों तथा छह सौ से अधिक निकायों तक यात्रा पहुंचकर उन लोगों को भी लाभान्वित करेगी जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि यात्रा में अपनी कहानी सुनाते हुए लाभार्थी भावुक हो जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले उनकी तकलीफ पर कभी किसी सरकार ने मरहम नहीं लगाया था।

यूपी के हर गांव में होगा खेल का मैदान व एक ओपन जिमः योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सांसद खेलकूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। यह हमारे युवाओं को अपनी ताकत और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे आयोजनों के माध्यम से देश में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हर एक जनपद में एक-एक खेल का सेंटर बनाने की कार्रवाई भारत सरकार के माध्यम से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा। हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी सामर्थ्य का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर हमारे

● सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बस्ती में किया सांसद खेलकूद महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ

खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को बस्ती जनपद में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 के शुभारंभ के अवसर पर कहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का उत्तर प्रदेश आगमन पर स्वागत भी किया।

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी भी बनाया गया है तो नायब तहसीलदार का पद भी दिया गया है। साथ ही पुलिस की अलग-अलग श्रेणी में भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेल कोटे के अंदर 500 नए पद निकल रहे हैं। खेल कोटे में 2 फ ीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। जो खिलाड़ी वैश्विक प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करेगा, सरकार उसको सरकारी नौकरी भी देगी और आजीवन उसके भरण पोषण की भी व्यवस्था करेगी।

उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उन्हें बधाई और जिन्होंने प्रयास किया है वो और अच्छा प्रयास करेंगे तो उन्हें अगले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ.साथ प्रदेश में अलग-अलग खेलों की लीग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। सीएम योगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बस्ती के बीच संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि बस्ती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष संबंध है। ये जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, यह आपको तभी प्राप्त हुआ था जब नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे।

उपराष्ट्रपति के प्रति विपक्ष का आचरण असंसदीय, अशोभनीय व अक्षम्यः योगी

● राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष के व्यवहार की मुख्यमंत्री ने की निंदा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रति व्यवहार को सीएम योगी ने असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण करार दिया है। विपक्ष के इस व्यवहार की सीएम योगी ने निंदा की है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति विपक्ष का असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण अलोकतांत्रिक होने के साथ ही उनके कुसंस्कारों को भी दर्शाता है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति अहंकार और विद्वेष से परिपूर्ण यह कृत्य अत्यंत ही शर्मनाक है। संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं।

मुख्यमंत्री आज लेंगे राममंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या के विकास का जायजा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लगभग साढ़े चार घंटा अयोध्या में रहेंगे। योगी यहां रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही उनका यहां दर्शन-पूजन का भी कार्यक्रम है। इससे पहले मुख्यमंत्री 2 दिसम्बर को अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करने केन्द्रीय मंत्रियों के साथ आए थे। इस माह में मुख्यमंत्री का दूसरी बार अयोध्या आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से लगभग 11 बजे रामकथा हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से सबसे पहले वे हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे यहां हो रहे मंदिर निर्माण और अन्य विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी सर्किट हाउस में अल्प प्रवास के बाद आयुक्त कार्यालय में दोपहर 1:30 बजे विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे तथा अगले चरण में संतों के साथ बैठक कर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

अयोध्या की सड़कों पर तमिल, तेलुगू में भी लगाई जाएंगी निर्देश पट्टिकाएंः एडीजी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ अयोध्या

अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए मार्गों पर निर्देश पट्टिका लगाई जाएंगी। देश के विभिन्न भागों से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए यहां अलग अलग भाषाओं में पट्टिका लगाई जाएंगी।

इनमें दक्षिण की तमिल, तेलुगू जैसी बडे पैमाने पर बोली जाने वाली भाषाओं में भी पट्टिकाएं होंगी। यह जानकारी अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन पियूष मोर्डिया दी। उन्होंने बताया कि प्रमुख मंदिरों की तरफ जाने वाले

● मार्गों की आवश्यकता के अनुरूप प्लान तैयार कर रही पुलिस

मार्गों को चिन्हित कर उन मार्गों पर यथासंभव यथा आवश्यकता के अनुसार श्रद्धालुओं के चलने के लिए योजना बनाई गई है।

जिस मार्ग से पैदल यात्री जा सकें, उन मार्गों पर वाहनों को जाने से रोका जाएगा। यह भी निर्धारित किया जा रहा है कि जहां पर वाहनों के आने की आवश्यकता है, वहां वे इस प्रकार से आएं कि अन्य लोगों का आना-जाना बाधित न हो। मार्गों की आवश्यकता के अनुरूप प्लान तैयार किया जा रहा है।

कुछ मार्गों पर ई-रिक्शा को बैन भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अयोध्या के मार्गों पर अलग अलग भाषाओं में निर्देश पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में दिक्कत न हो। खासकर दक्षिण के राज्यों की भाषाओं में निर्देश पट्टिकाएं भी होंगी।

प्रदेश में पारदर्शी प्रक्रिया से मक्का किसानों को किया गया 897.54 लाख का भुगतान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मक्का की खरीद जारी है। एक अक्टूबर से अब तक 4354.45 मीट्रिक टन मक्का की खरीद हो चुकी है। योगी सरकार ने किसानों के लिए मक्का का समर्थन मूल्य 2090 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। योगी सरकार के कुशल प्रबंधन और पारदर्शी प्रक्रिया से मक्का किसानों को 897.54 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है।

कानपुर संभाग में 22 क्रय केंद्रों से 2153.50 मीट्रिक टन और अलीगढ़ संभाग में अब तक 20 क्रय केंद्रों से 687.70 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है। लखनऊ में सात क्रय केंद्रों से 535.70 मीट्रिक टन, आगरा में 8 क्रय केंद्रों से 485.35 मीट्रिक टन, मेरठ संभाग में पांच क्रय केंद्रों से 245 मीट्रिक टन और आजमगढ़ में चार क्रय केंद्रों से 169

● 2090 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है मक्का का समर्थन मूल्य

मीट्रिक टन मक्का की खरीद की जा चुकी है। अन्य संभागों में भी तेजी से मक्का खरीद जारी है। केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार निरंतर ही किसानों के विकास पर कार्य कर रही है। किसानों से जुड़ीं अनेक योजनाएं उन्हें सम्मान के साथ स्वावलंबी बनाने की तरफअग्रसर हैं। सिर्फ मक्का की ही बात करें तो अब तक 897.54 लाख का भुगतान किया जुका है। सर्वाधिक भुगतान कानपुर संभाग के किसानों को किया गया है। यहां 385 किसानों को अब तक 450.08 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। वहीं अलीगढ़ के किसानों को 142.97 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

संकल्प और साधना के माध्यम से देना चाहिए अपने कार्य को गतिः दुर्गा शंकर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सातवीं कार्यक्षमता वृद्धि व्याख्यानमाला आयोजित की गई। व्याख्यानमाला में नई दिल्ली स्थित गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल के स्ट्रेस मैनेजमेंट एण्ड कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर मोहित गुप्ता ने 'तनाव मुक्त जीवन, संकल्प एवं साधना से सिद्धि' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्षमता वृद्धि व्याख्यानमाला में ख्याति प्राप्त महानुभावों से सचिवालय कर्मियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम सभी को तनावमुक्त जीवन जीना चाहिए। संकल्प और साधना के माध्यम से अपने कार्य को गति देना चाहिए। मुश्किल घड़ी से निकलकर खुशहाल जिदंगी जीना चाहिए। हम प्राचीन जीवन पद्धति को भूल गए थे। कोविड के बाद से आम नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। आज विश्वभर में लोग योग अभ्यास से

● मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ सातवीं कार्यक्षमता वृद्धि व्याख्यानमाला का आयोजन

लाभान्वित हो रहे हैं। योग से हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, इसमें सभी का अहम रोल है। हम सभी को बिना तनाव लिए अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निष्पादन करना चाहिये। सकारात्मक रहें और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। इससे पूर्व, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल के स्ट्रेस मैनेजमेंट एण्ड कार्डियोलॉजी विभाग के प्रो. मोहित गुप्ता ने कहा कि तनावमुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए नकारात्मक विचार अपने मन में न आने दें। नकारात्मतक विचार हमारे मन में नहीं रहते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं। हमारे

संकल्पों में शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब यह जानते हैं कि तनाव लेने से सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित होती है लेकिन फिर भी रोजाना हम किसी न किसी बात का तनाव लेते हैं। रूटीन को फॉलो करने से आपका जीवन बेहतर होगा। इससे आपको अपने शौक पूरे करने का भी समय मिलेगा, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अपनी रुटीन में सुबह जल्दी उठने को शामिल करें। यह न केवल आपके शरीर बल्कि दिमाग के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से एक्टिव रहना एक स्ट्रेस रिलीवर है। इससे न केवल आपमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी। इसलिए वॉक, जॉगिंग, गार्डनिंग, स्विमिंग या जो भी आपको पसंद हो, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन और योगा को स्ट्रेस से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका है। मेडिटेशन और योगा से दिमाग से नेगेटिव और स्ट्रेसफुल विचार बाहर निकल जाते हैं, जिससे आप रिफ्रेश और पॉजिटिव महसूस करते हैं। इसके साथ ही सकारात्मक रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं, इससे भी आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। इस दौरान एसजीपीजीआई के हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य कपूर ने आकस्मिक कार्डिएक अरेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सीपीआर देने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष कार्डियक अरेस्ट से करीब 7 लाख मौतें होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग इसके लक्षण और बचाव के तरीकों को नहीं जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट होने के शुरुआती पांच मिनट सबसे क्रिटिकल होते हैं।

जू में कर्मचारियों की सुरक्षा के बेहतर प्रबंध करेंः डॉ. अरुण सक्सेना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरूण कुमार सक्सेना ने बुधवार की सुबह नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान (लखनऊ जू) का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वन्यजीवों के बाड़ों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक चौबंद करने के निर्देश दिये। यह भी कहा

● मृतक सूरज की पत्नी को संविदा पद नौकरी देने के लिए निदेशक जू को दिए निर्देश

कि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ कर्मचारियों की भी सुरक्षा के बेहतर प्रबंध सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना भविष्य में घटित होने पाये अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। मंत्री डॉ. सक्सेना ने विगत दिनों चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े के हमले में मृतक सूरज की पत्नि को संविदा पद नौकरी देने के लिए निदेशक जू को निर्देश दिये। डब्ल्यूटीआई एवं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एजेन्सियों एवं लेबर डिपार्टमेंट से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर में साफ-सफाई के बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जू में स्थित सभी बाड़ों का निरीक्षण करते हुए कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनी बैरीकेटिंग को चुस्त.दुरूस्त कराया जाये। कहीं से कोई बैरीकेटिंग क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। मंत्री डॉ. सक्सेना ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ इनकी देख.भाल में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति बेहद संवेदनशील है। उन्होंने की विशेषज्ञों की देख-रेख में ही कर्मचारियों को बाड़े में जाने की अनुमति दी जाये और दरियाई घोड़े के उग्र होने की जांच चिकित्सक से कराई जाय। साथ ही समय-समय पर सभी वन्यजीवों का चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता रहे।

यूपी में नहीं बढ़ेंगी शराब की कीमतें, बढ़ेगा आबकारी का राजस्वः एक्साइज कमिश्नर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्य के एक्साइज कमिश्नर (आबकारी आयुक्त) सेंथिल पांडियन सी. ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की नई आबकारी नीति लागू होने के बाद प्रदेश में न सिर्फ कंट्री मेड शराब की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि सरकार के खजाने को भी समृद्ध किया जा सकेगा। सेंथिल पांडियन सी. ने नई आबकारी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कंट्री मेड शराब की विभिन्न कैटेगरीज को संक्षिप्त करते हुए इन्हें अब केवल चार हिस्सों में बांटा गया है। पहले ये नौ श्रेणियों में होती थीं और इनके दाम भी अलग अलग होते थे। उन्होंने बताया कि शराब की कीमतों में कमी लाने का सबसे बड़ा कारण यूपी में ग्रेन अल्कोहल को बढ़ावा देने की नीति है। इससे प्रदेश की दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म हुई

● नई नीति से 2024-25 में 50 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य

है और राजस्व को भी फायदा मिल रहा है। एक्साइज कमिश्नर के अनुसार सरकार शीरे वाली शराब की जगह ग्रेन (अनाज) वाली शराब को बढ़ावा दे रही है। दुनियाभर में ग्रेन अल्कोहल को सबसे ज्यादा क्वालिटी युक्त माना जाता है। पहले हमें ग्रेन अल्कोहल को पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से इम्पोर्ट करना पड़ता था, वहीं अब इनका निर्माण प्रदेश में ही हो रहा है। ऐसे में इम्पोर्ट ड्यूटी तो बच ही रही है, जीएसटी में भी कमी आई है, साथ ही लाइसेंस फीस का भी 254 रुपए प्रति बल्क लीटर निर्धारण करने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा मिनिमम गारंटी कोटा और मिनिमम गारंटी रेवेन्यू में 10 प्रतिशत का इजाफा करने से 2024-25 में 50 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य है। बावजूद इसके शराब के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि ग्रेन अल्कोहल और यूपीएमल की शराब की 42.8 डिग्री वाली मदिरा पहले जहां 90 रुपए की मिलती थी उसके दाम घटकर 85 रुपए हो जाएंगे। वहीं यूपीएमएल की शराब में 36 डिग्री वाली मदिरा नई श्रेणी के रूप में जोड़ी गई है, जिसकी कीमत को 75 रुपए रखी गई है। इसके अलावा शीरे वाली शराब को भी केवल दो कैटेगरी में रखा गया है। इसमें 25 डिग्री की कीमत 50 रुपए और 36 डिग्री की कीमत 70 रुपए रखी गयी है।

अब वैध रूप से परमिट रूम में पी सकेंगे बीयर

इसके साथ ही प्रचलित व्यवस्था के प्राविधानों में दुरुपयोग रोकने के भी तमाम प्रयास किए गए हैं। इनमें बीयर की दुकानों के पास 100 स्क्वायर फीट के स्थान को परमिट रूम के तौर पर डेवलप किया जा सकेगा। इसकी परमिशन लेने की फीस 5 हजार रुपए सालाना शुल्क होगी। परमिट रूम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ठंडी बियर को बियर की दुकानों के पास ही पीने की सुविधा मिल सकेगी। इससे सड़क पर या कहीं कोने में अवैध रूप से बीयर पीने से होने वाली असुविधा और कई बार सड़क पर छेड़खानी, मारपीट जैसे अपराधों और अन्य असुविधाजनक स्थिति से बचा जा सकेगा।

चार एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे 26 चार्जिंग स्टेशन, मिलेंगी कई और सुविधाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश की पहचान अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में बन चुकी है। प्रदेश में अभी 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं जबकि 7 निर्माणाधीन हैं। योगी सरकार अब प्रदेश के चार बड़े एक्सप्रेस-वे पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। यूपीडा की तरफ से इसे लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

इसके अंतर्गत बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कुल 26 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन्हे प्रदेश की ईवी पॉलिसी और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुरूप तैयार किया जाएगा। वहीं इसके अलावा एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार अन्य यात्री सुविधाओं को भी डेवलप करेगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी

● प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 साल की लीज पर सरकार देगी 2 हजार वर्गफुट जमीन

(यूपीडा) की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इससे संबंधित एक विस्तृत कार्ययोजना को प्रस्तुत किया गया है। वहीं इससे पहले प्री-बिड मीटिंग में 11 कंपनियों की ओर से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने के लिए रुचि दिखाई गई है।

इसमें रिलायंस, जीएमआर एनर्जी, अडानी टोटल एनर्जी, बेलेक्ट्रिक, लाइट जिप टेक्नोलॉजी, ईवी प्लेक्सस, सिमेन्स लिमिटेड, कैश और ड्राइव, एएम एंड सीई ई मोबिलिटी, एम्पवोल्ट्स और रैज एंड शाइन कंपनियों की तरफ से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के निर्माण में रुचि दिखाई गई है। योगी सरकार की ओर से 26 चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रति स्टेशन 2 हजार वर्गफुट की जगह 10 साल के लीज पर दी जाएगी। चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर को दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया और ई बस की चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जर स्थापित करना होगा। साथ ही सुरक्षा के लिए भी सरकार के मापदंडों का पालन करना होगा। जमीन मुहैया कराए जाने के 180 दिन के अंदर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को क्रियान्वित करना होगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के 5 साल बीतने पर छठे साल से सरकार को प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन के सकल राजस्व में से 5 प्रतिशत प्राप्त होगा। इसके अलावा योगी सरकार बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे वे-साइड एमिनिटीज भी विकसित करेगी। इन्हें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर (डीबीएफओटी) के आधार पर विकसित किया जाएगा।

बलवन्त काण्ड में आज होगी सुनवाई

कानपुर देहात। बहुचर्चित बलवन्त हत्यकाण्ड में आरोपियों के विरुद्ध आरोप विरचित करने के विन्दु पर सुनवाई के मध्य बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखने हेतु एक दिन के समय की याचना विचारण न्यायालय से की जिस पर न्यायालय ने इस विन्दु पर सुनवाई और आरोप विरचित करने हेतु 21 दिसम्बर की तिथि नियत करने का आदेश पारित कियाएयह जानकारी वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने दी उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला जज कक्ष संख्या पांच दुर्गेश की न्यायालय में चल रही है। बताया कि पूर्व में एक आरोपी शोनू यादव की हिपेटाइटिस की बीमारी के इलाज हेतु जिला कारागार से जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने की सुचना जिला कारागार अधीक्षक द्वारा न्यायालय में भेजे जाने और अन्य 6 आरोपियों द्वारा अभी तक अपना अधिवक्ता नियुक्त न करने के कारण केश में आरोपियों के विरुद्ध आरोप विरचित होने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी थी और आरोप विरचित करने की अगली तिथियां नियत करने के आदेश के साथ आरोपी शोनू यादव की बीमारी के सम्बंध में जिला चिकित्सालय के सीएमएस से आख्या तलब करने का निर्देश न्यायालय ने दिया था।20 दिसम्बर नियत तिथि पर सभी आरोपीगण तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशान्त गौतम तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पाण्डे सहित आठ पुलिस कर्मी जेल से न्यायालय में पेश किए गए। जितेन्द्र चौहान ने बताया कि आरोपी शोनू यादव के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर कर मामले में एक वर्ष के अन्दर निर्णय आदेश पारित करने का आदेश पारित किया है आदेश की प्रमाणित प्रति वादी अंगद सिंह की तरफसे न्यायालय में पूर्व में दिनांक 23 नवम्बर को दाखिल करते हुए आदेश का अनुपालन कराए जाने का लिखित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।शिवली क्षेत्र के ग्राम सरैंया लालपुर शिवराजपुर निवासी अंगद सिंह ने थाना रनिया के अन्दर अपने भतीजे बलवन्त सिंह की दिनाँक 12 दिसम्बर को आरोपियों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में बेरहमी पूर्वक पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखाई थी । मृतक व्यापारी बलवन्त सिंह का कानपुर नगर में डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था, मृतक के शरीर मे 31 चोटें होना, चोटों से खून के अत्यधिक रिसाव से दोनों गुर्दे खून से खाली हो जाने व उसी से मृतक की मृत्यु होने पाया गया थाएजिसमें विवेचना में एसआईटी ने आरोपी तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी व एक आरक्षी व जिला अस्पताल के एक चिकित्सक की नामजदगी गलत पाने का लेख लिखते हुए उनके पक्ष में अंतिम आख्या व केस में इरादतन हत्या की धारा 302 के स्थान पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया था।

अभियुक्त को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

कनपुर देहात। पुलिस द्वारा कडी पैरवी कर सजा दिलाने हेतु मुकदमों में पुलिस को एक और सफलता प्राप्त हुयी है। पुलिस की प्रभावी पैरवी से लूट के मामले में माननीय न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद कानपुर देहात ने सुनवाई कर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया कि थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपू पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम बहबलपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज के खिलाफ थाना सिकन्दरा पर मुअसं 237/2017 धारा 392/411 भादवि में पंजीकृत था। जिसमें अभियुक्त दीपू उपरोक्त के खिलाफबाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। जिसमें कोर्ट ने 20.12.2023 को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त दीपू उरपरोक्त को दोषी ठहराते हुए धारा 392/411 भादवि में जेल में बिताई गयी सजा की अवधि को समायोजित करते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस बार करें शत-प्रतिशत मतदान, तभी होगा स्वस्थ्य चुनाव: जिला निर्वाचन अधिकारी

- जनपद में स्वीप आइकॉन के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने बनाई मानव श्रंखला
- महिलाओं ने स्वयं जागरूक बन सभी को मतदान हेतु जागरूक करने की ली शपथ

कानपुर देहात। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु समूचे जनपद में स्वीप अभियान अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह के कुशल निर्देशनए उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे पी गुप्ता के मार्गदर्शन तथा नोडल अधिकारी स्वीप जिला विद्यालय निरीक्षक अचल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट स्वीप आइकॉन डॉ अनूप सचान द्वारा युवाओं में मतदान के प्रति जोश जगाने तथा परिवार की धुरी मानी जाने वाली मातृशक्ति को मतदान के प्रति जागरूक करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। जनपद की समस्त छह तहसीलों के उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदारों के सहयोग से लगातार जागरूक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ.साथ सर्दियों में जगह जगह अलाव के किनारे बैठे लोगों के साथ सांध्य स्वीप चौपाल का भी आयोजन करते हुए आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत उनके मताधिकार तथा मतदान करना कितना जरूरी है विषय पर चर्चा और गोष्ठी आयोजित कर जनपद में अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर देते हुए जागरूक करने का दौर जारी है। तहसील सिकंदरा के कस्बा राजपुर में स्थित बैलाही बाजार में तथा तहसील मैथा में एक विद्यालय में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं तथा महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्राओं को आमंत्रित कर पोस्टर, पेंटिंग सहित अन्य क्रियाकलापों से स्वीप अभियान को जोर.शोर से संचालित किए जाने की दिशा में मानव श्रृंखला बनवाकर तथा मातृ शक्तियों को जागरूक मतदाता होने की शपथ दिलाई। उनके समस्त पारिवारिक जनों के वोटर आईडी कार्ड बनवाने तथा आगामी लोकसभा निर्वाचन व अन्य सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में स्वीप आइकॉन द्वारा लगातार प्रयास करते हुए मतदान के विषय में जागरुक करते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, वेबसाईट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, बीएलओ से मुलाकात और वार्ता कर वोटर लिस्ट चेक करने के बारे में भी उन्हें अवगत कराया जा रहा है।

नौ माह में ई-संजीवनी सेवा का 1.19 लाख लोगों ने लिया लाभ

फतेहपुर। ई-संजीवनी टेली कंसल्टेंसी सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। बात अगर बीते दस माह की करें तो इस सेवा के लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस सेवा के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष के बीते नौ माह में 1 लाख 18 हजार नौ सौ अस्सी लोगों ने घर बैठे चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया है। इस सेवा के माध्यम से टेली कॉलिंग कर विशेषज्ञ चिकित्सकों से बातचीत कर चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। इसके तहत हर रोज कर अलग-अलग डॉक्टर रहते हैं जो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। ई-संजीवनी टेली कंसल्टेंसी सेवा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आई संजीवनी ऐप इंस्टॉल करें या गूगल क्रोम ब्राउज़र द्वारा पद पर जाएं। ऐप या वेबसाइट पर जाकर पेशेंट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें अपना राज्य चुने जनरल ओपीडी के अंतर्गत ओपीडी का चयन करें। मोबाइल नंबर डालें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें 6 अंकों का ओटीपी दर्ज कर अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें। पंजीकरण के बाद जेनरेट टोकन बटन पर क्लिक करके टोकन बनाएं। टोकन नंबर प्राप्त होने की सूचना मिलने पर टोकन नंबर और मोबाइल नंबर की सहायता से पेशेंट लोगों बटन पर क्लिक करें अपनी बारी का इंतजार करें और डॉक्टर से सलाह लें। सबसे अंत में ई प्रिस्क्रिप्शन पर्चे को डाउनलोड करें अब आसानी से चिकित्सक द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार उपचार करें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शाह के सीएचओ अनूप कुमार चौधरी बताते हैं कि उनके यहां प्रतिदिन 15 से बीस मरीज आते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज अधिक रहते हैं जिनका डाक्टर से कंसल्टेंसी कराकर इलाज किया जाता है।

किसान दिवस में संचालित योजनाओं के संबंध में दी गई जानकारी

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह कानपुर देहात के निर्देशन में किसानों की समस्याओं के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं ध् कार्यक्रमों के संबंध में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान दिवस का आयोजन विकास भवन सभागार माती में अपर जिलाधिकारी ;प्रशासनद्ध जगदंबा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में दिनांक 20 दिसंबर 2023 को किया गया। आयोजित किसान दिवस में उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी अकबरपुर, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता नहर, अधिशासी अभियंता नलकूप, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, जिला खनन अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं अन्य कृषि एवं कृषि समावेशी विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारियों के साथ.साथ किसान यूनियन के पदाअध्यक्ष एवं जनपद के प्रगतिशील कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उप कृषि निदेशक द्वारा किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करते हुए अवगत कराया गया की वर्तमान समय में कृषकों की आय को दुगना करने एवं उनका सर्वांगीण विकास करना भारत एवं प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैए जिसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें कृषि विभाग द्वारा प्रमुख रूप से मोटा अनाज को प्रोत्साहन की योजनाए अनुदान पर उन्नत बीज वितरणए 50 से 80: अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्र वितरणए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाए किसान सम्मान निधिए आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उनके द्वारा किसानों से इन योजनाओं किया लाभ उठाने की अपेक्षा की गई।

उप कृषि निदेशक द्वारा बैठक में उपस्थित किसान नेताओं एवं प्रगतिशील कृषकों को अवगत कराया गया कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 23 दिसंबर 2023 को इको पार्क माती में किसान सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें कृषि एवं कृषि समावेशी विभागों द्वारा सुसज्जित प्रदर्शनियां लगाकर किसानों को विभागीय योजनाओं के संबंध में जागरूक किया जाएगा तथा जनपद के प्रगतिशील किसानों एवं महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने.अपने उत्पादों के स्टाल भी लगाए जाएंगे। उप कृषि निदेशक द्वारा सभी उपस्थित कृषकों को आयोजित किसान सम्मान दिवस में प्रतिभा करने हेतु आमंत्रित किया गया। इसी प्रकार विभिन्न विभागो जैसे उद्यान, पशुपालन, मत्स्य एवम सहकारिता विभाग आदि के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किसानों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। भारतीय किसान यूनियन के कानपुर मंडल के अध्यक्ष रशीद अहमद आजाद द्वारा किसान सम्मान दिवस में उपस्थित अधिकारियों को किसने की समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया।

क्विक न्यूज

एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार

फर्रुखाबाद। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते समय विकास भवन के बाबू राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। सफाई कर्मचारी राजेश बाथम से निलंबन आबादी का वेतन का भुगतान करने के लिए लिपिक राकेश कुमार ने 80 हजार रुपए मांगे थे। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम राजेश को लेकर विकास भवन के पंचायती राज कार्यालय पहुंची। राजेश ने बाबू राकेश कुमार को रिश्वत के 10 हजार रुपए दिए। तभी एंटी करप्शन टीम ने लिपिक राकेश को दबोच लिया उसे कोतवाली फतेहगढ़ ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सफाई कर्मचारी राजेश बाथम ने मीडिया को बताया कि मैं कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला बरगदिया घाट में रहता हूं। कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम कुंवरपुर डूंगरसी में सफाई कर्मचारी पद पर तैनात हूं। बाबू राकेश कुमार ने निलंबन अवधि के बताया 1,83000 रूपयों का भुगतान करने के लिए 80 हजार रुपए मांगे थे। मैंने अपनी बाइक गिरवी रखकर 10 हजार रुपयों का इंतजाम किया। कर्जा लेकर बेटी का इलाज कराया। मालूम हो कि जिले में रुपए दिए बिना शायद ही किसी का काम होता हो एंटी करप्शन टीम ने बीते दिनों लेखपाल को भी 10 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया था।

पुलिस को देखते ही ढोंगी साधु अपहृत मासूम को छोड़कर भागा

हमीरपुर। कुरारा क्षेत्र के देबीगंज गांव में यज्ञशाला स्थल में भागवत कथा समाप्त होने के बाद एक साधु ने छह साल के बच्चे के अपहरण कर जंगल की तरफले गया, पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुये बच्चे को साधु के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक गांव में भागवत कथा समाप्त होने के बाद गांव के अनिरुद्ध का छह साल का बच्चा आर्यन दिखायी नही दिया माइक से पुकारने के बाद भी उसका कही पता नही चला तभी गांव के जियालाल ने बताया कि वह खेतो से लौट रहा था तभी एक काले कपडे पहने साधु बच्चे को लेकर जा रहा था गाव वाले ने पीआरबी 112 पुलिस को सूचना दी,पुलिस ने ग्रामीणों को साथ ले जाकर जंगल में खोजबीन शुरु की तो पुलिस को देखते ही ढोंगी साधु बच्चे को छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने दौड़कर उसे पकड लिया,बच्चा बहुत डरा था उसके व साधु के कपड़े भीगे थे। तरह तरह की अटकले लगायी जा रही है। ढोंगी साधु ने बताया कि उसका नाम बालकदास है वह मौदहा थाने के परछछ गांव का रहने वाला है। बच्चों को फुसलाकर लेजाने का काम करता है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर जेल भिजवा दिया है।

नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में एक सौ से अधिक मिले रोगी

संडीला (हरदोई)। स्व0 लाला गंगा प्रसाद मानव कल्याण समिति एवं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिनमें 111 मोतियाबिंद के पीड़ितों का नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। नगर कल्याण समिति के धर्मशालय में आयोजित इस शिविर में समिति के अध्यक्ष डॉ0 सत्यप्रकाश आर्य ने शिविर में आए चिकित्सकों डॉ0 पंकज कुमारए डॉ0 शालिनि सिंहए डॉ0 पूनम गुप्ताए डॉ0 संदीप यादवए डॉ0 देवेश सिंह तथा अन्य चिकित्सा टीम के सदस्यों का स्वागत किया। इस शिविर में 111 नेत्र रोग पीड़ितों में मोतियाबिंद पाया गयाए जिनका नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए चयन किया गया।

डीडीए ने हरि झंडी दिखा रवाना किया बस

फतेहपुर। परंपरागत कृषि विकास योजनान्तार्गत जनपद से कृषक प्रशिक्षण के लिए साठ किसानो का जत्था बुद्धवार को कृषि भवन लखनऊ बाईपास के पास से राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव झाँसी प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। किसानो की बस को उपनिदेशक कृषि प्रसार राममिलन सिंह परिहार व एसडीओ कृषि प्रसार रंजीत चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौत

फतेहपुर। कौशाम्बी जनपद के सैनी कोतवाली क्षेत्र के जोरावरपुर गाँव निवासी स्व. राम मनोहर का 48 वर्षीय पुत्र राम भवन पाल बाइक पर सवार होकर सब्जी लेने घर से निकला था। जब वह कौशाम्बी जनपद और फतेहपुर बॉडर के बीच कैच मोड़ पर पहुंचा तभी चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार गम्भीर रूप से घायल हो गया। जब तक उसको कही इलाज के लिए लेकर जाते उससे पहले ही उसकी मौके पर मौत हो गई।

ट्रक की टक्कर से रज्जन की मौके पर मौत

फतेहपुर। हुसैनगंज थानां क्षेत्रं के सहनीपुर गाँव व हाल मोकाम सदर कोतवाली क्षेत्र के रेयाज कालोनी गढ़ीवा मोहल्ला निवासी रज्जन पाण्डे का 45 वर्षीय पुत्र सचिन पाण्डे उर्फसुनील पाण्डे अपने ब्यवसायिक कार्य से चार पहिया वाहन से लखनऊ गया था। वहाँ से जब वह वापस आ रहा था तभी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बेरा गढ़ीवा गाँव के समीप ट्रक ने उसके चार पहिया वाहन को टक्कर मार दिया जिससे सचिन गम्भीर रूप से घायल हो गया।

नाबालिग किशोरी का अपहरण, शौच के लिए कहकर घर से निकली

फतेहपुर। जिले के एक नाबालिग लड़की के अपहरण का गंभीर मामला सामने आया है। खोजबीन के बाद सफलता न मिलने पर मामले में परिजनों ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि, 16 दिसंबर की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। उसकी 14 वर्षीय बेटी घर से शौंच के लिए कहकर निकली थी। काफी देर लड़की के वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पड़ोसी गांव के रहने वाले युवक पर आरोप आरोप है कि इस दौरान पता चला कि रात करीब आठ बजे थाना क्षेत्र के पड़ोसी गांव मऊ का रहने वाला दिलदार लड़की को बुरी नीयत से बहला फुसला कर भगा ले गया। लड़की के पिता ने सकुशल बरामदगी करने के साथ आरोपी युवक पर कार्रवाई किए जाने की स्थानीय थाने में तहरीर दी है।

द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत चलाया गया सघन चेकिंग अभियान

ट्रेक्टर चालकों को हिदायत देते यातायात प्रभारी।

कन्नौज। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक डॉ संसार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ओमकारनाथ शर्मा के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफ़ाक़ खान द्वारा तिर्वा रोड में वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसमें कई लोडरों एवं ट्रैक्टरों को चेक किया गया। जिसमें सवारियां बैठी पाई गई। जिन लोडरों में सवारियां बैठी पाई गई उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं दो ऐसे ट्रैक्टर मिले, जिनको चेक करने पर पता चला कि ट्रैक्टर और ट्राली को ज्वाइंट करने वाला लीवर जिसमें सेफ्टी पिन लगाई जाती है, सेफ्टी पिन लगी नहीं पाई गई। जो कि बहुत खतरनाक होता है। कभी भी लिवर धक्का लगने पर उछल सकता है जिससे ट्राली, ट्रैक्टर से अलग हो सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। यातायात प्रभारी द्वारा ट्रैक्टरों में बैठी सवारियों को और ट्रैक्टर चालकों को हिदायत देते हुए यातायात नियमों की जानकारी दी गई और ट्रैक्टरों में नंबर प्लेट लगवाने की सलाह दी गई।

शासन ने सेतु निगम से पुलों के निर्माण कार्य हटाकर ठेकेदारों पर विश्वास जताया

- वेतवा नदी में पारा-कंडौर मार्ग पर बनने वाला 90 करोड़ का पुल भी बनायेगा ठेकेदार

संवाददाता। हमीरपुर

शासन ने सेतु निगम से पुलों के निर्माण करने का अधिकार हटा कर ठेकेदार को दे दिया है। अब सेतु निगम कोई भी पुल बनाने में कार्यदायी संस्था नही रहेगी केवल ठेकेदारो के काम का मानीटरिंग करेगी। शासन का मानना है कि इस फैसले से रेट रिवाइज की प्रथा समाप्त हो जायेगी। अब बेतवा नदी में परसनी-कंडौर मार्ग में 90 करोड़ की लागत का बनने वाला पुल ठेकेदार द्वारा निर्मित किया जायेगा। सेतु निगम केवल मानीटरिंग कार्य करेगा।

जानकारी के मुताबिक शासन ने सेतु निगम की स्थापना प्रदेश में पुलों को निर्माण करने के लिये किया था,सेतु निगम कई दशकों से पुलों का निर्माण करा रहा है विभाग के पास अच्छी तकनीकि व डिजायन करने वाले एक्सपर्ट इंजीनियर भी है। मगर हर काम में विलंब होने से ज्यादातर पुलों में शासन को रेट रिवाइज करना पड़ता था। जिससे शासन का करो़डो रुपये अधिक व्यय होता था। हालाकि जिले में बेतवा नदी में बाईपास पर 302 करो़ड की लागत का फोरलेन पुल का निर्माण सेतु निगम ही करा रहा है। हालाकि इस पुल का भी रेट रिवाइज हो चुका है। परसनी कंडौर मार्ग में बनने वाला चौदह कोठियों के पुल निर्माण की मिट्टी की जांच व सर्वे सेतु निगम ने ही किया था मगर शासन की रातो रात एकदम पालिसी बदल गयी और परसनी कंडौर मार्ग के पुल के बनाने का काम ठेके दार को दे दिया है। पुल का एप्रोच मार्ग लोनिवि निर्माण करेगा। बताया जाता है कि सेतु निगम जो कार्य कराता था उसमे भी ठेकेदार की भूमिका होती थी सेतु निगम निर्माण सामग्री सीमेंट सरिया जो पुल निर्माण में अहम भूमिका निभाते है यह विभाग ही देता था ताकि ठेकेदार इस सामग्री में कोई कंजूसी न कर पाये और गुणवत्ता पूर्ण निर्माण हो मगर सेतु निगम में रेट रिवाइज का जो बीमारी लगी थी इस पर शासन को यह फैसला करना पड़ा है। हालाकि इसको लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है पुल जैसे निर्माण में पूरी तरह ठेकेदार को लाना लोगो के गले में नही उतर रहा है। सेतु निगम के सहायक अभियंता पंकज त्रिपाठी का कहना है कि शासन की पालिसी के अनुसार विभाग का करेगा और विभाग पुल निर्माण में निगरानी कर पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा।

बैलेट पेपर से चुनाव कराने सहित अन्य समस्याएं उठाते हुए भारतीय कृषक एसो. ने सौंपा ज्ञापन

कायमगंज फर्रुखाबाद । भारतीय कृषक एशो. ने जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन की प्रति उप जिलाधिकारी कायमगंज यदुवंश कुमार वर्मा को सौंपी। जिसमें कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव वैलेट पेपर से कराए जाएं। ई वी एम से निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने नगर पालिका का उदाहरण भी दिया है। इसी के साथ संगठन ने कहा है कि कायमगंज नगर में पेयजल पुनर्गठन योजना के अंतर्गत निगम को पाइपलाइन तथा ट्यूबवेल का कार्य सौंपा गया था। लेकिन अब तक यह कार्य अधूरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में इस नगर में 56 वर्ष पुरानी पाइप लाइनों से सप्लाई देने के कारण जलापूर्ति में अशुद्धता आ रही है।

किसानों की केसीसी सीमा 3 लाख से बढ़कर चार प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित करते हुए 5 लाख करने की मांग की। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कायमगंज ब शमशाबाद में कार्यरत रहे अधिकारी तथा कर्मचारी तबादला होने के बाद भी सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसे लोगों से आवास कब्जा खाली कराए जाएं।

किसान नेताओं ने विद्युत मीटर रीडिंग गलत ढंग से दर्ज किए जाने का आरोप लगाया। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव गुरुऊ शादी नगर के पास रेलवे स्टेशन पखना रोड पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके कई दुकानों पर मुर्गा मछली तथा बकरी आदि के गोश्त की बिक्री खुलेआम की जा रही हैं ।इस पर रोक लगाई जाए । साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की मिली भगत के कारण ही नगर तथा अन्य स्थानों पर खुलेआम मिलावट युक्त वस्तुएं बेची जा रही हैं । जिससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। खाद्य अधिकारी ऐसे लोगों से रिश्वत वसूलकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए इस पर रोक लगाते हुए ए सहायक खाद्य आयुक्त सहित अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अवैध स्त्रोतों से अर्जित चल अचल संपत्ति की जांच कराई जाए।

अवैध बालू खनन को तत्काल रोकने की प्रशासन से मांग

कायमगंज फर्रुखाबाद। तहसील क्षेत्र कायमगंज के गांव बेहटा बल्लू में गंगा के किनारे हो रहे अवैध बालू खनन पर चिंता व्यक्त करते हुए जनता जागृति सेवा संगठन के पदाधिकारी ने एसडीएम कायमगंज यदुवंश कुमार वर्मा के नाम संबोधित ज्ञापन तहसील पहुंचकर सौंपा। सौपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बालू खनन माफिया इस गांव के खेतों से जेसीबी मशीनों द्वारा लगातार अवैध बालू खनन कर रहे हैं ।उनका आरोप है कि खनन करने वाले गंगा तट के बिल्कुल किनारे स्थित खेतों से भारी.भारी गड्ढे बनाकर बालू का खनन कर उसे दूसरी जगह ले जाकर काफी महंगी कीमत पर बेच रहे हैं । उनके इस कार्य से गंगा की धारा को तथा खासकर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन बड़े.बड़े गढ्डों में जब सैलाब या वर्षा का पानी भर जाता है। तो खेतों पर जाने वाले किसानों के इस गहरे पानी में डूबने की आशंका बढ़ जाती है ।

ऐरायां में दिव्यांग बच्चों की तहसीलस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न

खागा (फ़तेहपुर)। विकासखंड ऐरायां में तहसील स्तरीय दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐलई के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कृष्णा पासवान व विशिष्ट अतिथि के रूप में खागा नगर पंचायत की अध्यक्ष गीता सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन एआरपी डा. अंबिका प्रसाद मिश्र ने किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण करके किया गया। विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की नीतियों का लाभ जन-जन तक पहुंचे और दिव्यांग बच्चे भी समाज के मुख्य धारा से जुड़े। इसीलिए यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बीआरसी स्टाफ ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में ऐरायां, विजयीपुर, धाता एवं हथगाम ब्लाक के कुल एक सौ नौ बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों के लिए दौड़, कुर्सी दौड़, छूकर पहचानना, गेंद फेंकना आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में शिवा ने प्रथम, दीपांशु ने द्वितीय तथा सचिन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुर्सी दौड़ में मोनी ने प्रथम, लक्ष्मी ने द्वितीय तथा आस्था ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गेंद फेकना में अंकेश प्रथम, प्रिया द्वितीय तथा रतन सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। छूकर पहचानना प्रतियोगिता में माया देवी ने प्रथम, प्रदीप ने द्वितीय तथा लक्ष्मी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ सभी प्रतिभागी बच्चों को भी सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐलई, प्राथमिक विद्यालय प्रथम व प्राथमिक विद्यालय ऐलई द्वितीय के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बुंदेलखंड राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष प्रवीण पांडेय, भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष विमलेश पांडेय, भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष राकेश सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री विजय कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अशोक सिंह, आनंद कुमार मिश्र, कुलदीप कुलभूषण, एआरपी अजय सिंह व कृष्ण वीर सिंह, राम प्रसाद, कैसर परवीन, रूपाली गुप्ता, सरोज राजपूत, गरिमा सिंह, स्पेशल एजुकेटर सुरेश सिंह, अनिल कुमार, प्रीती सिंह, वीरभान, दिलीप सिंह, लालचंद, रिषी त्रिपाठी, सर्वेश कुमार आदि शिक्षक तथा अभिभावक उपस्थित रहे।

मदरसा शिक्षा बोर्ड रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित

छह हफ्ते में मांगी सफाई, कहा-क्यों न किया जाए मामले में दंडित

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा बोर्ड लखनऊ डा प्रियंका अवस्थी के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित कर छह हफ्ते में सफाई मांगी है और पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें अवमानना मे दंडित किया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 19 फरवरी 24 को हाजिर रहने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मोहम्मद सलीम और दो अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि याचीगण मदरसा कुरूनियां जौनपुर में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और नियुक्ति को वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया। कालेज प्रबंधन में विवाद के कारण नियुक्ति को लेकर शिकायत की गई। उप सचिव ने रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया और अनुमोदन निरस्त कर दिया गया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिया। जिसका पालन न करने पर रजिस्ट्रार तलब की गई। हलफनामा दाखिल कर कहा याचिका पर जवाब दाखिल कर अंतरिम आदेश वापस लेने की प्रार्थना की गई है। इसलिए याचिका तय होने तक अवमानना केस की सुनवाई टाली जाए। इससे पहले कोर्ट ने आदेश पालन का एक माह का आखिरी अवसर दिया था।फिर भी पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने आरोप निर्मित कर सफाई मांगी है।

वन विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिछले 10 या 20 साल से कार्यरत दैनिक कर्मियों के अधिकार प्रभावित होते हैं तो भर्ती याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने पुष्पेंद्र सिंह और चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि पहले विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी पद दे उन्हें पदस्थापित कर तृतीय श्रेणी पद की भर्ती की जा रही है। यदि चयन की अनुमति दी गई तो नियमित होने के हकदार दैनिक कर्मियों का हित प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से वन विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मियों को समायोजित और नियमित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भी 20 साल से कार्यरत दैनिक कर्मियों को न्यूनतम वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया है। कोर्ट ने नीति तैयार करने की कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किया है। इसलिए भर्ती पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वीवो पीएमएलए मामला: कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया।चार व्यक्तियों – लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता ने न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों को 19 फरवरी को तलब किया है।आरोपपत्र धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत इस महीने की शुरुआत में दायर किया गया था।ईडी ने दावा किया कि चारों आरोपियों की कथित गतिविधियों ने वीवो-इंडिया को गलत तरीके से लाभ कमाने में सक्षम बनाया जो देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था।धनशोधन रोधी एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में वीवो-इंडिया और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की थी और चीनी नागरिकों तथा कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धनशोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था।ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में कर भुगतान से बचने के लिए वीवो-इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपए की भारी रकम अवैध रूप से चीन भेजी गई थी।कंपनी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वह अपने नैतिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करती है और कानूनी अनुपालन के लिए समर्पित है।

अवैध कोयला खननः मेघालय उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक के तबादले का आदेश दिया

शिलांग। मेघालय उच्च न्यायालय ने अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने के चलते पूर्वी जैंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक जगपाल धनोआ को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच एस थांगख्यू और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश बी के कटेकी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट दर्शाती है कि पुलिस अधीक्षक शायद अवैध गतिविधियों को रोकने में विफल रहे हैं। पीठ ने कहा, पुलिस अधीक्षक की विफलता पर, जैसा कि 19वीं अंतरिम रिपोर्ट से पता चलता है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें तुरंत मौजूदा पद से स्थानांतरित किया जाए।

थेरेपी ऑपरेटर की वेतन विसंगति पर तीस दिन में निर्णय ले डीजीएमईः हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के महनिदेशक डीजीएमई को मेडिकल कॉलेज में तैनात रेडियो थेरेपी ऑपरेटर को एक्स रे टेक्निशियन के मुताबिक वेतनमान प्रदान करने पर निर्णय लेते हुए तीस दिन के भीतर बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के रेडियो थेरेपी विभाग में तैनात थेरेपी ऑपरेटर संजय कुमार सिंह राठौर की याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुन कर पारित किया। याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने बताया कि याची की वर्ष 2006 से आगरा मेडिकल कॉलेज में थेरेपी ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। विभागीय जरूरत को पूरा करने के लिए उसे विभाग ने एक्स रे टेक्निशियन का विशेष प्रशिक्षण शासन की अनुमति से पूरा कराया। याची नियमित रूप से रेडियो थेरेपी ऑपरेटर का काम कर रहा हैं लेकिन उसे शासन द्वारा एक्स रे टेक्निशियन के समान वेतनमान प्रदान नही किया गया। याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने दलील दी कि रेडियो थेरेपी ऑपरेटर का पद एक्स रे तकनीशियन कैडर का पद है। इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर याची एक्सरे तकनीशियनों के समान वेतनमान पाने का अधिकारी हैं। याची शासन को प्रतिवेदन भेजा है। जिस पर अंतिम निर्णय वर्ष 2015 से अब तक नहीं हुआ। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक को याची के वेतन विसंगतियों पर विधि अनुसार निर्णय लेते हुए आदेश पारित करने और तीस दिन के भीतर संशोधित वेतनमान के मुताबिक बकाए वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया।

छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज केस में आरोपी पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस सी एस टी एक्ट के तहत जाति सूचक फब्ती कसने व छेड़छाड़ के आरोपी प्रयागराज मांडा के गुलाब शंकर शुक्ल के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार व विपक्षियों से चार हफ्ते में अपील पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने अधिवक्ता दिवांशु तिवारी व शैलेश कुमार उपाध्याय को सुनकर दिया है। अपील में विशेष अदालत प्रयागराज के 12 अक्टूबर 23 के आदेश को चुनौती दी गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि गरीब शिकायतकर्ता महिला भोलानाथ पांडेय के घर श्रमिक का काम करती है। अपीलार्थी और भोलानाथ पांडेय के बीच विवाद है। दबाव बनाने के लिए एफआईआर दो दिन देरी से दर्ज की गई है। जबकि कोई घटना ही नहीं हुई। कोर्ट ने कहा इस स्तर पर आरोपों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। मामला विचारणीय है।

अपर पुलिस महानिदेशक को ग्रेच्युटी भुगतान में देरी पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर महानिदेशक पुलिस उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ को निर्देश दिया है कि ग्रेच्युटी भुगतान में देरी के कारण बकाया देयों का भुगतान तीस दिन में कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करें अन्यथा कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 जनवरी नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कमाल अहमद ख़ान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता बी एन सिंह राठौर ने बहस की। विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर कहा कि याची का पूरा भुगतान कर दिया गया है। ग्रेच्युटी भुगतान में देरी पर ब्याज के भुगतान का प्रकरण अपर महानिदेशक पुलिस को प्रेषित किया गया है।याची 21 अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्त हो चुका है। उसके खिलाफआपराधिक केस के कारण भुगतान रुका रहा।जबकि उसे आपराधिक केस में बरी कर दिया गया है। याची अधिवक्ता राठौर का कहना है कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने पर किसी को सजा मिले बगैर दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए याची समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा ग्रेच्युटी भुगतान में तीन साल की देरी पर ब्याज की मांग उचित है।

अदालत ने पेड़ों के आसपास से कंक्रीट हटाने का आदेश दिया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भीकाजी कामा प्लेस परिसर में पेड़ों के आसपास से तुरंत कंक्रीट हटाने का बुधवार को निर्देश दिया और इस तरह के सौंदईकरण के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पेड़ों के आसपास कंक्रीट लगाए जाने और इससे वृक्षों को हुए नुकसान के संबंध में एक शिकायत पर त्वरित कार्वाई नहीं करने संबंधी अवमानना याचिका पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि उन्हें अगस्त में पता चला कि डीडीए सौंदईकरण के लिए भीकाजी कामा प्लेस कॉम्प्लेक्स में पेड़ों के चारों ओर एक चबूतरे का निर्माण कर रहा है। न्यायमूर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा, इस सौंदईकरण का क्या मतलब है? क्या आप फुटपाथ पर कंक्रीट संरचनाएं बनाते हैं? यह पेड़ों के लिए है। आप इनकी गतिविधि को प्रतिबंधित कर रहे हैं? इसका क्या औचित्य है। अदालत ने वन विभाग के वकील से इस बात का विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा कि शिकायत किए जाने के बावजूद पेड़ों की सुरक्षा के लिए कंक्रीटीकरण के खिलाफ उसके अधिकारियों ने कोई त्वरित कार्वाई क्यों नहीं की। इसने वन विभाग के वकील से कहा, मैं आपका विभाग बंद कर दूंगा। आप पूरी तरह से अक्षम हैं... 50 दिन के बाद आप इस पर तुरंत कैसे कार्वाई करेंगे? यह सही दिशा में नहीं जा रहा है। यह दुखद है। अदालत ने कहा, प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ों के आसपास से कंक्रीट ढांचा तुरंत हटाया जाए। इसने वन संरक्षक को पेड़ों के कंक्रीटीकरण से संबंधित आदेश के उल्लंघन और इसके खिलाफ उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया।

अपमानजनक पोस्ट रोकने के लिए मोइत्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई को उनके खिलाफ कोई भी कथित फर्जी और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोकने संबंधी अंतरिम अर्जी पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। मोइत्रा को हाल में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। वह लोकसभा में पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट का प्रतिनिधित्व करती थीं। उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता मोइत्रा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद दुबे और देहाद्रई के वकील को सुनने के बाद अंतरिम अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने प्रतिवादियों के वकील से जानना चाहा कि क्या मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच कोई लेन-देन हुआ था। मोइत्रा ने अक्टूबर में दायर अपनी याचिका में दुबे, देहाद्रई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स , सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब और 15 मीडिया संस्थानों के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की थी और अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ अपमानजनक, प्रथम दृष्टया झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान प्रकाशित करने, प्रसारित करने पर रोक लगाई जाए। उन्होंने हर्जाना भी मांगा है। बाद में मोइत्रा ने पक्षकारों की सूची से सभी मीडिया घरानों और सोशल मीडिया मध्यस्थों को हटा दिया और कहा कि उनका मामला केवल दुबे और देहाद्रई के खिलाफ है। दलीलों के दौरान, देहाद्रई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय घोष और दुबे का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभिमन्यु भंडारी ने दावा किया कि मोइत्रा को अपने व्यावसायिक हितों के पक्ष में सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी से बदले में उपहार और अन्य लाभ मिले। उन्होंने लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया और कहा कि समिति ने भी उनके और हीरानंदानी के बीच साठगांठ पाई, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया। अदालत ने वकील से समिति की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। मोइत्रा के वकील ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें हीरानंदानी से उपहार मिले थे क्योंकि वे दोस्त थे, न कि संसद में सवाल पूछने के लिए। वकील ने दावा किया कि देहाद्रई और दुबे अभी भी मोइत्रा के खिलाफ मानहानिकारक बयान दे रहे हैं और अदालत से उन्हें ऐसा करने से रोकने का आग्रह किया। दुबे ने मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके खिलाफ आरोपों की छानबीन के लिए एक जांच समिति गठित करने का आग्रह किया था। वकील देहाद्रई से मिले एक पत्र का हवाला देते हुए दुबे ने कहा था कि वकील ने कारोबारी द्वारा कथित तौर पर टीएमसी नेता को रिश्वत दिए जाने के अकाट्य सबूत साझा किए हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने दल-बदल कानून में विलय पर संरक्षण को चुनौती मामले में केंद्र से जवाब मांगा

भाषा। मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने दो दलों के आपस में विलय कर लेने की स्थिति में दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य करार दिए जाने से प्राप्त संरक्षण को एक जनहित याचिका के माध्यम से दी गई चुनौती पर बुधवार को सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने महान्यायवादी आर वेंकटरमनी को भी नोटिस जारी किया क्योंकि जनहित याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के चौथे अनुच्छेद की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। दसवीं अनुसूची दल-बदल कानून से संबंधित है। यह प्रावधान कहता है कि दो दलों के आपस में विलय कर लेने की स्थिति में दल-बदल के आधार पर (उन्हें) अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय मीडिया एवं विपणन पेशेवर तथा गैर सरकारी संगठन वनशक्ति की संस्थापक न्यासी मीनाक्षी मेनन की जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था। खंडपीठ ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मेनन के वकील अहमद आब्दी ने दलील दी कि दल-बदल सामाजिक बुराई है तथा विधायकासांसद जनहित के कारण नहीं बल्कि सत्ता, धन के लालच में तथा कभी-कभी जांच एजेंसियों के डर से अपनी निष्ठा बदल लेते हैं। आब्दी ने कहा, इन सब बातों की मार मतदाता भुगत रहा है।

मतदाता संसद तो जा नहीं सकता, मतदाता बस अदालत ही आ सकता है। एक खास विचारधारा या घोषणापत्र के आधार पर वोट डाला जाता है लेकिन बाद में पार्टी ही बदल जाती है। यह मतदाता के साथ विश्वासघात है। मेनन की अर्जी में अनुरोध किया गया है कि अदालत दसवीं अनुसूची में राजनीतिक दलों के विभाजन एवं विलय की व्यवस्था देने वाले अनुच्छेद को असंवैधानिक तथा उसके मूल स्वरूप के विरूद्ध घोषित करे। याचिका में कहा गया है कि नेता गुट या समूह में दल बदल करने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रक्रिया में मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जाता है।

अदालत ने शेखावत से गहलोत की अपील पर जवाब देने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस अपील पर जवाब देने को कहा जो उन्होंने एक आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें समन किए जाने के खिलाफ दायर की है।न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले को 22 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। गहलोत ने शेखावत द्वारा दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है। सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता नहीं है।

नवलखा के खिलाफ आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने का फिलहाल कोई साक्ष्य नहींः उच्च न्यायालय

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा है कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा सके कि उन्होंने साजिश रची थी या कोई आतंकी कृत्य किया। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की पीठ ने मंगलवार को नवलखा को जमानत दे दी। फैसले का पूरा पाठ बुधवार को उपलब्ध हुआ। उच्च न्यायालय ने कहा, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता (नवलखा) किसी गुप्त या प्रत्यक्ष आतंकी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं रहा है। इस मामले में अगस्त 2018 में गिरफ्तार नवलखा को नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने नजरबंद करने की इजाजत दे दी थी। वह वर्तमान में नवी मुंबई, महाराष्ट्र में रह रहे हैं। पीठ ने नवलखा को जमानत देते हुए आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी ताकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके। फैसले में कहा गया, हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि एनआईए द्वारा हमारे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। अदालत ने कहा, हमारे अनुसार, रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि अपीलकर्ता का इरादा कथित अपराध करने का था, इससे अधिक नहीं। उक्त इरादे को आगे चलकर आतंकवादी कृत्य करने की तैयारी या प्रयास में परिवर्तित नहीं किया गया। इसने कहा कि गवाहों के बयानों से बस ए संकेत मिलता है कि नवलखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्य थे, जिस पर केवल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेना) और 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता) के प्रावधान लागू होंगे। इन दोनों धाराओं में अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि दस्तावेज, जो नवलखा के पास से बरामद नहीं हुए हैं लेकिन उनके नाम का उल्लेख है, उनमें कुछ खास तथ्य नहीं है। अदालत ने कहा, इन पत्रों, दस्तावेजों की सामग्री जिनके माध्यम से अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है, श्रुति आधारित साक्ष्य के रूप में हैं, क्योंकि वे सह-आरोपियों से बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों और पत्र के माध्यम से एनआईए नवलखा का किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियों से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही थी।

पेज एक का शेष

मॉब लिंचिंग...

नहीं किया जाएगा। यहां मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से 'आतंकवाद' को आपराधिक न्याय प्रणाली के दायरे में ला दिया है। उन्होंने कहा कि हमने राजद्रोह की परिभाषा को 'राजद्रोह' (सरकार के खिलाफ अपराध) से बदलकर 'देशद्रोह' (राष्ट्र के खिलाफ अपराध) कर दिया है।' उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 124 या राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है। शाह ने कहा, नए कानून का उद्देश्य 'सरकार को बचाना नहीं, बल्कि देश को बचाना है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, हर किसी को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन हम किसी को भी भारत के बारे में अपमानजनक कुछ भी कहने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जो राजद्रोह का कानून बनाया, जिसके तहत तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल... हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी वर्षों तक जेल में रहे और वह कानून आज तक चल रहा है। जब विपक्ष में थे तो विरोध करते थे, लेकिन जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। पहली बार, मोदी सरकार ने राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया। शाह ने कहा कि राज्य का पहला कर्तव्य न्याय है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को मजबूत प्रशासन देने के लिए इन तीनों के बीच काम का बंटवारा किया। आज पहली बार ये तीनों मिलकर देश को न्याय केंद्रित व्यवस्था देंगे। शाह ने कहा, पहली बार मोदी के नेतृत्व में हमारे संविधान की भावना के अनुरूप कानून बनने जा रहे हैं। नए कानून हमारे संविधान के मूल मूल्यों- व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के लिए समान व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। बहस का जवाब देते हुए, जो मंगलवार को शुरू हुई और बुधवार को भी जारी रही, शाह ने कहा कि विधेयकों में तीन प्रमुख संशोधन लाए गए हैं और इनमें चिकित्सा पेशेवरों को राहत देना शामिल है, जिन्हें कभी-कभी मरीजों के रिश्तेदारों से धमकी का सामना करना पड़ता है। बहस में भाग लेते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि नए आपराधिक बिल लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा हैं क्योंकि वे पुलिस को 'न्यायाधीश, जूरी और निष्पादक' के रूप में कार्य करने की व्यापक शक्तियाँ देते हैं। उन्होंने कहा कि बीएनएस में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं जो 'बहुत खतरनाक' हैं। इसी अंदाज में बोलते हुए एनडीए की पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण बिलों को इस तरह से पारित नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली पर गृह मंत्री ने कहा कि समयसीमा देश में न्याय हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा रही है। उन्होंने कहा, 'न्याय समय पर नहीं मिलता...तारीख पर तारीख मिलती है...हर कोई एक-दूसरे पर दोष मढ़ता रहता है।' शाह ने कहा कि अब शिकायत मिलने के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी और 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी।

कुछ घटनाओं...

है। आरोपों की जांच के लिए भारत पहले ही एक जांच समिति गठित कर चुका है। साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि भारत 'विदेश स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों के बारे में गहराई से चिंतित था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये तत्व डराने-धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मजबूत द्विदलीय समर्थन है, जो एक परिपक्व और स्थिर साझेदारी का स्पष्ट संकेतक है। मोदी ने कहा कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग हमारी साझेदारी का एक प्रमुख घटक रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों से जोड़ना उचित है। मोदी ने कहा कि रक्षा, व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सहित कई क्षेत्रों में भारत-अमेरिका संबंध बढ़ रहे हैं। हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि हम बहुपक्षवाद के युग में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। यह वास्तविकता हमें यह मानने के लिए मजबूर करती है कि सभी मामलों पर पूर्ण सहमति सहयोग के लिए पूर्व शर्त नहीं हो सकती। दोनों पक्ष अब 'इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज' के तहत सेमीकंडक्टर, अगली पीढ़ी के दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा सहित सात विशिष्ट उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पर काम कर रहे हैं। मोदी ने जून में वाशिंगटन का दौरा किया जिससे दोनों पक्षों के बीच संबंधों में नई गति आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए मोदी के साथ व्यापक बातचीत की।

नकल उतारने...

अपमान बताने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे अक्सर राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या मुझे यह कहना चाहिए क्योंकि मैं दलित हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी धनखड़ से मुलाकात कर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि एक सांसद ने इस घृणित कृत्य को वीडियो ग्राफी के जरिए प्रचारित करने का फैसला किया। जिसे लोकतंत्र में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने उत्तराधिकारी धनखड़ के समर्थन में कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभापति के पद संवैधानिक पद हैं जिनकी गरिमा और मर्यादा को कभी कम नहीं किया जाना चाहिए। धनखड़ के प्रति समर्थन में मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही में भाग लिया और उनके साथ एकता दर्शाने के लिए लगभग 10 मिनट तक खड़े रहे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने मिमिक्री मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आलोचना करने पर आरोप लगाया कि 10 साल के लंबे कार्यकाल के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में सेवानिवृत्त हो रहे हामिद अंसारी को विदाई देते समय नरेंद्र मोदी ने अंसारी का मजाक उड़ाया था और उनकी पहचान को उसके धर्म तक सीमित कर दिया था। सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान बनर्जी ने धनखड़ की नकल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस हरकत का वीडियो बनाते दिखे। बनर्जी के अनुसार, यह अनजाने में किया गया था न कि उपराष्ट्रपति का अनादर करने के लिए। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए संसद परिसर में मौजूद बनर्जी ने कहा, हम हर किसी का सम्मान करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय...

लिए वह बुधवार दोपहर करीब एक बजकर 30 मिनट पर रवाना हुए। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को समन जारी करने के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के अधिवक्ता नोटिस का अध्ययन कर रहे हैं और कानूनी रूप से उचित कदम उठाए जाएंगे। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल का विपश्यना सत्र पूर्व निर्धारित था और यह जानकारी सार्वजनिक थी। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा था, हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री 19 दिसंबर को विपश्यना सत्र के लिए जा रहे हैं। वह नियमित रूप से इस ध्यान सत्र के लिए जाते हैं। यह एक पूर्व निर्धारित और पूर्व घोषित कार्यक्रम है। ईडी ने इससे पहले केजरीवाल को दो नवंबर को समन भेजा था, लेकिन नोटिस को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे।

बंगाल के...

बाद आया है। कात्याल को ईडी ने नवंबर में गिरफ्तार किया था। कथित घोटाला उस समय का है जब लालू संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक, भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में समूह डी पदों पर कई व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और बदले में, इन व्यक्तियों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। पिछले कुछ महीनों में, ईडी ने इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख की पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती (राज्यसभा में राजद सदस्य), चंदा यादव और रागिनी यादव के बयान दर्ज किए हैं।

राजस्थान में नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ

भाषा। जयपुर

राजस्थान की नवगठित 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को यहां शुरू हुआ जहां नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष कालीचरण सराफ ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने विधायक पद की शपथ ली। उनके बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के विधायक, संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर अपना विरोध जताने के लिए बांह पर काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। सदन में इस दौरान मौजूद प्रमुख चेहरों में कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तो सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं अन्य नेता नजर आए। राजस्थान की नवगठित 16 वीं विधानसभा का यह पहला सत्र है। पहले दिन 199 में से 190 विधायकों ने शपथ ली। जो विधायक सदन में उपस्थित नहीं होने के कारण शपथ नहीं ले पाए उन्हें बृहस्पतिवार को शपथ दिलाई जाएगी।

राजस्थान विधानसभा के सत्र में भाग लेने जातीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी

इसके साथ ही कल राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद का भी चुनाव होगा। भाजपा की ओर से वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। इस बीच देवनानी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को पांच नामांकन पत्र पेश किए। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के सामने पेश पहले नामांकन पत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्ताव को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अनुमोदित किया। दूसरे नामांकन पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने अनुमोदित किया। तीसरे नामांकन पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रस्ताव को विधायक राजकुमार रोत ने अनुमोदित किया। इसी प्रकार चौथे नामांकन पत्र में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रस्ताव को विधायक चंद्रभान सिंह ने अनुमोदित किया। पांचवें नामांकन में विधायक हनुमान बेनीवाल के प्रस्ताव को विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने अनुमोदित किया। राज्य में विधानसभा की 200 में से 199 सीट पर 25 नवंबर को मतदान हुआ। भाजपा ने 115 सीट जीतीं, जबकि कांग्रेस को 69 सीट मिलीं। करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर अब पांच जनवरी को मतदान होगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य को सर्व सुलभ बनाना महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति

हैदराबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय संस्थानों को समग्र राष्ट्र निर्माण में सहयोग की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने यहां एमएनआर एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा प्रगति के द्वार खोलती है और अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को जीवन में सक्रिय रखता है। मुर्मू ने कहा, इसके लिए संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि तेलंगाना और देश के समग्र विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, खासकर हैदराबाद में स्थित आईटी कंपनियों और राज्य के प्रतिभाशाली आईटी पेशेवरों ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुर्मू ने कहा, हमारे आईटी पेशेवरों की दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है।

भागवत ने मातृभाषा का सम्मान करने, विदेशी भाषाओं को बढ़ावा न देने का आग्रह किया

भुवनेश्वर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के बजाय अपनी मातृभाषा में बातचीत करने और इसका सम्मान करने का बुधवार को आग्रह किया। भागवत ने यहां अखिल भारतीय साहित्य परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लोगों ने अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, यहां हमारे देश में मातृभाषा के इस्तेमाल पर बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने अपनी मातृभाषा का प्रयोग बंद कर दिया है। परिणामस्वरूप, हमें अपने ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए अंग्रेजी शब्दकोश का संदर्भ लेना पड़ता है।

आरएसएस प्रमुख ने कहा, आज, हमने विभिन्न भारतीय भाषाओं के कई लेखकों को सम्मानित किया है। लेकिन, हमारी मातृभाषा को वास्तविक सम्मान तब मिलेगा, जब

हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। साहित्य के बारे में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इसे समाज के लाभ के लिए लिखा जाना चाहिए, न कि मनोरंजन या मानव जाति को किसी नुकसान के लिए। उन्होंने कहा, व्यक्ति को जिम्मेदार बनाने के लिए साहित्य लिखा जाना चाहिए।

भागवत ने यह भी दावा किया कि प्राचीन काल में अन्य देशों में कोई धर्म नहीं था तथा यह भारत से चीन और जापान जैसे कुछ अन्य देशों में फैला। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल की कुछ किताबों की सामग्री से यह आभास होता है कि आप हिंदू नहीं हैं और ऐसे लेखन समाज को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जो खतरनाक है।

इंटरनेशनल साइंस कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ

भाषा। नई दिल्ली

संयुक्त रूप से आयोजित तीसरे इंटरनेशनल साइंस कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव और 23वीं इंडियन साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में विज्ञान संचार विषय पर विद्वानों ने चर्चा की। इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसायटी की सहभागिता में हुए इस वार्षिक समागम में दुनियाभर से ऑन लाइन ढंग से विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रख्यात विज्ञान संचारक और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान लेखक संघ के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पटैरिया के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के डॉ. एसके वार्ष्णेय ने की।

काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय की प्रो. अंजना सिंह ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आज के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझाया। साथ ही चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय के डॉ. अरुल अराम, असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के डॉ. अभिजीत बोरा और केरल से डॉ. एचआर सुबैथा ने भी अपना व्याख्यान दिया। भारतीय विज्ञान लेखक संघ के उपाध्यक्ष तारिक बदर की अध्यक्षता में अंजन बानिक, एस श्रीना, बनानी कुंडू, आदित्य कुमार गोंड, रवीश चौहान, डॉ. विकास मिश्रा और डॉ. काव्यांजलि शुक्ला ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए। इस्कॉस के अधिशाषी सचिव डॉ. वीपी सिंह ने समापन वक्तव्य में कहा कि आने वाले समय में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हर क्षेत्र में बढ़ने वाला है और विज्ञान संचार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। संचालन अंशु अरोड़ा ने किया।

कोविड के जेएन.1 स्वरूप पर विशेषज्ञों ने कहा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जोखिम नहीं

नई दिल्ली। भारत में बुधवार को कोविड के जेएन.1 स्वरूप के 21 मामले सामने आने के मद्देनजर वैज्ञानिकों ने मौजूदा एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह देते हुए कहा है कि नए स्वरूप का उभरना ना तो हैरानी की बात है ना ही इससे घबराने की जरूरत है। तीन राज्यों में नए उप-स्वरूप के मामले आने के साथ कोविड-19 संक्रमण के 614 नए मामले सामने आए हैं, जो 21 मई के बाद एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। नए स्वरूप को लेकर कोविड के फिर से चर्चा में आने के बीच विशेषज्ञों ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है- उपलब्ध उपचार प्रभावी हैं, संक्रमण हल्का है और सभी वायरस में बदलाव होता रहता है।

वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सक और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया ने पीटीआई-भाषा से कहा, जैसा कि इन्फ्लूएंजा वायरस सहित अधिकांश श्वसन वायरस के साथ होता है, संक्रामक वायरस बदलते रहते हैं। इसलिए, सार्स कोव-2 का एक उप-स्वरूप का उभरना बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जेएन.1 के 19 मामले गोवा में और एक-एक केरल और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। पिछले दो हफ्तों में कोविड-19 से संबंधित 16 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें पीड़ित कुछ अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। मंगलवार को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जेएन.1 को मूल वंशावली बीए.2.86 से अलग वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (वीओआई) के रूप में वर्गीकृत किया। इसे पहले बीए.2.86 उपवंश के भाग के रूप में वीओआई के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक वीओआई का आशय ऐसे स्वरूप से है जिसमें आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं जो इसकी संक्रामकता, गंभीरता और टीकों से बचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, जेएन.1 द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को वर्तमान में कम माना गया है।

भारत ने भी राज्यों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के लिए सतर्क किया है। जेएन.1 के प्रसार के बारे में चिंताओं पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि सावधानियां जरूरी हैं लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विकास के दौरान वायरस का उत्परिवर्तन करना स्वाभाविक है। लहरिया ने कहा, भारत में लोग पहले ही ओमीक्रोन स्वरूप सहित विभिन्न उप-स्वरूप के संपर्क में आ चुके हैं और उन्हें कोविड-19 रोधी टीकों की कम से कम दो खुराकें मिली हैं। लहरिया ने कहा कि सार्स-कोव-2 स्वरूप या उप-स्वरूप के कारण गंभीर बीमारी होने का कोई नया जोखिम नहीं है।

तेलंगाना का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष के अंत तक 6.71 लाख करोड़ रहने का अनुमान

हैदराबाद। तेलंगाना पर चालू वित्त वर्ष (2023-24) के अंत तक 6,71,757 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज होगा। राज्य सरकार ने बुधवार को कहा कि इसमें कंपनियों या संस्थानों का गारंटी के बगैर दिया गया कर्ज भी शामिल है। वित्त वर्ष 2014-15 में राज्य पर कुल 72,658 करोड़ रुपए का कर्ज था। तेलंगाना का नवनिर्वाचित सरकार ने विधानसभा में तेलंगाना की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करते हुए बकाया कर्ज की जानकारी दी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, बजट के अंतर्गत और बजट से हटकर उधार ली गई धनराशि का ऋण चुकाने का बोझ बहुत बढ़ गया है। इसमें सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 34 प्रतिशत खर्च हो रहा है। वहीं कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर 35 प्रतिशत खर्च हो रहा है।

चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान के अनुसार, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के तहत राज्य पर कर्ज बढ़कर 3,89,673 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दस्तावेजों के अनुसार, तेलंगाना में बजटीय प्रावधान और वास्तविक व्यय में लगभग 20 प्रतिशत का अंतर है। यह फासला न केवल अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, बल्कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के व्यय की तुलना में भी अधिक है। श्वेत पत्र में कहा गया कि नई सरकार कांग्रेस की तरफ से दी गई सभी छह गारंटी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन गारंटियों पर राज्य की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया था।

विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सदस्य और पूर्व वित्त मंत्री टी हरीश राव ने श्वेत पत्र को गलतियों से भरा बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पिछली सरकार को दोषी ठहराना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने संपत्ति निर्माण पर बहुत पैसा निवेश किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राव ने जो भी कहा है, वह तथ्यात्मक रूप से गलत है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की अयोध्या के लिए पहली उड़ान 30 दिसंबर को

नई दिल्ली। एयर इंडिया एक्सप्रेस 30 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी से अयोध्या के लिए अपनी उद्घाटन उड़ान का परिचालन करेगी। एयरलाइन 16 जनवरी से इस मार्ग पर निर्धारित दैनिक सेवाएं शुरू करेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विस्तारित रनवे है जो ए-321बी-737 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले इस हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा।

Public Notice

This is to inform the general public that **Mr. Suresh Kumar Tipathi** is the sole owner of Third floor (with roof rights) left side portion built-up property no. B-197, area measuring 900 sq. ft., i.e., 83.61 sq. mtrs., out of Khasra no. 479, situated at Duggal colony Khanpur, New Delhi-110062. This ownership was legally acquired through a Sale Deed dated 16.09.2017 vide doc. No. 5509, executed by Mrs. Vinita Tripathi.

Mr. Suresh Kumar Tipathi is now the process of mortgaging the aforementioned floor with **SMFG India Home Finance Co.** Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 07-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client.

If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 7-day period by contacting **Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s):+910120-3101683 / 4562809; e-mail: accounts@lvnorth.in**

PUBLIC NOTICE

My client, Sh. Anil Yadav S/o Sh. Ranveer Singh is the owner of Property Bearing Address-65/213 Share bearing Khata no. 603 and Khasra nos. 1119 (1-02), 1124(1-02), 520 min 4(0-01), 651 min 4(0-04), 639 min 5(0-04),1120/1(0-09) and 1123/2(0-09) situated in the extended Lal Dora Abadi Deh of Village Kapashera New Delhi-110037 by virtue of release deed (blood relation without consideration) 04.07.2019 Doc. no. 5661 SR-IX Delhi executed by Sh. Ranveer Singh S/o Late Sh. Heera Lal Yadav. This above-mentioned Property is going to be mortgage with Fed Bank Financial Services Limited. Any person/bank/financial institution having any claim/right, lien any objection whatsoever in regard to above property, should notified to the undersigned /Adv. Vishal Mehan, E-713, Karkardooma Court, Delhi-110092 along with documentary evidence under address through registered A/d within 7 days from the date of publication of this notice failing which any claim, lien or objection shall be deemed to have been waived.

Adv. Vishal Mehan, E-713, Karkardooma Court, Delhi-110092; Mobile no. 9811215181

कांग्रेस, आप लोकसभा चुनाव में पंजाब में अकेले मैदान में उतरने की इच्छुक : सूत्र

नई दिल्ली (भाषा)। आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बजाय अकेले चुनावी मैदान में उतरने की इच्छुक है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। आप ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ सत्ता हासिल करते हुए 117 सीट जीती थीं और कांग्रेस केवल 18 सीट जीतने में कामयाब रही। विपक्षी खेमे के सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस भी पंजाब में आप के साथ गठबंधन के बिना लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा से संयुक्त रूप से मुकाबला करने के वास्ते जनवरी के मध्य तक लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की। वर्ष 2020 में आप ने दिल्ली की 70 सदस्ईय विधानसभा में 62 सीट जीतकर तीसरी बार सत्ता हासिल की थी। हालांकि, पार्टी प्रमुख केजरीवाल लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने कहा कि आप राष्ट्रीय राजधानी की सात लोकसभा सीट में से तीन कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार है। विपक्षी खेमे का मानना है कि कांग्रेस और आप के पास अकेले लड़ने तथा इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के बजाय एक टीम के रूप में राष्ट्रीय राजधानी में अधिक लोकसभा सीट जीतने की बेहतर संभावना है।

आरटीआई कानून के दुरुपयोग से सरकारी अधिकारियों में भय की स्थिति उत्पन्न हो रही: अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके चलते सरकारी अधिकारियों में भय और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीआई कानून सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने, प्रत्एक नागरिक की सूचना तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने, भ्रष्टाचार रोकने और सरकारों और उनके तंत्रों को जवाबदेह बनाने के प्रशंसनीय उद्देश्यों के साथ बनाया गया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, हालांकि, यह अदालत अब आरटीआई अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग को देख रही है और यह मामला सूचना के अधिकार के दुरुपयोग का एक मामला है। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सुशासन को आगे बढ़ाना है और इसका दुर्भाग्यपूर्ण दुरुपयोग केवल इसके महत्व को कम करेगा और साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अपनी गतिविधियों को करने से रोकेगा।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, यह चिकित्सकों को इसके परिणाम के भय से आपातकालीन स्थितियों में कदम उठाने से भी रोकेगा। दुर्भाग्य से इस अदालत में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें आरटीआई के दुरुपयोग के कारण सरकारी अधिकारियों में भय और जड़ता की स्थिति पैदा हो गई। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली शिशिर चंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें आयोग की रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया गया था कि जमशेदपुर के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल छाबड़ा की कथित चिकित्सकीय लापरवाही के चलते चंद के छोटे भाई की असामयिक मृत्यु के संबंध में उनके किसी भी अन्य मामले पर विचार न किया जाए।

सीआईसी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों की सूची और उसके द्वारा एक ही मुद्दे को बार-बार फिर से खोलने के लिए किए गए प्रयासों का हवाला दिया। उसने कहा कि मुद्दों पर पहले ही सभी पहलुओं से विचार किया जा चुका है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। निस्संदेह, याचिकाकर्ता डॉक्टर की डिग्री का पता लगाने के लिए बार-बार आवेदन दायर करके आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग कर रहा है, यह मुद्दा इस अदालत के साथ-साथ शीर्ष अदालत के आदेशों से पहले ही निर्णायक स्थिति तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता ने वही जानकारी नहीं बल्कि अतिरिक्त जानकारी मांगी है, और इसलिए, सीआईसी को उसी विषय पर याचिकाकर्ता के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए आयोग की केंद्रीय रजिस्ट्री को निर्देश नहीं देना चाहिए था।

कोविड के उप-स्वरूप जेएन.1 के तीन राज्यों में 21 नए मामले सामने आए: वीके पॉल

नई दिल्ली। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी. के. पॉल ने बुधवार को कहा कि देश भर में अब तक कोविड-19 के उप-स्वरूप जेएन.1 के 21 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पॉल ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय नए स्वरूप की बारीकी से जांच कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों को परीक्षण बढ़ाने और अपनी निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पॉल ने कहा कि संक्रमण की चपेट में आए लोगों में से लगभग 91 से 92 प्रतिशत लोग घर पर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, उप स्वरूप जेएन.1 के नए मामलों में से 19 मामले गोवा में दर्ज किए गए जबकि केरल तथा महाराष्ट्र में एक-एक मामला सामने आया है। बीते दो सप्ताह में कोविड-19 से संबंधित 16 मरीजों की मौत हो गई जिन्हें गंभीर सह-रुग्णताएं थी। केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और नए जेएन.1 स्वरूप के सामने आने के बीच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की और कोरोना वायरस के उभरते स्वरूपों के प्रति सतर्क रहने पर जोर दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि भले ही मामले बढ़ रहे हैं लेकिन 92.8 फीसदी मामलों में घर पर ही इलाज हो रहा है जो हल्की बीमारी का संकेत देता है। उन्होंने कहा, कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें अन्य बीमारियां थी और उनमें कोविड का पता अचानक लगा। देश में केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में दैनिक संक्रमण दर में वृद्धि देखी गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में 21 मई के बाद एक दिन में सबसे अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के 614 नए मामले दर्ज किए गए। इससे साथ ही देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या बढ़कर 2,311 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस के जेएन.1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। डब्यूएचओ ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client Ranjan Biswas is in process to purchase the Entire Upper Ground Floor without roof rights floor back side (Southern side Portion) of Property Bearing No. H-3/67 measuring 100 Sq. Yds. Out of Khasra No. 79/18 Situated in Village Palam in the abadi of Mahavir Enclave Palam, New Delhi (availing loan from Piramal Capital & Housing Finance Ltd) from Magna Chauhan, who purchased the same from Sanjay Kumar Goyal vide Sale Deed dated 18.2.2017 (Doc. No. 1005), whereas he has lost an original Sale deed dated 16.07.2013 executed by Mr. Beejali in favour of Mr. Sanjay Kumar Goyal pertain to the said property, an FIR has already been lodged for that on dated 10/10/2023

All person/s having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/registered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, bequest, partnership, possession, lease, sublease, tenancy, license, lien, charge, pledge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned. **Kamal Kant Gupta (Advocate)**

Unit No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

दलाई लामा ने अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया

भाषा। गया

तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने बुधवार को बिहार के गया जिले में तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय संघ फोरम (आईएसएफ) 2023 का उद्घाटन किया। भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में "परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना- आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षा पर एक संवादै विषय पर आज से शुरू इस तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन करते हुए दलाई लामा ने कहा, हर किसी में करुणा पैदा होनी चाहिए, चाहे वह पाली या संस्कृत परंपराओं में बौद्ध धर्म का पालन करते हों। हमें अपने और विश्व शांति के लिए बोधिसत्व की प्रथाओं का पालन करना चाहिए। मैं बोधिसत्व की प्रथाओं का पालन करता हूं और वे मेरे लिए बहुत फायदेमंद हैं।

तिब्बती धर्म गुरु ने कहा," इसी प्रकार, बोधिचित्त एक बहुत ही

अनमोल अभ्यास है जो आंतरिक शक्ति प्रदान करता है...और मैं इसका भी पालन करता हूं। बोधिचित्त के कारण बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें भी बोधिचित्त का प्रमुखता के साथ पालन करना चाहिए और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब आपके पास बोधिचित्त होता है, तो आप सहज महसूस करते हैं। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या शांत हो जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें बड़े पैमाने पर दुनिया की सेवा करनी है... हमें समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के बौद्ध परंपराओं के 2000 अनुयाई भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न बौद्ध परंपराओं के भिक्षु और विद्वान विनय नियमों के बारीक पहलुओं और 21वीं सदी में बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा शुरू करेंगे। आईएसएफ के एक बयान के अनुसार,"सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों भारत, थाईलैंड, म्यांमा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया की पाली परंपराओं के मानने वालों और संस्कृत परंपरा के तिब्बत, भूटान, नेपाल, वियतनाम, चीन, ताइवान, जापान, कोरिया, रूस, मंगोलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों के बीच संवाद और सहयोग विकसित करना है। तिब्बती धर्म गुरु 23 दिसंबर की सुबह महाबोधि स्तूप में जनता के साथ अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम के प्रतिनिधियों के साथ विश्व शांति प्रार्थना सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा वे 29, 30 और 31 दिसंबर को बोधगया के कालचक्र मैदान में धार्मिक प्रवचन देंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा की लंबी आयु के लिए एक जनवरी 2024 की सुबह कालचक्र मैदान में विशेष प्रार्थना भी की जाएगी।

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

"I, Narottam Kumar S/o Shri Trilok Chand R/o 61C, DDA Flats, Mata Sundari Road New Delhi 110002 declare that in school record wrongly mentioned name as Mayank Kaim Gautam but the correct name is Mayank Gautam for all future purposes."

PD(226)A

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी

[नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।

सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्ज़दार एवं ज़मानतदार को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति के संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार (रों)/ सह-कर्ज़दारों/ गारंटरों के नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्तियों निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	विभोर कुमार (कर्ज़दार), अनुराधा जसूजा (सह-कर्ज़दार) LBGUR00004983636	इकाई क्र. जी-68, ग्राउंड फ्लोर, स्पेज़ पलाज़ो सेक्टर 69, ग्राम फाजिलपुर, झारसा, हरियाणा गुड़गाँव-122001, क्षेत्रफल 394 वर्ग फुट	रु. 97,22,393/- (दिसंबर 08, 2023 तक)	रु. 72,00,000/- / रु. 7,20,000/-	दिसंबर 26, 2023 को दोप. 12:00 बजे से दोप. 02:00 बजे तक	जनवरी 17, 2024 को दोप. 12:00 बजे से

ऑनलाइन नीलामी हमारी ई-नीलामी संस्था **मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट **(URL Link- https://disposalhub.com)** पर संचालित होगी। बंधकदाताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **जनवरी 16, 2024** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस/ इन संरक्षित संपत्ति/यों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (सारणी ई संदर्भ) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005** में **जनवरी 16, 2024** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज, **जनवरी 16, 2024** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करें। कृपया नोट करें कि संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहने पर वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **जनवरी 16, 2024** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैडूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **दिल्ली** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।

संपत्ति अवलोकन, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** को फोन नंबर **8126013708/ 8584874809** पर संपर्क करें।

कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसियाँ **1. मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 2. ओजीओ असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड व 3. हेक्टा प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न हैं।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करें।

तिथि : दिसंबर 21, 2023
स्थान : गुड़गाँव

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया

छह जनवरी के विद्रोह मामले में कोलोराडो राज्य के उच्चतम न्यायालय ने दिया निर्णय

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के कोलोराडो राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि 2021 में अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) पर हुए हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका थी और इस कारण वह अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्य की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति प्राइमरी चुनाव से ट्रंप का नाम हटाया जाए।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप (77) को अयोग्य ठहराए जाने वाला यह फैसला संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संविधान को समर्थन देने, उसका पालन करने तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ लेने वाले अधिकारी यदि विद्रोह में शामिल होते हैं तो उन पर भविष्य में कार्यालय में शामिल होने पर रोक रहेगी।

ट्रंप अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन प्रक्रिया में सबसे आगे हैं। ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय के त्रुटिपूर्ण फैसले को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का संकल्प जताया है। कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय ने एक जिला अदालत के न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा कि ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को संसद भवन में विद्रोह को हवा दी थी लेकिन उस निष्कर्ष को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि कि रोक राष्ट्रपति चुनाव पर लागू नहीं होती।

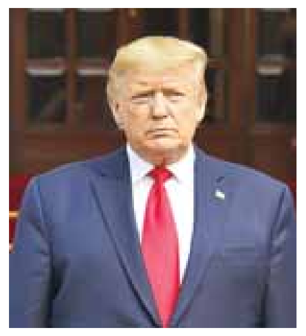

सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें पहली बार किसी अदालत ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के अयोग्य पाया है। यह निर्णय छह जनवरी 2021 को संसद परिसर पर हमले में ट्रंप की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। राज्य की अदालत ने अपने फैसले के अमल पर चार जनवरी तक रोक लगाई है इसके एक दिन बाद अर्थात पांच जनवरी को कोलोराडो के प्राइमरी चुनाव में उम्मीदवारों के नामों की पुष्टि होनी है। सात सदस्यीय कोलोराडो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला राज्य के बाहर लागू नहीं होता। ट्रंप ने छह जनवरी को संसद परिसर पर हुए हमले में कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और 14वें संशोधन के तहत किए जाने वाले मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। ट्रंप ने कोलोराडो में 14वें संशोधन और देश भर में उनके खिलाफ दर्ज इसी तरह के मुकदमों की आलोचना की है और उन्हें बेबुनियाद तथा गैर लोकतांत्रिक करार दिया है। पूर्व राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक, प्रवक्ता स्टीवन शेउंग ने एक बयान में कहा, कोलोराडो उच्चतम न्यायालय ने आज रात त्रुटिपूर्ण फैसला दिया....हमें पूरी उम्मीद है कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा और अंततः इस प्रकार के मामलों पर रोक लगेगी। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनाव प्रचार में शामिल सदस्यों ने कोलोराडो उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया। अब तक ट्रंप विभिन्न राज्यों में 14वें संशोधन से जुड़े अनेक मामलों का सामना कर चुके हैं और अब तक नौ ऐसे मामले खारिज किए जा चुके हैं।

गाजा में इजराइली हमले के बाद ध्वस्त मकानों के बीच अपना सामान खोजते फलस्तीनी

निकी हेली, विवेक रामास्वामी ने ट्रंप को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोकने वाले अदालती फैसले पर विरोध जताया

भाषा। वाशिंगटन

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल भारतीय-अमेरिकी निकी हेली और विवेक रामास्वामी ने बुधवार को अमेरिका के कोलोराडो राज्य के उच्चतम न्यायालय के उस फैसले पर विरोध जताया, जिसमें 2021 में अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) पर हुए हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के चलते उन्हें अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।

कोलोराडो राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले में ट्रंप की भूमिका थी और इस कारण वह अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्य की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति प्राइमरी चुनाव से ट्रंप का नाम हटाया जाए।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप (77) को अयोग्य ठहराए जाने वाला यह फैसला संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संविधान को समर्थन देने, उसका पालन करने तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ लेने वाले अधिकारी यदि विद्रोह में शामिल होते हैं तो उन पर भविष्य में कार्यालय में शामिल होने पर रोक रहेगी।

ट्रंप अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन प्रक्रिया में सबसे आगे हैं। ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय के त्रुटिपूर्ण फैसले को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का संकल्प जताया है।

ट्रंप मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन प्राइमरीज में ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी हेली ने कहा कि हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि न्यायाधीश ए तय करें कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में कौन शामिल हो सकता है और कौन नहीं।

हेली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रपति बनने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह देश के लिए अच्छा है।

हमास के शीर्ष नेता गाजा में युद्ध पर बातचीत के लिए काहिरा पहुंचे

दीर अल बलाह (गाजा पट्टी)। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिएह गाजा में युद्ध पर बातचीत के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गए हैं।

गाजा में 10 सप्ताह से अधिक समय से इजराइल की बमबारी और युद्ध में करीब 20,000 फलस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल ने दुनिया से हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में काली सूची में डालने का आह्वान करते हुए कहा है कि सात अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में किए गए हमले के बाद इसका नामोनिशान मिटा देना चाहिए।

हालांकि, दोनों पक्षों ने हाल में मिस्र और कतर की मध्यस्थता से अप्रत्यक्ष वार्ता फिर से शुरू की है, जिसका उद्देश्य एक और संघर्ष विराम करना और इजराइल द्वारा कैद किए गए फलस्तीनियों के बदले में उस हमले में पकड़े गए अधिक बंधकों को मुक्त कराना है। हाल के दिनों में उच्च-स्तरीय अधिकारियों की सक्रियता के बावजूद, दोनों पक्ष किसी समझौते से दूर नजर आ रहे हैं। हमास ने एक बयान में कहा कि हानिएह मिस्र के अधिकारियों के साथ युद्ध पर चर्चा करेंगे। हमास के सात अक्टूबर के हमले के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद से कतर और मिस्र ने आतंकवादी समूह और इजराइल के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माना जाता है कि हानिएह कतर में रहते हैं। हमास ने कहा कि हानिएह बुधवार को काहिरा पहुंचने के बाद मिस्र के अधिकारियों के साथ युद्ध पर चर्चा करेंगे।

इजराइल हजारों निर्माण श्रमिकों की भर्ती के लिए भारत में चलाएगा अभियान

भाषा। यरूशलम

इजराइल में निर्माण श्रमिकों की किल्लत को पूरा करने के लिए भारत से हजारों श्रमिकों की भर्ती करने की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में इजराइल के चयनकर्ताओं की एक टीम पिछले सप्ताह भारत दौरे पर गई थी और अगले सप्ताह भी एक टीम भारत रवाना होने वाली है।

इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन (आईबीए) के उप महानिदेशक और प्रवक्ता शाय पॉजनर ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, हम अगले सप्ताह 27 दिसंबर को दिल्ली और चेन्नई में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिलहाल हम सरकार की मंजूरी के अनुरूप 10,000 (श्रमिक) लाने पर विचार कर रहे हैं। निकट भविष्य में यह संख्या 30,000 तक पहुंच जाएगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है। यह एक निरंतर चलने वाला प्रयास है और इसमें कई महीने लगेंगे।

पॉज़नर ने कहा, अगले सप्ताह से शुरू होने वाली चयन प्रक्रिया 10-15 दिनों तक जारी रहेगी।

उन्होंने कहा, श्रमिकों से संबंधित मुद्दों और चयन दल का जिम्मा संभालने वाले खंड के प्रमुख इजैक गुरविट्ज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह भारत में था। वहीं अगले सप्ताह भारत रवाना होने वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई निर्माण एवं आवास मंत्रालय के महानिदेशक एहुदा मोर्गनस्टर्न करेंगे।

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान भारत से इजराइल में श्रमिकों के आगमन का समय आगे खिसकाने के बारे में चर्चा हुई थी।

पॉजनर ने पिछले महीने पीटीआई-भाषा से कहा था कि इजराइल को तत्काल अधिक श्रमिकों की जरूरत है। इजराइली निर्माण उद्योग उन विशिष्ट क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देता है जहाँ इजराइली श्रमिकों की कमी है।

पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने बुधवार को संभावित उम्मीदवारों से नामांकन पत्र स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आठ फरवरी के आम चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभावित उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने कहा कि वे सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े चार बजे तक फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और 22 दिसंबर तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। ईसीपी 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची जारी करेगा, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 24 से 30 दिसंबर तक होगी।

नए परिसीमन के बाद, संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में 336 सीट होंगी, जिनमें 266 सामान्य सीट, 60 सीट महिलाओं के लिए और 10 सीट गैर-मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगी।

इमरान खान के तीन सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना

इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आगामी आम चुनाव कम से कम तीन निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ेंगे। उनकी पार्टी ने बुधवार को यह घोषणा की। पांच अगस्त को खान को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। फैसले का मतलब था कि उन्हें पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कुछ दिन बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन वह अन्य मामलों में अभी भी जेल में हैं। वकील अली जफर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से कहा, इमरान खान बताना चाहते हैं कि वह पाकिस्तान के कम से कम तीन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जफर ने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय तोशाखाना मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली खान की याचिका पर अपना फैसला जल्द सुना सकता है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा क्योंकि (चुनाव) कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के जेएन.1 स्वरूप को वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया

भाषा। जेनेवा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस के जेएन.1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। डब्ल्यूएचओ ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य निकाय ने मंगलवार को कहा कि 2020 के अंत में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाले स्वरूपों के सामने आने से बाद से डब्ल्यूएचओ ने हल्के स्वरूप को वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तथा गंभीर स्वरूप को वैरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत करना शुरू किया है।

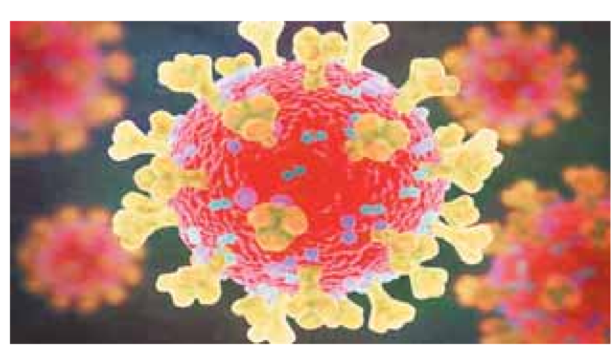

हाल में जेएन.1 स्वरूप के मामले कई देशों में सामने आए हैं और दुनिया में इस स्वरूप के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में भी इस स्वरूप का मामला सामने आया है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह अब ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा (जीआईएसएआईडी) से जुड़े बीए.2.86 वंशानुक्रम (लीनिएज) से संबंधित है।

इसने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तेजी से इसके मामले बढ़ने के कारण डब्ल्यूएचओ जेएन.1 को मूल वंश बीए.2.86 से अलग वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत कर रहा है।

भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, जेएन.1 के मामले अमेरिका, चीन, सिंगापुर और भारत में पाए गए हैं। चीन में इस स्वरूप के सात मामले सामने आए हैं।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही राज्यों से सतर्कता बरतने एवं निगरानी बढ़ाने की अपील की।

कोविड मामलों में विशेषज्ञों ने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया

सिंगापुर। पिछले कुछ सप्ताह में सिंगापुर में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने तथा एहतियात के तौर पर भीड-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओएच) के मुताबिक पिछले सप्ताह यहां 32,035 मामले दर्ज किए गए। इससे पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 56,043 था। समाचार पत्र द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, संक्रमण का सात दिनों का औसत 12 दिसंबर को 7,870 था जो 17 दिसंबर को थोड़ा कम होकर 7,730 हो गया। विशेषज्ञों ने लोगों से सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने और भीड़-भाड़ वाली बंद जगहों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है। नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (एनयूएच) के वरिष्ठ संक्रामक रोग सलाहकार प्रोफेसर डेल फिशर ने कहा, क्रिसमस पार्टियों के कारण स्थिति खराब होगी। अखबार ने मंगलवार को उनके हवाले से कहा, जब तक यह चरम पर नहीं पहुंच जाता तब तक आपको पता नहीं चलता कि यह चरम पर है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय मामलों में वृद्धि की इस अवधि के दौरान स्थिति पर नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए 19 दिसंबर से कोविड -19 संक्रमण के आंकड़ों का दैनिक अपडेट प्रदान कर रहा है।

अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की वायु सेनाओं ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास

उत्तर कोरिया ने बीते पांच महीने के भीतर पहली बार अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था

एपी। सोल

उत्तर कोरिया के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की वायु सेनाओं ने बुधवार को संयुक्त युद्धाभ्यास किया। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने बीते पांच महीने के भीतर पहली बार अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरियाई परमाणु खतरों के खिलाफ तीनों देशों की संयुक्त प्रतिक्रिया मजबूत करना था। बयान के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायु सेना के बी-1बी बम वर्षक विमानों के अलावा दक्षिण कोरिया और जापान की वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस तरह, इस साल कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर 13 वीं बार किसी अमेरिकी बम वर्षक को अस्थाई रूप से तैनात किया गया है। बी-1बी बम वर्षक विमान बड़े पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले बमवर्षक की तैनाती को अमेरिकी शत्रुता का प्रमाण बताकर इसके जवाब में मिसाइलों का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया ने सोमवार को ह्वासोंग-18 नामक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उसने कहा कि उसके इस कदम का मकसद अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टकरावसंबंधी रूख पर चेतावनी देना था।

इंग्लैंड में डॉक्टरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर तीन दिनी हड़ताल शुरू की

लंदन। इंग्लैंड में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को 72 घंटे की हड़ताल शुरू की। डॉक्टरों का वेतन के स्तर को लेकर ब्रिटिश सरकार के साथ लंबे समय से विवाद जारी है। ब्रिटेन की सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) में मरीजों से कहा गया है कि अस्तपालों में कामकाज कुछ प्रभावित होगा क्योंकि हजारों नियुक्तियां और प्रक्रियाएं स्थगित या रद्द कर दी जाएंगी। हड़ताल सुबह सात बजे शुरू हुई और यह शनिवार की सुबह तक चलेगी। डॉक्टर 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

भूकंप का संकेत मिला, लेकिन समझ नहीं पाए की किस क्षेत्र में आएगाः चीनी वैज्ञानिकों का दावा

बीजिंग। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें सोमवार रात आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से कुछ घंटे पहले इसका संकेत मिल गया था, लेकिन वे यह पता नहीं लगा पाए कि यह वास्तव में किस क्षेत्र में आएगा। एक रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई। चीन के गांसू और किंघई प्रांतों में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह पिछले नौ वर्ष में चीन में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना लगभग एक असंभव कार्य प्रतीत होता है, लेकिन चीनी प्रांत शांक्सी के अनुसंधानकर्ताओं ने एक अभूतपूर्व तकनीक विकसित करने का दावा किया है। अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि इस तकनीक की मदद से वे 7.0 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके का सफलतापूर्वक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप किस स्थान पर आएगा, इस बारे में पूर्वानुमान लगाने का इन वैज्ञानिकों के पास अभी भी कोई तरीका नहीं है। अनुसंधानकर्ताओं की टीम कम आवृत्तियों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की निगरानी करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करती है और इसके जरिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों में असामान्यताओं की तलाश करती है, जो एक चेतावनी संकेत हो सकता है।

अमेरिकी सांसदों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेसनल कॉकस बनाने की घोषणा की

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका में रिपब्लिकन सांसद पीट सेंशस और एलिस स्टेफनिक ने मंगलवार को कांग्रेसनल हिंदू कॉकस बनाने की घोषणा की ताकि इस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा की जा सके और संसद में उनके मुद्दों को उठाया जा सके। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मूल रूप से 115वीं कांग्रेस के दौरान स्थापित कॉकस ने हिंदू-अमेरिकी समुदाय और नीति-निर्माताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

सेशंस ने कहा, "कांग्रेसनल हिंदू कॉकस की शुरुआत हमारे देश की राजधानी में हिंदू-अमेरिकी समुदाय के मुद्दों को उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उनकी चिंताओं को दूर करने, उनके योगदान का जश्न मनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सरकार उनकी आवाज भी सुने।

बयान में कहा गया है कि इसमें अन्य धर्मों जैसे सिख, जैन और बौद्ध के सदस्य भी शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि सांसद सेशंस और स्टेफनिक की अध्यक्षता में कांग्रेसनल हिंदू कॉकस उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित है, जो हिंदू-अमेरिकी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं।यह समूह (कॉकस) भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रिटेन और नीदरलैंड सहित विभिन्न देशों के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है।

सांसदों के अनुसार, कांग्रेसनल हिंदू कॉकस मुक्त उद्यम, सीमित सरकार, वित्तीय अनुशासन, मजबूत पारिवारिक मूल्यों और सत्तावादी शासन के खिलाफ प्रभावी विदेश नीति की वकालत करता है। इसमें कहा गया है कि सेशंस और स्टेफनिक के अलावा, कॉकस में सांसद एंडी बिग्स जैसे सदस्य भी शामिल हैं।

राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका के मंदिरों में सप्ताहभर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे

वाशिंगटन। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्तरी अमेरिका के मंदिरों में सप्ताह भर विशेष समारोह आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इन मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल (एचएमईसी) की तेजल शाह ने पीटीआई-भाषा को बताया, यह हमारा सौभाग्य है तथा हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम इस जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हमारे सपनों का मंदिर लंबे इंतजार तथा संघर्ष के बाद आकार ले रहा है। अमेरिका और कनाडा में हर कोई इसके लिए बेहद उत्साहित है। हर कोई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एचएमईसी अमेरिका में 1,100 से अधिक हिंदू मंदिरों की सर्वोच्च संस्था है। उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका के छोटे और बड़े मंदिरों में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव 15 जनवरी से शुरू होंगे और इनका समापन अयोध्या से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधा प्रसारण दिखाने के साथ किया जाएगा। शाह ने कहा कि उत्सव को लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और उन्हें उम्मीद है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए हजारों लोग मंदिरों में पहुंचेंगे।

फिल्म निर्माताओं ने ईरान के दो फिल्म निर्देशकों के खिलाफ आरोप वापस लेने को कहा

दुबई। दुनियाभर के फिल्म निर्माताओं और फिल्म महोत्सव आयोजकों ने ईरानी अधिकारियों से ईरान के दो फिल्म निर्देशकों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने और उनकी यात्रा पर प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया है। पैन अमेरिका द्वारा जारी एक खुले पत्र में कहा गया है कि मरियम मोघदाम और बेहतास सनाइहा ने अपनी नई फिल्म माई फेवरेट केक के सिलसिले में सितंबर में पेरिस की यात्रा करने की योजना बनाई थी लेकिन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और उन्हें सूचित किया कि उनके ईरान से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पत्र पर 30 फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों फिल्म निर्देशक लगभग 70 उन ईरानी फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के कर्मचारियों में शामिल थे, जो पुट योर गन डाउन नामक एक अभियान में शामिल हुए थे।

विदेशी अनुसंधान जहाजों के अपनी सीमा में आने पर श्रीलंका ने लगाई रोक

भाषा। कोलंबो

श्रीलंका ने उसकी समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए विदेशी जहाजों को अनुमति देने पर एक साल के लिए रोक लगाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री अली सबरी ने श्रीलंकाई समुद्री सीमा में चीनी निगरानी जहाज को अनुमति देने के लिए बार बार की जा रही अपील के बीच यह घोषणा की। सबरी ने डेली मिरर अखबार से कहा कि श्रीलंका सरकार ने ए फैसला किया है और उससे संबंधित देशों को अवगत करा दिया है।

अखबार में कहा गया है कि चीन द्वारा जनवरी में श्रीलंकाई समुद्री सीमा में एक और अनुसंधानपरक जहाज के रूकने के वास्ते अनुमति मांगे जाने के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। चीन नियमित रूप से अपने अनुसंधानपरकानिगरानी जहाजों को श्रीलंका भेजता है। इस साल अगस्त में चाइना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के जंगी जहाज एचएआई यांग 24 एचएओ दो दिन की यात्रा पर आया था। चीन का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान जहाज शी यान 6 भारत की आपत्ति के बाद भी अक्टूबर में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर ठहरा था और हिंद महासागर में नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ अनुसंधान गतिविधियां की थीं।

पिछले साल अगस्त में चीनी बैलेस्टिक मिसाइल एवं सेटेलाइट निगरानी जहाज युआन यांग 5 श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पहुंचा था। भारत ने इस जहाज के वहां पहुंचने और रूकने पर कड़ा ऐतराज किया था। दरअसल भारत को इस बात की चिंता है कि इन जहाजों की उच्च प्रौद्योगिकी वाली निगरानी प्रणाली श्रीलंका जाने के रास्ते में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की चेष्टा कर सकती है।

इजराइली हमले में 17 दिन पहले पैदा हुई फलस्तीनी नवजात और उसके भाई की मौत

रफाह (गाजा पट्टी)। दक्षिणी गाजा शहर के एक अस्पताल में 17 दिन पहले जन्मी नवजात अल-अमीरा आयशा धरती पर तीन सप्ताह भी नहीं रह पाई और इजराइल-हमास युद्ध ने उसके जीवन का अंत कर दिया।

फलस्तीन में इजराइली सैन्य बलों की लगातार बमबारी के बीच, 17 दिन पहले इस बच्ची का जन्म जिस अस्पताल में हुआ, वहां बिजली भी नहीं थी।

नवजात का नाम उसके परिवार ने बड़े उत्साह से अल-अमीरा आयशा रखा था जिसका अर्थ होता है राजकुमारी आयशा। लेकिन मंगलवार को इजराइली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई। हमले में नवजात का घर पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसका भाई भी मारा गया। नवजात की दादी और हमले जीवित बची सुजैन जोराब ने बताया कि मंगलवार को सुबह होने से पहले रफाह में जब उनके अपार्टमेंट पर हमला हुआ तब उनका पूरा परिवार सो रहा था।

निर्णायक तीसरे वनडे में भारत को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

भाषा । पार्ल (दक्षिण अफ्रीका)

पहले दोनों मैचों में शुरूआती जोड़ी की नाकामी के बाद भारतीय टीम बृहस्पतिवार को तीसरे और आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज करने के लिए अच्छी शुरूआत की कोशिश में होगी।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे श्रृंखला में सिर्फ एक बार ही हराया है। उसे दोहराने के लिए भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज रूतुराज गायकवाड़ और बी साइ सुदर्शन से अच्छे प्रदर्शन की जरूरत होगी। साइ सुदर्शन ने पहले दोनों मैचों में 55 और 62 रन बनाए। वहीं गायकवाड़ ने पांच और चार रन ही बनाए। पहले मैच में भारतीय सलामी जोड़ी 23 और दूसरे में चार रन की साझेदारी ही कर सकी।

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज टोनी डि जोर्जी ने पहला शतक बनाया और रीजा हेंड्रिक्स ने 130 रन की पारी खेली।

भारत के तिलक वर्मा अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखला के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी नाकाम रहे। गायकवाड़ और वर्मा को अपनी चिर परिचित लय हासिल करनी होगी क्योकि मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर नहीं हैं। वैसे वर्मा की जगह 30 वर्ष के रजत पाटीदार को चौथे नंबर पर उतारा जा सकता है। अय्यर पहले वनडे के बाद ही टेस्ट श्रृंखला की तैयारी में जुट गए। शीर्षक्रम के बल्लेबाजों के लिए राहत की बात यह है कि बोलैंड पार्क की पिच बल्लेबाजों की मददगार है।

गक्बेरहा की पिच में असमान उछाल था लेकिन अगला मैच पार्ल में खेला जाएगा जहां पिच से बेहतर उछाल मिलेगी। इससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने में मदद मिलेगी।

टीम प्रबंधन संजू सैमसन को एक और मौका दे सकता है जो पिछले मैच में 12 रन पर आउट हो गए।

गेंदबाजी में मुकेश कुमार दो मैचों में एक भी विकेट नहीं ले सके। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज टोनी डि जोर्जी ने उनकी गेंदों की जमकर धुनाई की। अर्शदीप सिंह और आवेश खान पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे और अर्शदीप ने दूसरे मैच में भी लय कायम रखी। टीम प्रबंधन अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को भी मौका दे सकता है। उन्होंने हरियाणा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में टीम प्रबंधन को कुलदीप यादव या अक्षर पटेल में से एक को बाहर रखकर चहल के लिए जगह बनानी होगी। कुलदीप और अक्षर टेस्ट टीम का हिस्सा हैं ऐसे में दोनों अधिकतम मैच अभ्यास चाहेंगे। दक्षिण अफ्रीकी टीम डि जोर्जी के प्रदर्शन से उत्साहित है और लगता है कि उन्हें क्विंटन डिकॉक का विकल्प मिल गया है। तेज गेंदबाज नांद्रे बरगर ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया है।

टीमें : भारत: लोकेश राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़, बी साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, अवेश खान, रिंकू सिंह, आकाश दीप, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), नांद्रे बरगर, टोनी डि जोर्जी, रीजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, मिहलाली मपोंगवाना, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, तबरेज शम्सी, रासी वैन डेर डुसेन, काइल वेरिन, लिजाद विलियम्स और ब्यूरान हेंड्रिक्स।

मैच भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे शुरू होगा।

स्पिनरों के भरोसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट जीत पर भारत की नजरें

भाषा । मुंबई

इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय महिला टीम बृहस्पतिवार से आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट में आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम पर जीत दर्ज करके अपनी उपलब्धियों में इजाफा करना चाहेगी।

भारत ने 46 साल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले दस टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम को पता है कि स्पिनरों की मददगार पिच पर उसके पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता।

भारतीय गेंदबाजों खासकर आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने पिछले सप्ताह डी वाई पाटिल स्टेडियम पर इंग्लैंड के खिलाफ 347 रन से मिली जीत में अहम भूमिका निभाई। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से यह सबसे बड़ी जीत थी। अब दीप्ति आस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगी।

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने भी नई गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है। तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर ने भी इंग्लैंड के खिलाफ तीन विकेट लिए। बल्लेबाजी में हरमनप्रीत कौर (49 और नाबाद 44), जेमिमा रौड्रिग्ज (68) और यास्तिका भाटिया (66) ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रभावित किया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से भारत को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। बाएं हाथ की बल्लेबाज शुभा सतीश इस मैच में शायद नहीं खेल सकेंगी जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान हेयरलाइन फ्रेक्चर हो गया था। पूजा पूनिया कवर के तौर पर भारतीय टीम से जुड़ी है लेकिन हरलीन देयोल को मौका मिल सकता है जिन्होंने नेट पर काफी देर अभ्यास किया।

करीब 40 साल बाद भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने आई आस्ट्रेलियाई टीम के पास एलिसा हीली के रूप में नई कप्तान हैं। मेग लानिंग की जगह कप्तान बनी हीली के लिए भारत में टेस्ट जीतना बड़ी चुनौती होगी। भारत और आस्ट्रेलिया की महिला टीमों ने फरवरी 1984 में इसी मैदान पर भारत में आखिरी बार टेस्ट खेला था। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दो साल पहले आस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट में स्मृति मंधाना के पहली पारी में बनाए गए 127 रन की मदद से मैच ड्रॉ रहा था।

भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, जेमिमा रौड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, यास्तिका भाटिया, रिचा घोष, स्नेह राणा, शुभा सतीश, हरलीन देयोल, साइका इशाक, रेणुका सिंह ठाकुर, टिटास साधू, मेघना सिंह, राजेश्वरी गायकवाड, पूजा वस्त्राकर।

आस्ट्रेलिया : एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, लौरेन चीटल, हीथर ग्राहम, एशले गार्डनर, किम गार्थ, जेस जोनासेन, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, बेथ मूनी, एलिसा पेरी, मेगान शट, अनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम।

मैच का समय : सुबह 9 . 30 से।

वीटा दानी आईटीटीएफ संचालन समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय

नई दिल्ली। खेल परोपकार से जुड़ी उद्यमी वीटा दानी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) में संचालन समिति की सदस्य के रूप मे शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी। इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई। अल्टीमेट टेबल टेनिस की अध्यक्ष के तौर पर वीटा इस खेल को बढ़ावा दे रही है। इस टूर्नामेंट का आयोजन देश के के 25 राज्यो मे हो रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार वीटा ने कहा, मै इस सम्मान के लिए आईटीटीएफ संस्थान को शुक्रिया करना चाहूंगी। यह टेबल टेनिस को बढ़ावा देने की मेरी दृष्टिकोण के मुताबिक है। टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसे कोई भी खेल सकता है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और हमारा उद्देश्य उस संदेश को फैलाना और खेल को सभी के लिए सुलभ बनाना है।

प्रणवी संयुक्त 11वें स्थान पर, चार भारतीयों ने कट हासिल किया

मराकेश (मोरक्को)। प्रणवी उर्स सहित चार भारतीय महिला गोल्फर बुधवार को यहां क्वालीफाइंग स्कूल गोल्फ टूर्नामेंट के पांच दिवसीय अंतिम चरण के चौथे दौर के बाद 2024 के लिए लेडीज यूरोपीय टूर पर पूर्ण कार्ड हासिल करने की दौड़ मे बनी हुई है। प्रणवी 74 का कार्ड खेलकर संयुक्त रूप से 11वे स्थान पर है। उनके अलावा कट हासिल करने वाली नेहा त्रिपाठी संयुक्त 36वे, वाणी कपूर संयुक्त 46वे और अमनदीप द्राल संयुक्त 56वे स्थान पर मौजूद है। शीर्ष 65 और संयुक्त रूप से रहने वाली गोल्फर ही पांचवे और अंतिम दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी जिससे आठ भारतीय कट हासिल करने से चूक गई। कट चूकने वाली भारतीय गोल्फर रिद्धिमा दिलावड़ी, अवनी प्रशांत, त्वेसा मलिक, जैसमीन शेखर, स्नेहा सिंह, सहर अटवाल, अनन्या दतार और दुर्गा निटूर है।

पंजाब किंग्स ने कहा, आईपीएल नीलामी में सही खिलाड़ी चुना

नई दिल्ली। पंजाब किंग्स ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया कि दुबई मे आईपीएल नीलामी के दौरान उन्होने सही क्रिकेटर को अपने साथ जोड़ा है जबकि इस तरह की खबरे थी कि नाम मे भ्रम के कारण उन्होने गलत खिलाड़ी के लिए बोली लगा दी। मंगलवार को शशांक सिंह को नीलामी के अंतिम लम्हो मे खरीदा गया जब विभिन्न फ्रेंचाइजी अनकैप्ड (जिन खिलाड़ियो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नही खेला हो) भारतीय खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए के उनके आधार मूल्य पर खरीदने का प्रयास कर रही थी। नीलामी की संचालनकर्ता ने जब शशांक के नाम की घोषणा की तो पंजाब किंग्स की सह मालिक प्रीति जिंटा ने तुरंत ही बोली लगा दी और यह क्रिकेटर बिक गया। खबरों के अनुसार फ्रेंचाइजी ने बाद मे महसूस किया कि उन्होने गलती कर दी है और उन्होने बोली वापस लेने के लिए नीलामी संचालनकर्ता से संपर्क किया। अपने स्पष्टीकरण मे पंजाब किंग्स ने कहा, मीडिया ने शशांक सिंह के बारे मे लिखा है कि पंजाब किंग्स ने उन्हे गलती से खरीद लिया। पंजाब किंग्स स्पष्ट करना चाहते है यह खिलाड़ी हमेशा उन खिलाड़ियों की सूची मे शामिल था जिन पर हमे बोली लगानी थी। उन्होने कहा, भ्रम इसलिए था क्योकि सूची मे एक ही नाम के दो खिलाड़ी थे। हमे उसे अपने साथ जोड़ने की खुशी है और उसे हमारी सफलता मे योगदान देते हुए देखते है। पंजाब किंग्स के एक अधिकारी ने पीटीआई से बुधवार को कहा कि सही खिलाड़ी चुना गया है और फ्रेंचाइजी की पिछले कुछ समय से उन पर नजरे थी। अधिकारी ने कहा, हमने सही खिलाड़ी को चुना है। पिछले कुछ समय से हम उस पर नजर रखे हुए थे। वह छत्तीसगढ़ का 32 साल का खिलाड़ी है जो 2022 सत्र मे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था।

शुभमन को हटा बाबर फिर से वनडे में शीर्ष रैंकिंग बल्लेबाज बने

भाषा । दुबई

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कम समय तक ही रह पाए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर बुधवार को जारी एकदिवसीय रैंकिंग में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने उन्हें पहले स्थान से हटा दिया। शुभमन ने पिछले महीने वनडे विश्व कप के दौरान रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। उन्होंने हालांकि विश्व कप के बाद कोई एकदिवसीय मैच नहीं खेला है।

बाबर 824 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पहुंच गए जबकि शुभमन (810) दूसरे स्थान पर हैं। इस रैंकिंग में उनके बाद भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं।

श्रेयस अय्यर 12वें स्थान पर खिसक गए हैं जबकि लोकेश राहुल एक स्थान के सुधार के साथ 16वें पायदान पर आ गए हैं। गेंदबाजों की सूची में दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड दूसरे और भारत के मोहम्मद सिराज तीसरे स्थान पर है।

शीर्ष 10 में जसप्रीत बुमराह (पांचवें) और कुलदीप यादव (आठवें) अन्य भारतीय है। मोहम्मद शमी 11वें तो वहीं रविंद्र जडेजा 22वें स्थान पर है। हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। शीर्ष 20 में जडेजा (12वें) और हार्दिक पंड्या (17वें) के रूप में दो ही भारतीय हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय में सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर बरकरार हैं।

गेंदबाजों में इंग्लैंड के आदिल राशिद शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले ग्रीम स्वान इस प्रारूप में इंग्लैंड के शीर्ष तेज गेंदबाज बने थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला के चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सात विकेट लेकर उन्होंने अफगानिस्तान के राशिद खान को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। भारत के रवि बिश्नोई इस सूची में तीसरे स्थान पर है। हरफनमौला खिलाड़ियों में शाकिब की बादशाहत बरकरार है जबकि हार्दिक चौथे स्थान के साथ शीर्ष भारतीय है। टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के जो रूट (दूसरे) और स्टीव स्मिथ (तीसरे) उनके बाद है।

इस रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित 10वें स्थान के साथ देश के शीर्ष खिलाड़ी है।

टेस्ट गेंदबाजों की सूची में अनुभवी भारतीय रविचंद्रन अश्विन पहले स्थान पर है जबकि दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाड़ा दूसरे पायदान पर है।

पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में दमदार गेंदबाजी के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस तीसरे स्थान पर पहुंच गए जबकि रविंद्र जडेजा चौथे पायदान पर खिसक गए।

बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने सात विकेट से हराया

एपी । नेलसन (न्यूजीलैंड)

हेनरी निकोल्स (95) और विल यंग (89) शतक लगाने से चूक गए लेकिन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी से न्यूजीलैंड ने दूसरे एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है।

बांग्लादेश ने सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार की 169 रन की पारी से पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 49.5 ओवर में 291 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 46.2 ओवर में तीन विकेट पर 296 रन बना कर जीत दर्ज की। श्रृंखला के शुरुआती मैच में 105 रन बनाने वाले यंग ने मंगलवार को रचिन रविंद्र (33 गेंद में 45 रन) के साथ पहले विकट के लिए 76 रन की साझेदारी कर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। उन्होंने 94 गेंद की पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए।

निकोल्स श्रृंखला के पहले मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे थे। उन्होंने 99 गेंद की पारी में आठ चौका और एक छक्का लगाया।

इन दोनों के आउट होने के बाद कप्तान टॉम लैथम (34) और टॉम ब्लंडेल (24) ने 22 गेंद शेष रहते न्यूजीलैंड को सात विकेट की आसान जीत दिला दी। इससे पहले सरकार ने 151 गेंद में 169 रन की पारी खेल टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। वह लिटन दास (174 रन) इस प्रारूप में बांग्लादेश के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। पारी का आगाज करने वाले इस बल्लेबाज ने 22 चौके और दो छक्के लगाए। वह 49वें ओवर में आउट हुए।

साल्ट के दूसरे टी20 शतक से इंग्लैंड ने श्रृंखला में बराबरी की

सेन फर्नांडो (त्रिनिदाद)। विश्व चैम्पियन इंग्लैंड ने चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 75 रन से हराकर श्रृंखला में बराबरी की।

सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के लगातार दूसरे शतक के दम पर इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 267 रन बनाए। साल्ट और बटलर ने 9 . 5 ओवर में 117 रन जोड़े। बटलर 29 गेंद में 55 रन बनाकर आउट हुए। साल्ट ने 119 रन बनाए जो टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है। इसमें 10 छक्के और सात चौके शामिल थे। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 16वें ओवर में 192 रन पर आउट हो गई। ब्रेंडन किंग खाता भी नहीं खोल सके और रीसे टॉपले की गेंद पर मोईन अली को कैच दे बैठे। निकोलस पूरन 15 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज का स्कोर सातवें ओवर में 100 रन पर चार विकेट था। पांचवां और आखिरी मैच बृहस्पतिवार को खेला जाएगा।

एफ आईएच पुरस्कार कड़ी मेहनत और दृढ़ता का नतीजा : हार्दिक

भाषा । नई दिल्ली

भारतीय पुरूष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह ने बुधवार को कहा कि एफआईएच वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत और दृढता का नतीजा है जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इतने साल से उन्होंने दिखाई है।

मनप्रीत सिंह (2019) और हरमनप्रीत सिंह (2020 .21 और 2021 .22) के बाद यह पुरस्कार पाने वाले हार्दिक भारत के तीसरे पुरूष खिलाड़ी बन गए। वहीं महिला टीम की कप्तान सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार एफआईएच वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। हार्दिक ने कहा , यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाना सम्मान की बात है। मैं अपने साथी खिलाड़ियों, कोचों और समर्थकों का शुक्रगुजार हूं जो मेरी सफलता के स्तंभ रहे। इससे लगातार अच्छे प्रदर्शन की मेरी ललक और बढ़ी है। उन्होंने कहा , इस सफर में कई चुनौतियां और सबक मिले। इससे यह विश्वास भी पक्का हो गया कि कड़ी मेहनत, दृढता और सहयोगी टीम के साथ होने से बड़ी उपलब्धियां अर्जित की जा सकती है।

हार्दिक ने 2022 में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता था। अब तक 114 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके 25 वर्ष के हार्दिक तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। इसके अलावा वह इस साल एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी और एशियाई खेल चैम्पियन टीम के भी सदस्य रहे।

फ्रांस को 5-4 से हराकर भारत ने पांच देशों की टूर्नामेंट में दर्ज की सांत्वना जीत

वेलेंसिया (स्पेन)। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जुगराज सिंह के दो-दो गोल से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पांच देशों की टूर्नामेंट के अपने चौथे और आखिरी मैच मे बुधवार को यहां फ्रांस

को 5-4 से हराकर सांत्वना जीत दर्ज की। मुकाबले मे विवेक सागर प्रसाद (16वां मिनट) ने भारत के लिए पहला गोल किया। जुगराज ने 20वे और 60वे मिनट जबकि हरमनप्रीत ने 25वे और 56वे मिनट मे टीम के लिए गोल दागे। विश्व रैंकिंग मे तीसरे स्थान पर काबिज भारतीय टीम का इस टूर्नामेंट मे प्रदर्शन काफी खराब रहा। टीम को शुरुआती तीनो मैच मे स्पेन (0-1), बेल्जियम (2-7) और जर्मनी (2-3) से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को टूर्नामेंट की कम रैंकिंग की टीम फ्रांस (विश्व रैंकिंग मे नौवे स्थान पर काबिज) ने भी कड़ी टक्कर दी। लुकास मोंटेकोट ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल मे बदलकर मैच के 11वे मिनट मे फ्रांस को बढ़त दिला दी। भारत ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत मे ही विवेक के मैदानी गोल से बराबरी कर ली। इसके बाद जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल मे बदलकर भारत को बढ़त दिला दी जबकि हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर के जरिए इस बढ़त को दोगुनी कर दी। फ्रांस को इसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक मिला और एटिने टाइनेवेज (28वे) ने बिना कोई गलती किए इसे गोल मे बदल दिया। मध्यांतर के समय भारतीय टीम 3-2 से आगे थी। फ्रांस ने तीसरे क्वार्टर के आखिर मे गैसपार्ड बॉमगार्टन (43वे मिनट) के मैदानी गोल से 3-3 की बराबरी हासिल कर ली। मैच के आखिरी क्वार्टर मे दोनो टीमो ने बढ़त लेने के लिए एक-दूसरे की रक्षा पंक्ति मे सेंध लगाने की कोशिश की। टाइनेवेज ने मैच के 53वे मिनट मे मिले पेनल्टी कॉर्नर पर अपने दूसरे के साथ फ्रांस को 4-3 से आगे कर दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने हालांकि तीन मिनट के बाद पेनल्टी कॉर्नर को गोल मे बदल कर स्कोर बराबर कर टीम पर दबाव हावी नही होने दिया। मैच के आखिरी मिनट मे जुगराज ने एक और पेनल्टी को गोल मे बदल कर भारतीय को 5-4 से आगे कर दिया।

रमिता जिंदल महिला 10 मीटर एयर राइफल के ट्रायल में लगातार दूसरे दिन शीर्ष पर रही

नई दिल्ली। एशियाई खेलो की कांस्य पदक विजेता निशानेबाज रमिता जिंदल बुधवार को यहां कर्णी सिंह परिसर मे महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल ट्रायल मे लगातार दूसरे दिन शीर्ष स्थान पर रही। ट्रायल एक मे शीर्ष स्थान हासिल करने वाली हरियाणा की रमिता ने ट्रायल दो मे लय जारी रखते हुए आठ खिलाड़ियों के फाइनल मे 252 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। तमिलनाडु की आर नर्मदा नितिन उनसे 0.9 अंक पीछे दूसरे स्थान पर रही। ट्रायल एक मे दूसरे स्थान पर रहने वाली हरियाणा की नैन्सी इसमे तीसरे स्थान पर रही। इससे पहले क्वालिफिकेशन चरण मे महाराष्ट्र की सोनम उत्तम मस्कर 634.5 अंको के साथ तालिका मे शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि नैन्सी 0.5 अंक पीछे दूसरे स्थान पर और रमिता 631.8 अंको के साथ तीसरे स्थान पर थी। पेरिस ओलंपिक कोटा विजेता अखिल श्योराण ने पुरुषो की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन ट्रायल दो के फाइनल मे 465.2 के स्कोर के साथ जीत हासिल की। ट्रायल एक के विजेता रेलवे के स्वप्निल कुसाले दूसरे स्थान पर रहे जबकि सेना के अनुभवी चैन सिंह तीसरे स्थान पर रहे। स्वप्निल ने भी पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान सुनिश्चित किया है। अखिल ने क्वालिफिकेशन चरण मे भी 592 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल ट्रायल एक मे हरियाणा की रिदम सांगवान ने फाइनल मे ओलंपियन मनु भाकर को 38-37 से हराया। मनु ने हालांकि क्वालिफिकेशन चरण मे काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। वह 589 का स्कोर बनाकर शीर्ष स्थान पर थी जबकि रिदम ने 580 का स्कोर बनाकर तीसरे स्थान के साथ फाइनल मे जगह बनाई थी।

केकेआर गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ और एक्स फैक्टर होंगे स्टार्क : गंभीर

भाषा । नई दिल्ली

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मेंटोर गौतम गंभीर ने मिचेल स्टार्क के लिए अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा रिकॉर्ड बोली लगाने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि यह आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एक्स फैक्टर और गेंदबाजी आक्रमण का अगुआ होगा। केकेआर ने दुबई में मंगलवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी में स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि में खरीदा।

फ्रेंचाइजी के मेंटोर (मार्गदर्शक) गंभीर भी नीलामी में मौजूद थे, उन्होंने कहा, स्टार्क एक एक्स फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा खिलाड़ी जो नई गेंद से गेंदबाजी कर सकता है, डेथ ओवरों (अंतिम ओवरों) में गेंदबाजी कर सकता है और सबसे अहम बात है कि वह गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई भी कर सकता है।

उन्होंने कहा, वह हमारे दो घरेलू गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार भी साबित होगा क्योंकि हमारे दोनों गेंदबाज काफी प्रतिभाशाली हैं और मैदान पर उनकी मदद के लिए आपको किसी की जरूरत है और स्टार्क इन सभी भूमिकाओं में खरे उतरेंगे। गंभीर ने जियो सिनेमा से कहा, वह अपनी गेंदबाजी के लिए नहीं बल्कि गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई के लिए भी अहम होंगे जो अन्य सभी गेंदबाजों की मदद करेंगे। इसलिए किसी को तो इसके लिए भुगतान करना ही होगा।

केकेआर को अपनी कप्तानी में दो आईपीएल खिताब दिला चुके गंभीर ने कहा कि उनकी नजर में मजबूत बल्लेबाजी लाइन अप के बजाय मजबूत गेंदबाजी लाइन अप ज्यादा अहमियत रखता है।

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कहा, हमारे गेंदबाजी लाइन अप में काफी गहराई है। हम हमेशा मजबूत गेंदबाजी आक्रमण चाहते थे और अब हमारे पास मुजीबुर रहमान, गुस एटकिन्सन, सुनील नारायण, वरूण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क के साथ होने से काफी विकल्प हैं और हमारे पास दो भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा और सुयश शर्मा के अलावा चेतन सकारिया भी हैं।

उन्होंने कहा, हमारे पास अब काफी विकल्प हैं जिसमें हम स्टेडियम को देखकर विभिन्न संयोजन उतार सकते हैं। मैं हमेशा मजबूत बल्लेबाजी लाइन अप के बजाय मजबूत गेंदबाजी लाइन अप को तरजीह देता हूं।

भाजपा सांसद से जब उस फ्रेंचाइजी में वापस आने के बारे में पूछा गया जिसे वह 2012 और 2014 में खिताब दिला चुके हैं तो उन्होंने कहा, मेरे लिए केकेआर एक टीम नहीं बल्कि भावना है। इसके पीछे कारण है कि मुझे सात साल तक कोलकाता के लोगों से अथाह प्यार मिला है और उम्मीद करता हूं कि हम वैसी ही यादें बना पाएं जो हमने 2012 और 2014 में बनाई थीं। कोई गारंटी नहीं है कि हम जीत जाएं लेकिन एक गारंटी तो बिलकुल है कि हम डटे रहेंगे।

राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप में ध्रुव-तनीषा की जोड़ी जीती

गुवाहाटी। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की मिश्रित युगल जोड़ी ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए बुधवार को यहां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप के शुरूआती दिन वी जोसफ और लाडिंगपुल राल्टे की जोड़ी को 21-5, 21-7 से हराया।

हाल में ओडिशा मास्टर्स खिताब जीतने वाली कपिला-क्रास्टो की जोड़ी का सामना अब अब्दुल रहमान सैयद और मामाइक्या लंका से होगा।

पुरुष एकल में विश्व जूनियर चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता आयुश शेट्टी पहले दौर में अधीप गुप्ता को 43 मिनट में 22-20, 21-17 से पराजित करने में सफल रहे। अगले दौर में उनकी भिड़ंत नीर नेहवाल से होगी जिन्होंने वी जोसफ को 21-9, 21-13 से हराया।

समीर वर्मा ने आदित्य मंडल को 31 मिनट में 21-11, 21-13 से शिकस्त दी और अगले दौर में मेराबा मेसनाम लुवांग के सामने होंगे। अंडर-19 खिलाड़ी ध्रुव नेगी को प्रेम सिंह चौहान को 21-7, 21-11 से हराने में महज 21 मिनट लगे। अब राउंड 64 में उनका सामना ओरिजीत चालिहा से होगा।

संजय सिंह को डब्ल्यूएफआई का चुनाव जीतने का भरोसा

भाषा । नई दिल्ली

निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विश्वासपात्र संजय सिंह ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफ) के बहुप्रतीक्षित चुनावों में जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि कुश्ती जगत को पता है कि कौन खेल के लिए फायदेमंद होगा और कौन इसे नुकसान पहुंचाएगा।

उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह का अध्यक्ष पद के लिए सामना राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनिता श्योराण से होगा। अनिता को देश के शीर्ष पहलवानों का समर्थन हासिल है जिन्होंने बृजभूषण पर अपने कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों के कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

सूत्रों की माने तो बृजभूषण के समर्थन वाले संजय सिंह के पैनल को 50 सदस्ईय निर्वाचक मंडल में से कम से कम 41 का समर्थन हासिल है।

माना जा रहा है कि असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के अलावा अन्य राज्य संघ संजय सिंह के पैनल के समर्थन में मतदान करेंगे।

संजय सिंह ने पीटीआई से कहा, पूरे कुश्ती जगत को पता है कि किसने खेल की बेहतरी के लिए काम किया और किसने इसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। डब्ल्यूएफआई का पिछले 11 साल में किया गया काम सबूत है कि कुश्ती के खेल ने भारत में अच्छी प्रगति की है। लोग जब वोट देंगे तो उनके दिमाग में यह बात होगी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक तथा विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट ने जंतर-मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की अगुआई की थी।

इन्हें वादा किया गया था कि बृजभूषण के परिवार के किसी सदस्य या सहयोगी को चुनाव लड़ने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी कारण बृजभूषण का बेटा प्रतीक और दामाद विशाल सिंह चुनाव में नहीं उतरे।

संजय सिंह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण के करीबी हैं लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनके नामांकन को स्वीकृति दे दी।

निर्वाचक मंडल के एक सदस्य ने कहा, बृजभूषण की क्षमता पर काफी भरोसा है कि उन्होंने खेल के स्तर में सुधार के लिए अच्छा काम किया है। उनके नेतृत्व में महासंघ की वित्तीय हालत में भी काफी सुधार हुआ। यही कारण है कि उन्हें अब भी कुश्ती जगत का समर्थन हासिल है।

अध्यक्ष के पद के अलावा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, दो संयुक्त सचिव और कार्यकारी परिषद के पांच सदस्यों के लिए भी चुनाव होंगे।

जुलाई में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया में अदालत में चलने वाले मामलों के कारण लगातार विलंब हुआ। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महासंघ यूनाईटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी निर्धारित समय में चुनाव नहीं कराने के कारण डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया। उच्चमतम न्यायालय ने हाल में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चुनावों पर लगाई रोक को खारिज कर दिया जिससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हुआ।

उच्चतम न्यायालय के चुनाव का रास्ता साफ करने के बाद निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमएम कुमार ने चुनाव की तारीख घोषित की।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879900।